छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **पंचम सत्र**

गुरुवार, दिनांक 27 फरवरी, 2025

(फाल्गुन 08, शक सम्वत् 1946)

[अंक 03]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

सोमवार, दिनांक 27 फरवरी 2025

(फाल्गुन 8, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वान्ह 11.00 बजे समवेत् हुई.

{अध्यक्ष महोदय, (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुये}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बजट में सम्मिलित सड़क/पुल-पुलिया

[लोक निर्माण]

1. (*क्र. 439)श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में कितने सड़क निर्माण, पुल पुलिया निर्माण को बजट में सम्मिलित किया गया था? कार्य का नाम बजट राशि सहित बतावें? **(ख)** उक्त कार्यो में से कितने कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई? कितने निर्माण प्रारंभ हुए? कितने प्रगतिरत हैं? कार्य का नाम स्वीकृति राशि सहित जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) एवं **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र**[1] अनुसार है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल । श्रीमती शेषराज हरवंश ।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी से है, विभाग के द्वारा प्रश्न का उत्तर तो माननीय मंत्री जी के द्वारा बहुत सही दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि वर्ष 2022-2023 में प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त सड़क कार्य शिवरीनारायण से खेड़ताल की लंबाई 11.75 किलोमीटर की मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण के लिये स्वीकृत किया गया था, जिसे प्रशासकीय स्वीकृति 18.75 करोड़ की हो गई थी । अध्यक्ष महोदय, इसमें निविदा भी लगाई गई थी, जिसे स्थगित किया गया है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि इसे स्थगित करने के क्या कारण हैं और इसमें स्वीकृति कब प्रदान करेंगे ?

---

[1] परिशिष्ट "एक"

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पामगढ़ विधान सभा में वर्ष 2022-2023 में सड़क के बजट में 4 काम प्रावधानित थे, 3 पुल के काम थे । 3 सड़कों के कामों की प्रशासकीय स्वीकृति मिली, उसमें से 2 कार्य पूर्ण हो चुके हैं । तीसरे कामों का शिवरीनारायण खेड़ताल मार्ग 11.57 किलोमीटर के मजबूतीकरण और चौड़ीकरण का उल्लेख, जैसा कि अभी माननीय सदस्या ने किया है । अध्यक्ष महोदय, इस काम का पुर्नपरीक्षण किया जा रहा है और परीक्षण उपरान्त आगे की कार्यवाही की जायेगी । अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023-2024 में 9 सड़क बजट में प्रावधानित थे और 4 पुल के काम थे, उसमें से 1 काम पूर्ण हुये हैं और वर्ष 2024-2025 में 26 कामों की प्रशासकीय स्वीकृति की प्रक्रिया बजट में सम्मिलित है, जिसका प्राक्कलन तैयार कर आगे की कार्यवाही की जा रही है ।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर में यह भी बताया गया है कि वर्ष 2022-2023 की एक तथा वर्ष 2023-2024 के बजट में सम्मिलित 7 सड़कें हेतु प्रशासकीय स्वीकृति के लिये पत्र वर्ष 2023 में प्रेषित की गई है । अध्यक्ष महोदय, 2 वर्ष के अधिक समय के बाद भी प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि यह प्रशासकीय स्वीकृति क्यों अपेक्षित है ?

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, प्राक्कलन आदि की कार्यवाही की जा रही है, बजट की उपलब्धता के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर, उन सड़कों पर आगे की कार्यवाही होगी ।

अध्यक्ष महोदय :- चातुरी जी, आप एक प्रश्न पूछ लीजिए ?

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप ला सबसे पहली प्रणाम करथंव । मैं हा माननीय मंत्री जी से पूछना चाहथंव कि मोर क्षेत्र के मात्र दू ठन सड़क ला प्रशासकीय स्वीकृति मिले हे, बाकी सड़क ला कब स्वीकृति मिलही, कृपया बताय के कष्ट करें ?

अध्यक्ष महोदय :- बोलना चाहे त ठीक हे, संदर्भ नई हे ।

श्रीमती शेषराज हरवंश :-अध्यक्ष महोदय, सड़कों के काम प्राथमिकता से किये जा रहे हैं, प्राथमिकता के आधार पर प्राक्कलन तैयार करके प्रशासकीय स्वीकृति की प्रक्रिया की जा रही है ।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में एक सेकण्ड ।

अध्यक्ष महोदय :- ऐसा नहीं होता ।

श्री दिलीप लहरिया :- इसी में सर । अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है, मान लीजिए वर्ष 2023-2024 का आपने...।

अध्यक्ष महोदय :- मान लीजिए, ऐसा प्रश्न विधान सभा में नहीं होता है । आप सीधा पूछिये कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मान लीजिए क्या है ?

श्री दिलीप लहरिया :- अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024-2025 का जो आ चुका है, वह कब तक होगा ? आप लोगों का बिल्हा, तखतपुर ...।

अध्यक्ष महोदय :- पूरे प्रदेश का संदर्भ हो चुका है ...।

श्री दिलीप लहरिया :- सब जगह हो चुका है, बिलासपुर जिले में हमारा क्यों रोका गया है सर ? मैं यह निवेदन करना चाहूँगा ।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी से संबंधित है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न कर लीजिएगा, अभी बहुत समय है । गोमती साय जी ।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न है, मार्च आ चुका हैं, मार्च ऐंडिंग है । हमारा कब होगा, भारतीय जनता पार्टी के जहां विधायक हैं, वहां हो चुका है ?

अध्यक्ष महोदय :- जब लोक निर्माण विभाग की चर्चा आयेगी तो अपने-अपने क्षेत्र के या राज्यपाल के अभिभाषण में अपनी बात को रख सकते हैं । यह प्रश्न पामगढ़ विधान सभा से संदर्भित है । अब आप पूरे प्रदेश को पूछें तो मंत्री जी जवाब कैसे देंगे ? जो प्रश्न आया है, उन्होंने उसका जवाब पूरा का पूरा दे दिया है । आपको पूरा अवसर मिलेगा । आप इसे राज्यपाल के अभिभाषण और चर्चा में भी रख सकते हैं । श्रीमती गोमती साय अपना प्रश्न करें ।

श्री दिलीप लहरिया :- तब तक तो सत्र निकल जायेगा, अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती गोमती साय ।

विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव अंतर्गत जल जीवन मिशन के कार्यो की अद्यतन स्थिति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

2. (*क्र. 224) श्रीमती गोमती साय : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव अंतर्गत कहॉ-कहॉ पर जल जीवन मिशन का कार्य अपूर्ण है, अपूर्ण होने का क्या कारण है ? **(ख)** जिन ठेकेदारों ने निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नही किया, उन के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई, क्या उन्हें ब्लेक लिस्ट किया गया, यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं कराये जाने पर क्या कार्यवाही की गई, यदि नहीं तो क्यों ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव अंतर्गत 166 ग्रामों में जल जीवन मिशन के कार्य अपूर्ण है। अपूर्ण कार्य एवं अपूर्ण होने का कारण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** जिन ठेकेदारों ने निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नही किया, उनके विरूद्ध अनुबंध की शर्तों के अनुसार पेनाल्टी लगाई गई है। जी नहीं। कार्य प्रगतिरत होने के कारण उन्हे ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है। **(ग)** निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं कराये जाने पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार पेनाल्टी लगाने की कार्यवाही की गयी है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

श्रीमती गोमती साय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था, उसका उत्तर मुझे मंत्री जी से मिल चुका है । जिस विषय को लेकर मैंने प्रश्न पूछा है, वह देश के मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन योजना है, जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की योजना है । मुझे सारे उत्तर मिल चुके हैं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है । माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की योजना है कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर में शुद्ध पेय जल पहुंचे । वह योजना पहले 5 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई थी, जिसके कारण आज पूरे प्रदेश में अव्यवस्था फैली हुई है । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि इस योजना को व्यवस्थित करने के लिए आपने क्या-क्या योजना और रचना बनाई है ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही सही कहा है कि आजादी के इतने सालों के बाद दूरस्थ गांव के लोग, अंचल के लोग पोखर का पानी, तालाब का पानी पीते थे और कई-कई किलोमीटर दूर जाकर अपने पेयजल की व्यवस्था करते थे । प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने सन् 2019 में जल जीवन मिशन योजना प्रारंभ की और उन्होंने हर घर तक शुद्ध पेय जल पहुंचाने की योजना बनाई । हमारे छत्तीसगढ़ में वह योजना वर्ष 2019 में प्रारंभ क्यों नहीं हुई, मैं उस कारण के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वर्ष 2019 की बजाय वर्ष 2021 में यह योजना प्रारंभ हो पाई और बाकी कम्पानेंट के ठेके 2021 में हो गए, टेण्डर हो गए, पर जो मुख्य चीज नलकूप है, उसका टेण्डर अप्रैल, 2023 के बाद प्रारंभ हुआ और उसमें अनेक प्रकार की विसंगतियां हुईं, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद हमने लगातार इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए पूरी ताकत लगाकर काम किया है और हमारी एक साल की जो उपलब्धि है, वह मैं आपके सामने रखना चाहूंगा । माननीय सदस्या ने इस विषय पर प्रश्न पूछा है । कुछ तथ्य जो आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को पता चले, इस दृष्टि से मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर जल जीवन मिशन को 15 अगस्त, 2019 को लांच किया गया । हमारे प्रदेश में केबिनेट की बैठक के बाद वह योजना फरवरी, 2021 से प्रारंभ हुई । छत्तीसगढ़ के जल जीवन मिशन की कुल लागत 26,465.74 करोड़ रूपए थी, जिसमें केन्द्रांश 12424.57 करोड़ और राज्यांश जो कुछ अन्य मदों को मिलाकर 14041.17 करोड़ है । वर्तमान में 6178.33 करोड़ रूपए केन्द्रांश और राज्यांश 7292.28 करोड़ प्राप्त हुए हैं । कुल मिलाकर 13470.61 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त हुई है । 26465 करोड़ रूपए में से 13470 करोड़ रूपए की राशि मतलब आधी राशि व्यय हुई है । इस योजना में 19656 गांव सम्मिलित हैं, जिनके 50,03,016 परिवारों में नल के कनेक्शन देने हैं । जब यह योजना 2019 में लांच हुई, तब इस योजना की अवधि 2024 तक थी और अभी 2025-26 के बजट में वित्त मंत्री जी ने इस योजना की अवधि वर्ष 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है । जनवरी, 2025 तक हमारे प्रदेश में 50 लाख में से 40.21 लाख घरों में नल के कनेक्शन दिए गए हैं, जो लक्ष्य के 80.3 प्रतिशत हैं और 9 लाख, 82 हजार घरों में नल के कनेक्शन

देना शेष है । इन 19656 गांवों में 653 गांव ऐसे हैं, जहां पर स्त्रोत उपलब्ध नहीं है । जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्यूब वेल खनन का काम अप्रैल, 2023 से प्रारंभ हुई और अभी तक ट्यूब वेल खनन के जो हमारे लक्ष्य थे, उसमें से आधे से थोड़ा ज्यादा खनन ही हुए हैं । हम ट्यूब वेल खनन का काम लगातार कर रहे हैं । इस बीच हमने एक साल में 3438 नलकूप खोदे हैं और नलकूप के माध्यम से 2527 स्रोत स्थापित किए हैं। हाइड्रो-फैक्चरिंग विधि से 735 नलकूप जीवित किए गए हैं। इस बीच 2711 टंकियों का निर्माण हुआ है। हमने पंचायतों को एक साल में 2141 योजनाओं को हस्तांतरित किया है और हर घर जल प्रमाणित जो गांव हैं, वे 1438 हैं। इस प्रकार लगातार हम इस योजना को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस बीच हमने 351 ठेकेदार जो काम प्रारंभ नहीं कर रहे थे, उनके ठेके निरस्त किए हैं। हमने 3 लाख, 20 हजार, 856 मीटर पीवीसी पाईप्स, जो कि मानक के अनुरुप नहीं थे, को अस्वीकृत किया है, और 15 एजेंसियों को डिबार किया है। जो टंकियॉ गुणवत्ता के अनुरुप नहीं थी, ऐसी 389 टंकियों को तोड़ने का काम किया, नल के चबूतरे जो ठीक नहीं थे, ऐसे 4679 चबूतरों को तोड़ने का काम किया, 14 बाउंड्रीवॉल तोड़े गए। पाईप उखाड़कर बदलने का काम, ये लगातार चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, पर्याप्त है। आपने व्यापक उत्तर दिया, वैसे भी प्रश्नकर्ता संतुष्ट थीं और आपके जवाब के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है। अच्छा जवाब आया।

श्रीमती गोमती साय :- अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न और है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं उप मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि इन्होंने इतनी बड़ी योजना पर कार्रवाई करने का काम किया हैं, लेकिन जो अभी लंबित हैं, उन कार्यों के लिए एक समय सीमा निर्धारित हो, ताकि गांव-गांव तक, जन-जन तक पानी पहुंचे, इस विषय में आप थोड़ा जरुर काम करें। इसके लिए आप क्या योजना बनाए हैं, कृपा करके बताने का कष्ट करेंगे?

श्री अरुण साव:- अध्यक्ष महोदय, पूरी मजबूती से प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की आकांक्षाओं के अनुरुप इस योजना को पूरा करने हेतु हमारा विभाग पूरी ताकत से लगा हुआ है।

अभनपुर नगर अंतर्गत गौरव पथ निर्माण योजना

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

3. (*क्र. 479)श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अभनपुर नगर पालिका में मुख्य मार्ग पर गौरव पथ निर्माण कार्य की कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हाँ तो कितने किलोमीटर लंबाई के

कितनी राशि के निर्माण की योजना है? (ख) वर्तमान में अभनपुर नगर गौरव पथ योजना किस स्तर पर प्रक्रियाधीन है?

उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) (श्री अरूण साव) : (क) जी हॉ, लोक निर्माण विभाग द्वारा अभनपुर नगर पालिका क्षेत्र में पुराने नेशनल हाईवे में गौरवपथ निर्माण कार्य 2.8 कि.मी. राशि रुपए 2640.51 लाख की प्रस्तावित की गई है। (ख) लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता, नवा रायपुर अटल नगर को संशोधित प्राक्कलन कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

श्री इन्द्र कुमार साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या अभनपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अभनपुर नगर पालिका में मुख्य मार्ग पर गौरव पथ निर्माण की कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हॉ तो कितने किलोमीटर लंबाई के कितनी राशि के निर्माण की योजना है?

श्री अरुण साव:- अध्यक्ष महोदय, अभनपुर में वर्ष 2017 में गौरव पथ निर्माण की घोषणा हुई थी। प्रारंभिक तौर पर उसकी कार्यवाही नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा की जा रही थी, बाद में शासन स्तर पर बैठक हुई और लोक निर्माण विभाग को वह हस्तांतरित किया गया है। लोक निर्माण विभाग ने 26 करोड़ 40 लाख 51 हजार रुपए का उसका पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया है और यह स्वीकृति के प्रक्रियाधीन है।

श्री इन्द्र कुमार साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है।

प्रदेश में बंद पड़े इन्डक्शन फर्नेस तथा रोलिंग मिलों के कर्मचारियों का नियोजन

[वाणिज्य एवं उद्योग]

4. (*क्र. 432) डॉ. चरण दास महंत : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) दिसम्बर, 2023 तक प्रदेश में कितने इन्डक्शन फर्नेस (मिनी स्टील प्लान्ट) और रोलिंग मिल उत्पादनरत थे? जनवरी, 2024 से जनवरी, 2025 तक कितने में उत्पादन कार्य बंद है? बन्द होने का कारण उद्योग के नाम सहित बतावें? बन्द होने के कारण उत्पादन कितना कम हो रहा है? (ख) उक्त बन्द हुए उद्योगों में कितने-कितने कर्मचारी, तकनीशियन, इंजीनियर, प्रबंधक कार्यरत थे?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) :(क) जिलों से प्राप्त जानकारी अनुसार उद्योगों को जारी ई.एम. पार्ट-II एवं उत्पादन प्रमाण पत्र अनुसार दिसम्बर 2023 तक प्रदेश में 232 इन्डक्शनफर्नेस (मिनी स्टील प्लान्ट) और रोलिंग मिल विभाग में पंजीकृत थे। जनवरी, 2024 से जनवरी 2025 तक 05 इकाईयों में उत्पादन कार्य बंद है। बंद होने के कारण उत्पादन कुल 3,10,860 टन (तीन लाख दस हजार आठ सौ साठ) कम हो रहा है। बंद होने का कारण की जानकारी उद्योग के नाम सहित

प्रपत्र पर दर्शित है। (ख) उक्त बन्द हुए उद्योगों में कार्यरत कर्मचारी, तकनीशियन, इंजीनियर, प्रबंधक की जानकारी प्रपत्र पर दर्शित है।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जी से है। मंत्री जी, आप सुन रहे हैं ना? मैं वित्त मंत्री जी के बजट भाषण का उल्लेख करते हुए बताना चाहता हूं कि वर्तमान उद्योग नीति की समीक्षा करके नई उद्योग नीति जारी की जाएगी। इसमें राज्य में उपलब्ध कृषि उत्पाद, वनोपज एवं खनिज संपदा तथा रोजगारमूलक उद्योगों की स्थापना का ध्यान रखा जाएगा और नए उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ-साथ कोर सेक्टर में पूर्व से कार्यरत उद्योगों को क्षमता विकास के लिए अनुकूल अवसर दिए जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से पूछा है कि जनवरी 2024 से जनवरी 2025 के अंतर्गत कितने उत्पादन कार्य बंद हुए। इन्होंने मुझे 5 उत्पादन कार्य बंद होने की सूचना दी है, जिसमें कुल मिलाकर 274 लोगों को सेवा से अलग किया गया और विशेषकर राजनांदगांव जिले के ग्राम टेडेसरा में जो ओरियेण्ट इस्पात प्रा. लि. है, इन्होंने उस उत्पादन केंद्र को भी बंद कर दिया है। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से सबसे पहले यह पूछना चाहता हूं कि आपने एक साल में सिर्फ इसी जिले के खनिज से संबंधित 5 उत्पादन केंद्र बंद किये हैं। आप इसी के बाद बता दीजिये कि यह जो उद्योग बंद हुए हैं, उसके कारण आपने बताया है कि वे वित्तीय घाटा और वित्तीय कारणों से बंद हुए हैं तो फिर इन लोगों को आपने सहयोग क्यों नहीं दिया ? क्या आप इसकी जानकारी देंगे ?

श्री लखनलाल देवांगन :- अध्यक्ष महोदय, जो 5 उद्योग बंद हुए हैं, उनको भी उद्योग विभाग के नियमानुसार जो अनुदान राशि, सब्सिडी दी जाती है, वह उनको प्रदान की गयी है। वे 5 उद्योग वित्तीय कारणों से बंद हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि पांचों उद्योगों को हमने अपने ब्याज अनुदान में से 75 लाख 31 हजार और स्थायी पूंजी में से 60 लाख रूपये की अनुदान राशि देकर सहायता की गयी है। इस तरह से निरंतर प्रक्रिया है। वैसे वह उद्योग किसी कारण से बंद हुए होंगे। वे अपने परिचालन घाटा के कारण बंद हुए हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसमें बताना चाहूंगा कि वर्ष 2023 में कांग्रेस के शासन काल में 18 उद्योग बंद हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आप प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय सबसे ज्यादा स्टील उद्योग लगे थे। कांग्रेस के शासन काल में वर्ष 2023 में ही 18 उद्योग बंद हुए है और पांच साल में कुल 27 उद्योग बंद हुए हैं। इस तरह से यह रूटीन का मामला है। यदि किसी का उद्योग नहीं चल पाता है तो वह अपना उद्योग बंद कर देता है। इसके अतिरिक्त हम लोगों का तो पूरा प्रयास है कि उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। इसके लिए नयी उद्योग नीति भी ...।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। महंत जी, और कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिये।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मुझे यह लग रहा है कि माननीय मंत्री जी घबरा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप छोटा-छोटा प्रश्न करिये।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, वह आप की ही तरफ इंगित कर रहे हैं तो क्या मैं भी आप की ही तरफ इंगित कर सकता हूं ? लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल, हम जिनकी 150वीं जयंती मना रहे हैं। आपने पण्डरिया में उद्योग खोला था, वह विश्व की बेस्ट टेक्नोलॉजी थी और उसमें हाईयेस्ट शुगर का उत्पादन होता था और वहां बिजली भी बनती थी, वह 18 फरवरी, 2025 को बंद हो गया। वह इसलिए बंद हो गया क्योंकि आपने गन्ना उत्पादकों को पैसे नहीं दिये, उनका भुगतान नहीं किया। भोरमदेव भी आपका क्षेत्र है। भोरमदेव में जो शक्कर का कारखाना था, वह 26 जनवरी, 2025 को बंद हो गया, जहां बिजली का भी उत्पादन होता था। बालोद का शक्कर कारखाना भी बंद हो गया। हमारी सरकार ने मक्का से इथेनॉल बनाने के लिये कोण्डागांव में उद्योग चालू करने के लिये तैयारी कर रखी थी। वह चालू नहीं हुआ क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि यह कार्य भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है और सूरजपुर जिले के कसहा गांव में शक्कर कारखाना बंद है। माननीय मंत्री जी, हम लोगों ने एक रिवाल्विंग फंड बनाया था। उस रिवाल्विंग फंड में यह व्यवस्था थी कि शक्कर कारखाना में या अन्य किसानों को गन्ना उत्पादन के कुछ पैसे देने हो तो उनको पैसे दिये जाएं। ताकि वह गन्ना उत्पादित कर सकें और उनको किसी तरीके से कोई कठिनाई न हो। आप लगातार जो प्लांट बंद करते जा रहे हैं, आप किसी को लीज में देना चाहते हैं, किसी को किराये में देना चाहते हैं तो फिर आपकी औद्योगिक नीति का क्या मतलब है? आपने अपने जवाब में कहा है कि क्षमता विकास के लिए अनुकूल अवसर प्रदान किये जाएंगे। आप यही अनुकूल अवसर प्रदान कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, क्या आप इस विषय में बता पाएंगे ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता जी ने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न से अलग हटकर, प्रश्न कर रहे हैं। अगर प्रदेश के शक्कर कारखाना वगैरह का प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं, उनको अलग से जानकारी दे दूंगा।

डॉ. चरणदास महंत :- चलिए। इस पर अलग से प्रश्न कर लूंगा और ध्यानाकर्षण ले आऊंगा। आप इसी बात पर बता दीजिए कि आप शक्कर कारखानों के संबंध में मत बताईये। जनवरी 2024 से 2025...।

अध्यक्ष महोदय :- यह मिनी स्टील प्लान्ट का प्रश्न है। उनका कहना है कि आप प्रश्न तक सीमित रहे तो ज्यादा अच्छा है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है। प्रदेश के मिनी स्टील प्लान्ट में...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी सीमित कैसे रहेंगे वह तो असीमित आदमी हैं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी असीमित हैं, मगर उन्होंने प्रश्न सीमित किया है। उन्होंने मिनी स्टील प्लान्ट से संबंधित प्रश्न किया है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के मिनी स्टील प्लान्ट जितने बंद हुए हैं क्या आप बता सकते हैं कि जनवरी, 2024 से जनवरी, 2025 के दौरान प्रदेश में एक भी मिनी स्टील प्लान्ट नया खुला है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे प्वाईंटेड तो प्रश्न नहीं हो सकता।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में एक भी नया मिनी स्टील प्लान्ट नहीं खुला है। बाकी बहुत सारे उद्योगपतियों ने अलग-अलग उद्योगों को खोलने के लिए इच्छा जाहिर की है । अगर आप अगल-अलग बताने के लिए कहेंगे तो मैं, आपको बता दूंगा।

डॉ. चरणदास महंत :- नहीं। माननीय मंत्री जी, आप समय खराब मत करिये। सदन का समय कीमती है। यहां उद्योग बंद होने पर बेरोजगार कर्मचारियों को कारखाना अधिनियम एवं श्रम अधिनियम के तहत मुआवजा का भुगतान करने का प्रावधान है तो जो प्रदेश में मिनी स्टील प्लान्ट के कारखाने बंद हुए हैं क्या उनको, आपके श्रम अधिनियम और कारखाना अधिनियम के तहत मुआवजा का भुगतान किया है ? यदि हां तो कितने लोगों को मुआवजे का भुगतान किया गया है और यदि हां तो उनको कितने रूपये के मुआवजा का भुगतान किया गया ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग के द्वारा उनको मुआवजा नहीं दिया गया है, यह उद्योगों की जिम्मेदारी रहती है। बाकी प्रदेश में कोई नया उद्योग खुलेगा तो उनको हम सहयोग प्रदान करेंगे। उनको मुआवजा नहीं दिया गया है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो बंद होने वाले कारखानों में लगे हुए कर्मचारियों के लिए मुआवजे भुगतान की बात है। अगर उन्हें मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया तो हम क्या करेंगे ? यह तो बहुत गंभीर प्रश्न है और इसका उत्तर बहुत ही साधारण है।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो श्रम विभाग के द्वारा श्रम अधिनियम प्रसारित है, उसके नियम अनुसार उनको प्रावधानित किया जायेगा।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको नियम अनुसार प्रावधानित किया जायेगा ? आप उनको मुआवजा देंगे ?

श्री लखन लाल देवांगन :- नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह श्रम विभाग के नियमानुसार होगा।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हां, श्रम और कारखाना अधिनियम है। यह दोनों अधिनियम आपके अधिनस्थ है। इन दोनों अधिनियम के तहत जो काम करने वाले हैं।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसको दिखवा लूंगा और जो भी नियम में होगा, हम उसको करेंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- आप यह करेंगे ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी नियम में होगा, हम उसको करेंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- आप यह निमानसुार करेंगे। आपको धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- आपको धन्यवाद्।

जलजीवन मिशन अंतर्गत स्त्रोत विहीन स्थानों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

5. (*क्र. 271) श्री अजय चंद्राकर : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रदेश के कुल कितने ग्रामों के कितने घरों में नल कनेक्शन लगाने का लक्ष्य रखा गया है तथा लक्ष्य के अनुरूप कितने ग्रामों के, कितने घरों में नल कनेक्शन कार्य पूर्ण/अपूर्ण/प्रगतिरत्/अप्रारंभ की स्थिति में हैं तथा निर्धारित समायावधि कब तक है? कितनी बार समय वृद्धि की गयी तथा नवीन समयावधि कब तक निर्धारित की गयी है? कितना प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है और निर्धारित लक्ष्य से कितना आगे/पीछे चल रहा है? **(ख)** उक्त योजनांतर्गत ऐसे कितने ग्रामों के घरों में, कितनी लागत का नल कनेक्शन लगाया जा चुका है जहां जल स्त्रोत विहीन व पर्याप्त जल स्त्रोत विहीन हैं? क्या इन स्थानों में नल कनेक्शन से संबंधित कार्य पूर्ण करने के पूर्व जल स्त्रोत का परीक्षण कराया गया था? यदि हां, तो ऐसी स्थिति में किसके निर्देश पर कनेक्शन लगाने की मंजूरी दी गयी? यदि परीक्षण नहीं किया गया है तो किस आधार पर नल कनेक्शन लगाया गया? इन एजेंसियों के नाम, मालिक का नाम व पता सहित बतायें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) :(क) जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रदेश के कुल 19656 ग्रामों में 50,03,519 घरों में नल कनेक्शन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य के अनुरूप 5291 ग्रामों के 12,80,808 घरों में नल कनेक्शन कार्य पूर्ण, 14,079 ग्रामों के 37,00064 घरों में नल कनेक्शन कार्य अपूर्ण/प्रगतिरत एवं 286 ग्रामों के 22,647 घरों में नल कनेक्शन कार्य अप्रारंभ की स्थिति है। निर्धारित समायावधि वर्ष 2024 थी। एक बार समयावृद्धि की जाकर नवीन समयावधि वर्ष 2028 लक्ष्य के विरूद्ध 80.3 प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन कार्य पूर्ण हो चुका है। लक्ष्य के विरूद्ध 19.7 प्रतिशत पीछे चल रही है। **(ख)** योजनांर्तगत स्त्रोत विहीन व पर्याप्त जल स्त्रोत विहीन 3907 ग्रामों के 8,08,411 घरों में नल कनेक्शन लगाये गये। लागत रू. 208666.7 लाख। जी हां। नल कनेक्शन लगाने की मंजूरी जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के अनुमोदन पश्चात् कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा दी गई है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। जल स्त्रोत विहीन व पर्याप्त जल स्त्रोत विहीन ग्रामों में कार्यरत एजेंसियों के नाम, मालिक का नाम व पता सहित जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र** अनुसार है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपको एक लाईन पढ़कर सुनाता हूं, फिर आपसे प्रश्न करूंगा। यह विधान सभा से ही संबंधित है। मेरे 16 दिसम्बर, 2024 के ध्यानाकर्षण में माननीय मंत्री महोदय जी ने विधान सभा में जो कहा है। वहां स्थानों पर टंकी बन गई है और जल स्त्रोत नहीं है। यह उसी से संबंधित प्रश्न है। आपको इसकी जिलेवारी जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। माने मुझे उपलब्ध करवाएंगे। आज तक तो मुझे वह जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। अब विधान सभा के स्टेटमेंट में भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ? यह महत्वपूर्ण हो गया है। इस सरकार के अधिकारी माननीय मंत्रीगण के कथन को गंभीरता से लेते है या नहीं लेते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि मेरे प्रश्न के पूरे उत्तर को ही बदल दिया गया। मुझे यह उत्तर शाम को मिला है। मेरे प्रश्न का जो उत्तर था, जो पूर्व में प्रिंट था उससे वह दूसरा हो गया है, लेकिन चलिये, मैं, आपसे फिर से उसी में प्रश्न करना चाहता हूँ। जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत स्त्रोत विहीन व पर्याप्त जल स्त्रोत विहीन 3 हजार 907 ग्रामों के 8 लाख 8 हजार 411 नल कनेक्शन लगाए गए हैं । पर्याप्त जल स्त्रोत से मेरा आशय कुछ नहीं है। मैं फिर वही प्रश्न पर आऊंगा कि जल स्त्रोत विहीन गांव कितने हैं जिसमें पाईनलाईन डल गई है और टंकी बन गई है ? मेरा छोटा सा प्रश्न है, यह बता दीजिए।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जल स्त्रोत विहीन गांवों की संख्या 653 है और उसमें से 3254 गांव ऐसे हैं, जहां अपर्याप्त स्त्रोत हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रश्न दोहरा देता हूं। ऐसे जल स्त्रोत विहीन गांव कितने हैं जिसमें पाईपलाईन डल गई है और टंकी बन गई है?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय के प्रश्न का बहुत विस्तार से उत्तर दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट में विस्तार से उत्तर दिया है। मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न है, उद्भूत हो रहा है। आप मुझे इसकी 4 महीने पहले जानकारी देने वाले थे।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी बहुत विस्तृत से जानकारी दी है। मैंने जैसे बताया कि नलकूप खनन का काम अप्रैल 2023 से प्रारंभ हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं यह प्रश्न तो पूछ ही नहीं रहा हूं।

श्री अरूण साव :- मैं आपको स्त्रोत के ही कारण बता रहा हूं कि नलकूप खनन का काम अप्रैल 2023 से प्रारंभ हुआ इसलिए स्त्रोत की दिक्कत हुई है। हर एक स्कीम में जब डी.पी.आर. तैयार हुआ, उसका ग्राम सभा से अनुमोदन हुआ, हर एक स्कीम में एक स्त्रोत identified था। उसी के हिसाब से वह काम प्रारंभ हुआ, नलकूप खनन विलंब से प्रारंभ हुआ, इसलिए स्त्रोत की दिक्कत आ रही है। जैसा मैंने बताया कि जल स्त्रोत विहीन गांवों की संख्या 653 है जिसमें वहां पर 1,32,717 घर हैं, जहां पर नल कनेक्शन हुए हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी नल कनेक्शन में प्रश्न पूछा ही नहीं हूं। मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न है कि कितने गावों में जल स्त्रोत नहीं हैं और पाईपलाईन और टंकी बना दी गई ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 653 गांव बताया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसमें पाईपलाईन और टंकी डल गई है ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि जो आपका जल जीवन मिशन है, आप जो इधर-उधर की बात बता रहे हैं। क्या बिना जल स्त्रोत के पाईपलाईन और टंकी बनाई जा सकती है ? कार्यपालन अभियंता या जिला स्वच्छता समिति में जो भी है जिन्होंने इसको अनुमोदन दिया है, क्या बिना जल स्त्रोत के गावों में अनुमोदन दे सकते हैं ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी स्पष्ट किया कि जब प्रारंभिक तौर पर डी.पी.आर. बना, ग्राम सभा से उस डी.पी.आर. का अनुमोदन हुआ। जिला जल एवं स्वच्छता समिति ने उसका अनुमोदन किया और हर एक योजना में एक जल स्त्रोत चिन्हित था। वह जल स्त्रोत चिन्हित होने के कारण से वह काम आगे बढ़ा। इसमें जो बड़ी दिक्कत हुई कि अप्रैल 2023 से ट्यूबवेल का टेंडर हुआ और इसलिए प्रोग्रेस दिखाने के लिए भी काम चला। प्रोगेस दिखाने के लिए नल के कनेक्शन लगाये गये। हमारी सरकार बनने के बाद हमने इसका विश्लेषण किया। शायद प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक साथ 6 executive engineer को निलंबित किया और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, मैं छोटा-छोटा प्रश्न पूछा रहा हूं, आप छोटा-छोटा उत्तर दे देते तो कृपा रहती। आप अच्छा काम कर रहे हैं मैं प्रशंसा कर देता हूं, यह बोल देता हूं कि सब अच्छा है। आप मेरे से जितनी प्रशंसा सुनना चाहेंगे, मैं बिल्कुल चारणभार जैसे प्रशंसा कर दूंगा। लेकिन मैं बहुत छोटा प्रश्न पूछ रहा हूं। आपने डी.पी.आर. बनाया, आप जो बार-बार डी.पी.आर. बोल रहे हैं। डी.पी.आर. में जल स्त्रोत नहीं था तो उसके बाद जो टंकी और नल कनेक्शन बिछाये तो उन जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब मैं आगे बोलूंगा तो आरोप हो जायेगा, जिसको मैं नहीं लगाना चाहता हूं । आप यह बतायेंगे कि डी.पी.आर. में जल स्त्रोत था या नहीं था तो इससे अच्छा आप मुझको यह बता दीजिये ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा कि जब डी.पी.आर. तैयार हुआ, ग्राम सभा में उसका अनुमोदन हुआ तो हर एक योजना में एक जल स्त्रोत चिन्हांकित था और मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में बताया कि 26 हजार करोड़ से अधिक की यह योजना है, केवल 13

हजार करोड़ रूपये व्यय हुए हैं मतलब 50 प्रतिशत व्यय हुआ है, काम पूर्ण नहीं हुआ है और जब तक पूरी तरह से वह काम प्रमाणित नहीं हो जायेगा ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्री अजय चंद्राकर :- सर, एक मिनट । अभी तो मेरा चल रहा है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे एक आग्रह है कि आप उपमुख्यमंत्री हैं, आप वरिष्ठ हैं, ये दोनों खड़े रहते हैं । ये जब प्रश्न करते हैं तब भी खड़े रहते हैं और वे जब उत्तर देते हैं तब भी खड़े रहते हैं, ये बाद में बैठे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कृपया निर्देश करिये कि जब एक बोले तो दूसरा बैठ जाये ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं समझा कि आप प्रश्न कर रहे हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- वे कोशिश तो पूरी कर रहे हैं लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो क्या करें । (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- क्या है कि यह आपके समय की कलाकारी है जिसको वे भोग रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न है कि डी.पी.आर. में पानी नहीं होने के बाद भी यानी जल स्त्रोत नहीं होने के बाद भी नल टंकी बनायी गयी, पाईप लाईन बिछाई गयी जो खुला करप्शन है । क्या उन गांवों में जहां आज भी जल स्त्रोत नहीं है और जिसमें टंकी और पाईप लाईन बिछा दी गयी उन गांवों को चिन्हित करके क्या आप उन अधिकारी या तत्कालीन समय के लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने यह स्पष्ट रूप से कहूंगा कि किसी भी ठेकेदार का जब तक काम पूरा नहीं होगा, 70 प्रतिशत से अधिक भुगतान नहीं करेंगे और जब तक पूरी तरह से वह योजना संचालित नहीं होगी, भुगतान नहीं होगा और स्त्रोत नहीं पाया गया, योजना पूरी नहीं हुई तो संबंधित लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, दूसरा प्रश्न ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय :- वे कड़ी से कड़ी बोल रहे हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक साल से कड़ी से कड़ी कार्रवाई को देख रहा हूं । कितनी कड़ी कार्रवाई हुई है उसको मैंने देखा है । मैं अभी जिस गांव के बारे में बोलूंगा तो आप वहां जाकर देखेंगे, आप बोलिये तो मैं आपको आमंत्रित कर देता हूं । उसमें अभी कुछ भी नहीं हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप छोटा प्रश्न कर लीजिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप शांति से प्रश्न करिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो शांति से ही प्रश्न कर रहा हूं । आपने तो मुझे पहले ही निर्देश दे दिया है कि शांति से रहना है ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, प्रश्न आराम से करिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा आपके उत्तर को पढ़ रहा हूं कि जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रदेश के कुल 19656 ग्रामों में आपको लगभग 50.03 लाख घरों में नल कनेक्शन लगाने थे । आपने 5291 ग्रामों में 12 लाख 80808 कनेक्शन दिये हैं, आपने 50,000 में 12 हजार लगाया है और इसको आप बोल रहे हैं कि 80.3 प्रतिशत पूरा हो गया है तो यह कौन से गणित में 80 प्रतिशत पूरा हो गया है ?

श्री अरूण साव :- मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं । आप प्रश्न पढ़िएगा कि लक्ष्य के अनुरूप कुल कितने ग्रामों के कितने घरों में नल कनेक्शन पूर्ण तो जिन गावों में सौ प्रतिशत कनेक्शन हो गया है, उन गांवों की संख्या 5291 है और बाकी के जो कनेक्शन हैं किसी गांव में 80 प्रतिशत हुए हैं, कहीं 90 प्रतिशत हुए हैं, कहीं 70 प्रतिशत हुए हैं इसलिये वह आंकड़ा 40 लाख से ऊपर है ।

श्री अजय चंद्राकर :- अच्छा चलिये, मैं आपकी बात मान लूं । आप अपनी उपलब्धियों में अभी बहुत सारी बातें कर रहे थे तो यह मान लें कि 19656 ग्रामों में केवल 12 हजार नल कनेक्शन लगे हैं, यह मान लें न ? 19656 ग्रामों में अभी तक 12 हजार कनेक्शन ही लगे हैं कि ज्यादा लगे हैं ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद समझने में दिक्कत हो रही है । मैंने यह कहा कि 5291 ग्रामों के...।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने उसको लिखा है, आप मेरी बात समझ लीजिये या हो सकता है कि जो कन्फ्यूजन क्रियेट हो रहा है वह ठीक हो जाये । आपको 50 लाख समथिंग नल कनेक्शन देने हैं उनमें से 5000 गांव की ही बात कर रहा हूं, मान लीजिये कि आपने 5000 गांव में 12 लाख 80808 ही नल कनेक्शन दिये हैं तो यह कुल कनेक्शन की संख्या है कि जो 5000 गांव हैं उनकी संख्या है ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 5000 गांव की संख्या है । जो 5000 गांव हैं वहां नल कनेक्शन की संख्या है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- तो उसमें 80 प्रतिशत है न, ठीक है, चलिए।

श्री अरूण साव :- कुल मिलाकर जितना 50 लाख कनेक्शन देना है, उसका 80 प्रतिशत हमने किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब जो भी आप चाहें। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप उत्तर दे सकते हैं तो, मैं इस प्रश्न में शुरू दिन से जिस दिन से सरकार बनी है, उस दिन से लगा हूं। आपने एक भी कार्रवाई नहीं की है। जो जल स्रोत विहीन गांव हैं और जिसमें नल टंकी लग गई है और पाइपलाइन

बिछ गयी है, क्या उसकी जांच करवाकर कार्रवाई करेंगे और क्या जल स्रोत की व्यवस्था के लिए कोई आश्वासन सदन को देंगे कि इतनी अवधि में जल स्रोत की व्यवस्था हो जाएगी? क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं, यह उत्तर मैं आपसे तीसरी बार सुन रहा हूं और हम वहीं के वहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप जवाब सुन लीजिए।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार ने बजट घोषणा में योजना की अवधि वर्ष 2028 तक बढ़ाई है और इसके लिए 67,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। (मेजों की थपथपाहट) मैंने भी जैसे आपको बताया कि 26,000 करोड़ रूपये से अधिक की योजना है, केवल 13,000 करोड़ रुपये खर्च हुआ है। योजना की कार्यवाही चल रही है। योजना प्रगतिरत है और आपके सामने धमतरी जिले का और कुरूद विधान सभा का भी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर देता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं-नहीं, मुझे प्रदेश स्तरीय चाहिए, मैं इतना लिमिटेड आदमी नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- तो आप उसमें कार्रवाई नहीं करेंगे?

श्री अरूण साव :- मैंने आपसे पहले ही कहा कि जहां पर ये योजना सफल नहीं होगी, जल नहीं आएगा, घर तक नल पानी नहीं पहुंचेगा तो निश्चित रूप से संबंधित लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठेकेदार का भुगतान भी नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। जवाब पूरा आ गया। एक विषय यदि जानकारी उपलब्ध कराने का आश्वासन पूर्व के सत्रों में किसी भी मंत्री जी द्वारा दिया गया है तो उस जवाब को संबंधित सदस्य तक पहुंचाना और उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ये चर्चा में नहीं आना चाहिए। जिस भी जानकारी की घोषणा हम करते हैं उस जानकारी को सत्र शुरू होने के पहले माननीय सदस्य को उपलब्ध कराना चाहिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

अध्यक्ष महोदय :- आप इसी में पूछेंगे?

श्री धरमलाल कौशिक :- इसी में एक प्रश्न पूछूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं कि 17 दिसंबर, 2024 को विधान सभा में घोषणा की थी तो उन्होंने कहा था कि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। अभी जब प्रश्न लगा तो 22 फरवरी, 2025 को ही मैंने वेब न्यूज पोर्टल में पढ़ा कि मेरे प्रश्न के आधार पर आपने मेसर्स विजय सालुके, बिलासपुर, इनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कर दिया है और जो तीन हैं, मेसर्स बंसल इंफ्रास्ट्रक्चर, रायपुर को तीन वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट किया है। के. के. नायर, भंडारा, महाराष्ट्र को दो वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट किया है और एन.एन.टी. डेवलपमेंट, पटना, बिहार को भी दो वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट किया है। एक में आपने एफ.आई.आर. किया है और उनको 2 साल के लिए, 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया है। मूल रूप से

यह था कि जो सर्टिफिकेट दिया, वह फाल्स पाया गया, लगा दिया गया और जब जांच में आया तो ये सब सही पाया गया। मैं केवल आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि जब एक के खिलाफ किया है तो बाकी के खिलाफ़ भी एफ.आई.आर. कर दें और ये 2 साल, 3 साल के बजाय छत्तीसगढ़ के लिए उसको बैन कर देंगे तो ये जो करप्शन का सारा मामला आ रहा है, वह समाप्त हो जायेगा।

श्री अरूण साव :- माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जो सुझाव दिया है, निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे।

बांसकोट से केशकाल सड़क निर्माण कार्य

[लोक निर्माण]

6. (*क्र. 93)श्री नीलकंठ टेकाम : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या विकासखंड बड़ेराजपुर अंतर्गत बांसकोट से केशकाल तक सड़क मरम्मत कार्य अधूरा है ? यदि हां तो इसका क्या कारण है ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा ? **(ख)** क्या इस मार्ग का चौड़ीकरण कार्य भी किया जाएगा ? यदि हां तो कब तक ? वर्तमान में क्या प्रक्रिया प्रचलित है ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) जी हॉ। स्वीकृत मद बजट से विलुप्त होने एवं आबंटन की अनुपलब्धता के कारण अपूर्ण। निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** वर्तमान में जी नहीं। मार्ग के चौड़ीकरण कार्य हेतु किसी भी योजनान्तर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं है।

श्री नीलकंठ टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि केशकाल घाट के लिए उन्होंने आवंटन दिया। इस घाट से हमारे बहुत सारे विधायक मित्र, जो यहां बैठे हुए हैं, वे भी यहां आना-जाना करते थे। बहुत ज्यादा खराब हो गया था। बारिश के बाद रिकॉर्ड टाइम में दो महीने में हमने इसे पूरा भी किया। अब वह केशकाल घाट बहुत अच्छे तरीके से आवागमन के लिए उपलब्ध है। मेरा प्रश्न आपके मुख्यमंत्रित्व काल में जो बना हुआ केशकाल से कोंडागांव को जोड़ने वाला एक 85 किलोमीटर सड़क के बारे में है। इसमें से आधा कोंडागांव विधान सभा में है और आधा केशकाल विधान सभा में है। मेरा प्रश्न मुख्य रूप से केशकाल विधान सभा से संबंधित है, क्योंकि कोंडागांव में ऑलरेडी रोड का चौड़ीकरण हो चुका है। तो पहला प्रश्न तो मेरा यही है कि जब केशकाल घाट का renovation का काम कर रहे थे तो पूरा ट्रैफिक इस रोड में रायपुर तरफ से आने के लिए और रायपुर से जाने के लिए डायवर्ट किया गया था। इस कारण से इस रोड की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि उसमें प्रतिदिन दुर्घटना

हो रही है, प्रदूषण फैल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं । यह न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि ओडिशा का भी सारा दबाव इस रोड पर है । इस रोड का रिन्यूवेशन होना बहुत आवश्यक है । माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो जवाब दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि इसके लिए जो बजट था, वह विलुप्त हो गया है । मेरा एक ही प्रश्न है कि क्या इस बजट में इसके रिन्यूवेशन का प्रावधान किया जाएगा ? ताकि इसका सुदृढ़ीकरण का काम हो सके ।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बांसकोट से केशकाल जो 39 किलोमीटर की सड़क है जिसके रिपेयरिंग के बारे में यह प्रश्न किया है । 1 से लेकर 21 किलोमीटर तक 7 भागों में निविदा अनुबंधित है, 15 किलोमीटर का डामरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष 6 के लिए कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । शेष 18 किलोमीटर पेंच रिपेयर का टेंडर लगाया जा रहा है और इस सड़क की रिपेयरिंग हम शीघ्र कर लेंगे ।

श्री नीलकंठ टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल इसके चौड़ीकरण को लेकर भी है । क्योंकि यह भारत माला प्रोजेक्ट से हमारे नेशनल हाईवे को जोड़ने वाली सड़क होगी और आने वाले दिनों में इसका चौड़ीकरण होना बहुत आवश्यक है । इस पर सरकार की ओर से कोई पहल की जा रही है क्या ?

श्री अरूण साव :- निश्चित रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है इस पर जरूर विचार करेंगे ।

नगर पालिक निगम, रायपुर अंतर्गत अमृत मिशन योजना से वार्डों में हुये कार्यो एवं व्यय की जानकारी

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

7. (*क्र. 482)श्री मोतीलाल साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) अमृत मिशन योजना अंतर्गत नगर पालिका निगम रायपुर में 45 वार्डो में हुये कार्यों की जानकारी वर्ष 2019 से 2024 तक वर्षवार एवं वार्डवार देवें। (ख) कितनी राशि से, कितने वार्डो में, किन -किन कार्यो के लिए तथा किन-किन एजेसियों द्वारा कार्य संपादित किया गया? (ग) उक्त वार्डो में पूर्ण रूप से हितग्राहियों को जल आपूर्ति सुनिश्चित हुई है अथवा नहीं ? यदि नहीं तो उसका कारण बतावें।

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) :(क) अमृत मिशन योजना के जल प्रदाय योजना घटक अंतर्गत नगर पालिक निगम, रायपुर के 45 वार्डों में हुये कार्यों की वर्ष 2019 से 2024 तक की जानकारी [2]संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) प्रश्नांश 'ख' की जानकारी संलग्न प्रपत्र में समाहित है। (ग) योजना हेतु स्वीकृत डिजाईन एवं ड्रॉइंग अनुसार कार्य कराया गया है, जिससे वार्डों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हुई है।

[2] परिशिष्ट "दो"

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न अमृत मिशन को लेकर है । जिसमें रायपुर शहर के 70 वार्डों में से 45 वार्डों में अमृत मिशन के माध्यम से घरों तक जल आपूर्ति करना है । मुझे उत्तर के माध्यम से जानकारी मिली है उसके अनुसार 8 कार्यों के माध्यम से लगभग 41,114 लाख रूपए का खर्च बताया गया है परंतु जिन वार्डों में यह कार्य हुआ है, उन वार्डों की स्थिति अभी बहुत दयनीय है । कहीं पर पाईप लाईन तो लग गया है किंतु पानी की सप्लाई अभी तक नहीं हो पा रही है । ऐसा कैसा डीपीआर बनाया गया और कैसे कार्य पूर्ण कराया गया कि आज भी उपभोक्ता के पास पानी नहीं पहुंच रहा है । कई वार्डों में आज भी कार्य अधूरा है, खुदा हुआ है, पाईन लाईन बिछा है तो अधूरा बिछा हुआ है । कहीं कनेक्शन दिया भी गया है तो नाली में पड़ा हुआ है । कहीं कनेक्शन दिया है तो वह कुचलकर टुकड़े-टुकड़े हो गया है । आज भी शहर की ऐसी स्थिति है और जो 8 कार्य हुए हैं उनको पूर्ण बता रहे हैं, पूर्णता की ओर बता रहे हैं तो ऐसी अधूरी स्थिति में कार्य पूर्ण कैसे हो सकता है ? यह भ्रष्टाचार है, यह अनियमितता है । इस प्रकार से जनता के साथ धोखा है । अभी भी कार्य अधूरा है और सड़कों की जो खुदाई हुई थी वह आज भी कहीं अधूरी पड़ी है और कहीं वह गड्ढा बन चुका है, इसमें गुणवत्ता की बिल्कुल कमी है ।

अध्यक्ष महोदय :- इसी में प्रश्न कर लीजिए ना, क्या प्रश्न करना चाहते हैं ? आप तो जानकारी दे रहे हैं ।

श्री मोतीलाल साहू :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि ऐसा क्या हुआ कार्य करने के बाद भी, आज भी जल आपूर्ति नहीं हो रही है । पाईप लग चुका है ।

अध्यक्ष महोदय :- वह, मंत्री जी बता देंगे ।

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, रायपुर शहर में कुल 70 वार्ड हैं । 70 वार्डों में से 20 वार्डों में अमृत योजना के अंतर्गत पानी की व्यवस्था की गई है । रायपुर नगर निगम में भवनों की संख्या 2 लाख, 60 हजार, 255 है । कुल नल कनेक्शन 1 लाख, 95 हजार, 964 है । जो अमृत योजना के अंतर्गत 73,206, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत जो काम हुआ है उसमें 20,021 और पूर्व के जो कनेक्शन थे वह 1 लाख, 2737 । अमृत योजना में 20 वार्डों में पानी की सप्लाई की व्यवस्था हुई, स्मार्ट सिटी योजना से 06 वार्डों का और अमृत, स्मार्ट सिटी, पीएचई मिलाकर 12 वार्डों में नल के कनेक्शन के माध्यम से पानी की सप्लाई हो रही है । जो 13 वार्ड हैं, वार्ड नम्बर 1, 2, 6, 7, 9, 10, 32, 52, 67, 68, 61, 23, 19, 20, इन 13 वार्डों में इस योजना से नल कनेक्शन नहीं हुए हैं। 19 वार्ड हैं, जहां पर आंशिक रूप से नल कनेक्शन हुए हैं। 8 परियोजनाएं जो अमृत योजना में हुई थी, जिस काम का, जितने काम का टेंडर हुआ है, माननीय सदस्य के विधान सभा में फेस नंबर 6 और 7 है, दो टंकी बने हैं लेकिन नल कनेक्शन का कोई प्रावधान नहीं था। वह जो सर्वे हुआ था, जिस आधार पर अमृत योजना बनी थी, वह वर्ष 2016-17 का सर्वे है, उसके बाद अलग परिस्थितियां बन गयी है। फिर

से सर्वे करायेंगे और सर्वे कराकर काम करेंगे। अमृत योजना नगर-निगमों के लिए समाप्त हुई है, छोटे शहरों के लिए चल रही है। इस पर अन्य मद से जरूर विचार करेंगे, फिर से सर्वे करायेंगे। इस क्षेत्र में अभी जो जल की सप्लाई हो रही है, वह 48,857 नल के कनेक्शन पहले से हैं, 967 नग बोरवेल हैं और 385 नग हैंडपंप के माध्यम से इन क्षेत्रों में अभी भी पानी की सप्लाई हो रही है। एक बार सर्वे करायेंगे, सर्वे करा करके उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, सर्वे हो जाएगा, सर्वे करा देंगे।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वे की बात ठीक है। ये जो कार्य हुए हैं, मैंने कहा कि कार्य को पूर्णता बताया गया है। अभी भी क्षेत्रों में कार्य अधूरे हैं, गड्ढे खुदे हुए हैं, पाईपलाईन अधूरी पड़ी हुई है तो कार्य कैसे पूर्ण हो सकता है ? यह मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ने कहा न कि सर्वे कराकर जो अधूरे काम हैं, उसको पूरा करायेंगे। उन्होंने यही बोला है। आपका विषय आ गया। राजेश जी आप एक प्रश्न कर लीजिए।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं सम्माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। 20 लाख की आबादी है, 20 लाख की आबादी में 70 वार्ड हैं। 70 वार्ड में खाली एक वार्ड बता दें जिसमें 100 प्रतिशत पानी पहुंच गया हो। 70 वार्ड में 411 करोड़ रूपए शहर के अंदर पानी विस्तार के लिए खर्च हुए हैं। क्या किसी ने साईड पर डी.पी.आर. बनाने के लिए सर्वे किया ? अगर सर्वे किया है तो क्या उसका सत्यापन हुआ ? उसकी मूल एजेंसी कौन थी ? क्या नगर निगम ने उनको ok किया है ? मंत्री जी, अगर इतना ही बता दें तो बहुत है।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रीब्यूशन पाईपलाईन ओव्हरलैंपिंग न हो, इस हेतु निगम रायपुर से संबंधित जोन क्षेत्रांतर्गत जल कार्य से सम्बद्ध अभियंता लाईनमेन के माध्यम से जानकारी संलग्न कर कंसलटेंट मेसर्स आई.पी.ई. ग्लोबल दिल्ली द्वारा ड्राईंग डिजाईन तैयार कराया गया। स्वीकृत ड्राईंग डिजाईन के अनुसार कार्य के दौरान कार्यस्थल पर आवश्यकता होने पर नवीन पाईपलाईन बिछाई गयी है। पाईपलाईन के कार्य में ओव्हरलैपिंग न हो, इसके क्रियान्वयन के दौरान विशेष ध्यान रखा गया, अपितु राईजनिंग मेनलाईन नई टंकी बिछाई गयी, ओव्हरलैपिंग नहीं हुई है, सभी जो प्रक्रियाएं हैं, प्रकोष्ठ के माध्यम से नियमानुसार की गयी है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय उप मुख्यमंत्री जी, रायपुर में 75 प्रतिशत ओव्हरलैपिंग हुई है। रायपुर शहर के चारों विधायक यहीं बैठे हैं, पूर्व महापौर भी हैं। अगर आपको जिस भी अधिकारी ने ओव्हरलैपिंग नहीं हुई है कि बात कही है, आप जिस मोहल्ले में कहेंगे, उसने जिस जगह की डी.पी.आर. बनाई है, मैं आपको तथ्यात्मक प्रूफ के साथ लाकर इस सदन में बता दूंगा कि आपके यहां ओव्हरलैपिंग हुई है। 6 इंच की पाईपलाईन डली है, 4 इंच की पाईपलाईन डली है, जिसने डी.पी.आर. चैंज की पाईपलाईन को दबा दिया, 4 इंच की पाईपलाईन को दबा दिया। अध्यक्ष महोदय, यही प्रश्न मेरा भी लगा

था, मंत्री जी आपने अपने प्रश्न के उत्तर में यह बात कही है कि कहीं पर किसी भी प्रकार का डिस्फ्यूजन पाईपलाईन ओव्हरलैपिंग न हो इसलिए संबंधित क्षेत्र के जल विभाग में पदस्थ तत्कालीन उप अभियंता, सहायक अभियंता तथा लाईनमेन से जानकारी संलग्न कर कार्य का विस्तार परियोजना प्रतिवेदन निकाय द्वारा तैयार किया जाकर पाईपलाईन विस्तारीकरण का कार्य कराया गया। इस संबंध में नगर-निगम से, अध्यक्ष महोदय, मैं जो कोट कर रहा हूं, इस बात को माननीय उप मुख्यमंत्री जी गंभरता से लें कि नगर-निगम से कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया गया।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, पूरे शहर के पानी की सप्लाई का काम नगर-निगम करती है। सालों-साल से नगर-निगम पाइप लाईन का विस्तार करती है और नगर-निगम ही इसका पूरा संचालन करती है। उस नगन-निगम से कोई एन.ओ.सी. तक नहीं ली गई तो आखिर में उस पाइप लाईन का विस्तार किसके निर्देश पर कहां हुआ है ? मेरा प्रश्न यही है कि 411 करोड़ रूपये खर्च करने के बाद भी राजधानी के अंदर हम 24x7 पानी का विस्तार नहीं कर पाये तो इसके लिए जो भी दोषी अधिकारी हैं, जिन्होंने बिना जानकारी के काम किया है, क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ओव्हर लेपिंग और किसी प्रकार की अनियमितता के कोई तथ्य यदि माननीय सदस्य के पास उपलब्ध हों तो वह मुझे उसे उपलब्ध करा दें, मैं निश्चित रूप से उसकी जांच करवा लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत अच्छा। बहुत स्पष्ट हो गया।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं, राजेश जी। इसका जवाब आ गया है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजधानी का विषय है। आप जो तथ्य उपलब्ध कराने के लिए कह रहे हैं तो यह मैं लिखित में कई बार नगर-निगम में कमीश्नर से लेकर सबको समीक्षा में दे चुका हूं। जो पहले नगर-निगम में बैठे थे, उनपर मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप उनपर आरोप मत लगाइये।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, इस रायपुर शहर के पैसे का जिस प्रकार से हुआ है, सिंगल वार्ड ऐसा नहीं है। यह इस बात का दर्द है कि राजधानी के अंदर करोड़ों रूपये खर्च करने के बाद भी एक वार्ड के अंदर 24X7 पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पुराना फिल्टर प्लांट।

अध्यक्ष महोदय :- अब आपका कहां से प्रश्न आ गया ?

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैं आपके और मंत्री जी के संज्ञान में एक विषय लाना चाहता हूं कि पुराने फिल्टर प्लांट में 87 एम.एल.डी. व 45 एम.एल.डी. पानी की सप्लाई

होती थी, उसके बाद नया फिल्टर प्लांट बन गया तो 150 एम.एल.डी. के बाद भी हम नीचे तक पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो यह responsibility किसकी है ? यह एक चिंता का विषय है। मेरा इतना ही निवेदन था।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बैठ जाइये। आप सभी के प्रश्नों के बारे में माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि आपके पास जो-जो शिकायतें हैं, उनको आप लिखित रूप से दे दें। चूंकि रायपुर राजधानी है तो इसके सारे विषयों का मंत्री जी व्यापक रूप से परीक्षण करा लेंगे और जो भी विषय होगा, उसको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए इन्होंने इन सब प्रश्नों का जवाब सामूहिक रूप से दिया है।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय :- आप मंत्री जी को लिखकर दे दीजिए क्योंकि यह प्रश्न लंबा हो गया है।

श्री मोतीलाल साहू :- अध्यक्ष महोदय, मुझे जो जानकारी मिली है, उसमें 45 वार्डों को अमृत मिशन के तहत् कहा गया है और माननीय मंत्री जी ने अभी 20 वार्डों को अमृत मिशन के तहत् कहा है तो उन्होंने जो कहा है, वह सही है या मुझे जो जानकारी मिली है, वह सही है ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। प्रश्न क्रमांक-8। श्रीमती भावना बोहरा जी।

पंडरिया विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कुई में फूड पार्क की स्थापना

[वाणिज्य एवं उद्योग]

8. (*क्र. 456) श्रीमती भावना बोहरा : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या दिनांक 17 दिसंबर, 2024 के परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 53 (क्रमांक 338) में प्राप्त जानकारी के अनुसार पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कुई तहसील पंडरिया में फूड पार्क की स्थापना हेतु शासकीय भूमि को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को हस्तांतरित किया गया है ? यदि हाँ तो हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई है या नहीं ? इसकी जानकारी देवें ? **(ख)** यदि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तो फूड पार्क की स्थापना का कार्य कब तक प्रारंभ कर लिया जाएगा ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) जी हाँ, पंडरिया विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम-कुई, तहसील-कुकदूर, जिला कबीरधाम में स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 10/1 रकबा 11.498 हेक्टेयर फूड पार्क की स्थापना हेतु न्यायालय कलेक्टर जिला-कबीरधाम के आदेश क्रमांक 11256 दिनांक 04.12.2024 द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को हस्तांतरित किया गया है। भूमि का आधिपत्य राजस्व विभाग से उद्योग विभाग को दिनांक 13.01.2025 को सौंपा गया है। **(ख)** मंत्रिपरिषद् के निर्णय के अनुक्रम में, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र. एफ 20-101/2018/11/(6)

दिनांक 13.07.2024 द्वारा, स्थापनाधीन फूडपार्कों के लिए विभिन्न विभिन्न विकासखण्डों में कलेक्टर द्वारा हस्तांतरित की गई भूमि के आदेश में वर्णित प्रयोजन "फूडपार्क की स्थापना" के स्थान पर "फूडपार्क एवं अन्य औद्योगिक प्रयोजन" वर्णित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। तत्संबंध में कलेक्टर, जिला कबीरधाम को प्रश्नाधीन भूमि के हस्तांतरण आदेश में आवश्यक संशोधन हेतु संचालनालय के पत्र क्रमांक 2534, दिनांक 12.02.2025 के माध्यम से लेख किया गया है। न्यायालय कलेक्टर जिला-कबीरधाम के समक्ष हस्तांतरण आदेश दिनांक 04.12.2024 में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। संशोधन पश्चात् औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति ली जाकर अधोसंरचना विकास कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।

श्रीमती भावना बोहरा :- धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय जी। मैं सबसे पहले तो माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने पंडरिया में फूड पार्क की स्थापना की स्वीकृति दी है। लेकिन चूंकि समय कम है तो मैं उनसे इस विषय में सीधे प्रश्न पूछना चाहूंगी। इस विषय में यह मेरा तीसरा प्रश्न लगा है। इस विषय में मेरा पहला प्रश्न 23 जुलाई को लगा था और दूसरा प्रश्न 17 दिसम्बर को लगा था। वह प्रश्न सेम ही था। उस प्रश्न का जो जवाब आया था और इस बार मेरे तीसरे प्रश्न का जो जवाब आया है, वह लगभग सेम ही है कि जो फूड पार्क स्थापना की बात आई है, उसमें भूमि स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है। अध्यक्ष महोदय जी, लगभग 14 महीने हो गये हैं और 14 महीनों में यदि भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है तो कृपया आप एक बार इसकी समयावधि बताने का कष्ट करें कि उसमें अभी और कितना समय लगेगा? क्योंकि लगातार कभी तहसील कार्यालय, कभी कलेक्टोरेट और कभी संचालनालय में यह प्रक्रियाधीन रहेगी तो फिर इसमें बहुत समय लगेगा। पंडरिया जैसे टाउन कस्बे में स्थापित होने वाले इस फूड पार्क का बहुत महत्व है। कृपया मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इसमें और कितना समय लगने वाला है?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्क्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उस समय कलेक्टर के यहां इसकी प्रक्रिया चल रही थी। बाकी अभी उद्योग विभाग को पूर्ण रूप से जमीन का आधिपत्य मिल गया है और जल्द से जल्द फूड पार्क और क्योंकि वह बड़ी जमीन है तो वहां पर हम फूड पार्क के साथ उद्योग लगाने का काम भी करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, विधायक जी का कहना यह है कि उनको इस विषय में चौथा प्रश्न न लगाना पड़े, उसके पहले फूड पार्क की शुरूआत हो जाये।

श्री लखन लाल देवांगन :- अध्यक्ष महोदय, इसकी जो भी प्रक्रिया है, उसको पूर्ण करके अब जल्द से जल्द फूड पार्क शुरू हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत बढ़िया। आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। ठीक है।

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय जी, इसमें मेरा दूसरा प्रश्न यह था कि चूंकि अभी नई औद्योगि नीति आ गई है और उसके अनुसार अभी वह संशोधन के लिए विचाराधीन है तो क्या नई औद्योगिक नीति के तहत् इसमें कुछ छूट दी जाएगी ? किस तरह के उद्योगों को इसमें प्राथमिकता मिलेगी ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक नीति के तहत नया उद्योग नीति बना है, उसके तहत जो भी उद्योग लगायेंगे, उस नीति के अनुसार पूर्ण रूप से अनुदान, छूट और सब्सिडी सब मिलेगा।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भले इसकी जानकारी बाद में दे दें, लेकिन मंत्री महोदय एक बार बताने का कष्ट करेंगे कि कितना और किस तरीके से प्रोत्साहन या कितना छूट मिलने वाला है ? कृपया बताने का कष्ट करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- वह आपको डिटेल बता देंगे।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको डिटेल भिजवा दूंगा।

कांकेर जिले में जल जीवन मिशन के तहत प्रदत्त नल-जल कनेक्शनों की स्थिति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

9. (*क्र. 7)श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जल जीवन मिशन के तहत कांकेर जिले के चारामा, भानुप्रतापपुर और दुर्गकोंदल विकासखण्ड के कितने गांवों को जनवरी 2025 की स्थिति में नल-जल कनेक्शन दिया जा चुका है और कितने ग्राम बाकी हैं? क्या प्रदायित सभी कनेक्शन चालू स्थिति में हैं यदि नहीं तो कब तक चालू हो जायेंगे ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) :जल जीवन मिशन के तहत कांकेर जिले के विकासखण्ड चारामा, भानुप्रतापपुर एवं दुर्गूकोन्दल में कुल 355 ग्रामों में जनवरी 2025 की स्थिति में नल जल कनेक्शन दिया जा चुका है और 07 ग्रामों में नल कनेक्शन प्रदाय करना बाकी है। जी नहीं। निश्चित समयावधि बताया जाना सम्भव नहीं है।

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आया है। उप मुख्यमंत्री महोदय मुझे केवल यह बता दें कि जिन 355 ग्रामों में नल कनेक्शन दिया गया है, वे चालू स्थिति में हैं या नहीं ? साथ ही इसकी सूची भी उपलब्ध करा दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री जी ने जिन 355 ग्रामों का आकड़ा बताया है और केवल7 ग्रामों में ही काम बचा है, बता रहे हैं। ये आकड़ें गलत हैं और केवल कागज में है, धरातल पर कुछ और है। 355 ग्रामों में से केवल 100 ग्रामों में

भी कनेक्शन पहुंच गया हो तो बड़ी बात होगी। मैं जहां भी जाती हूं, वहां देखती हूं कि केवल टंकी बनाकर छोड़ दिया गया है या तो पाईप लाईन बिछाकर छोड़ दिया गया है। हर गांव में नल-जल कनेक्शन की शिकायत है। तो ऐसे लापरवाही ठेकेदार पर कार्रवाई होगी क्या ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के विधानसभा क्षेत्र में कुल 55,933 घरों में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कनेक्शन देना था। 49,538 घरों में नल के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। कुल 482 योजनाएं भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत हैं। 280 योजनाएं पूर्ण हो गए हैं 202 योजनाएं प्रगतिरत हैं। रेट्रोफिटिंग योजना के 113 कार्य स्वीकृत हैं, उसमें से 67 पूर्ण हो गये हैं और 46 कार्य प्रगतिरत है। एकल ग्राम योजना के 108 काम स्वीकृत हैं उसमें से 71 पूर्ण हो गए हैं और 37 प्रगतिरत हैं। सोलर आधारित 261 कार्य स्वीकृत हैं, उसमें 142 कार्य पूर्ण हो गए हैं और 119 कार्य प्रगतिरत हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि जिन 355 ग्रामों में नल कनेक्शन लग गए हैं, वहां पानी जा रहा है या नहीं जा रहा है ? सिर्फ उतना ही पूछी हैं।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसी में आ रहा हूं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समय कम है। पाईण्टेड प्रश्न है पाईण्टेड उत्तर दे दीजिये।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर दे रहा हूं। एक-एक योजना का बता रहा हूं। 84 गांवों में हर घर रिपोर्टेड नल की संख्या अनुसार जल प्रदाय हो रहा है। जो प्रमाणित गांव है, उसकी संख्या 38 है और 38 ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित भी हो गये हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका प्रश्न यही है कि 355 ग्रामों के नलों में पानी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है ? आपने उत्तर दिया है कि नल कनेक्शन लग गये हैं।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि 84 गांवों में पानी की सप्लाई हो रही है, जिसमें से प्रमाणित गांव 38 हैं।

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 355 ग्राम का आंकड़ा बहुत गलत है। क्योंकि कहीं कनेक्शन पहुंचा नहीं है। ठेकेदार बिलकुल लापरवाह हो गए हैं, उन पर बिलकुल कार्रवाई कीजिये। मेरे क्षेत्र के तीनों ब्लाक चारामा, भानुप्रतापपुर एवं दुर्गूकोन्दल में हर जगह ठेकेदार लापरवाही कर रहे हैं। इसमें कार्रवाई होगी या नहीं होगी ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि योजना प्रगतिरत है। जहां पर भी गड़बड़ी मिल रही है हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। लगातार कार्रवाई कर रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 355 ग्रामों में काम पूरा हो गया है, बोल रहे हैं और अभी 84 बोल रहे हैं। वहां पानी नहीं पहुंच रहा है। हम माननीय मंत्री जी के जवाब से असंतुष्ट होकर बहिर्गमन करते हैं।

समय
11.59 बजे

बहिर्गमन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा मंत्री जी के जवाब के विरोध में

(श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा मंत्री जी के जवाब के विरोध में सदन से बहिर्गन किया गया)

तारांकित प्रश्नों का मौखिक उत्तर (क्रमश:)

श्री राजेश मूणत :- नेता कौन हैं, समझ में नहीं आ रहा है। कभी भी कोई भी बहिर्गमन करके चले जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :-प्रश्न संख्या-10 उनको पूछने दीजिये। बहुत कम समय है। छोटा प्रश्न पूछो।

विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अंतर्गत लगाए गए फिल्टर प्लांट

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

10. (*क्र. 423)श्री रामकुमार टोप्पो : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अंतर्गत पीने के पानी की सप्लाई हेतु अब तक कितने फिल्टर प्लांट लगाये गए हैं ? उनकी लागत कितनी है ? **(ख)** वर्तमान में कितने चालू या बंद हैं ?यदि चालू हैं तो इससे नगर पंचायतों के कितने घरों को लाभ प्राप्त हो रहा है ? अगर नहीं तो क्यों ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) :(क) विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अंतर्गत पीने के पानी की सप्लाई हेतु अब तक 01 नग फिल्टर प्लांट (जल शोधन संयंत्र) लगाया गया है। फिल्टर प्लांट की लागत रू. 95.75 लाख है। **(ख)** चालू निरंक है। बंद 01 है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। नगर पंचायत सीतापुर में स्थापित फिल्टर प्लांट का उपयोग नहीं करते हुए शहर में निर्मित 04 उच्च स्तरीय जलागारों को 07 नलकूपों के माध्यम से भरकर तथा 07 नलकूप स्रोतों से सीधे पंपिंग के माध्यम से 689 घरों में पेयजल प्रदाय नगर पंचायत द्वारा किया जा रहा है।

श्री रामकुमार टोप्पो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रश्न का जवाब मिला है। पूरा प्रश्न पूछूंगा तो जवाब नहीं आयेगा। इसलिए विषय रख देता हूं कि मेरे यहां एक फिल्टर प्लाण्ट सन् 2009 से आपके कार्यकाल के दौरान लगा था, लेकिन वह आज तक चालू नहीं हुआ है। तो कब चालू होगा, इस विषय को बता दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- कब चालू होगा, प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12:00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

सहकारिता विभाग का प्रतिवेदन

(i) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2020-2021 एवं 2021-2022

सहकारिता मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार :-

(i) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 तथा

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2020-2021 एवं 2021-2022 पटल पर रखता हूँ।

पृच्छा

श्री ब्याश कश्यप (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला-जांजगीर-चांपा में मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना के अंतर्गत किसानों को ग्रीष्मकालीन धान हेतु पानी दिया जा रहा है, परंतु वर्तमान में वहां के किसान डी.ए.पी., यूरिया एवं पोटाश जैसे खादों को मार्केट से अधिक कीमत पर 500-600 रूपये में खरीद रहे हैं। यूरिया खाद की पूर्ति भी नहीं हो पा रही है। आग्रह है कि छत्तीसगढ़ सरकार सोसायटियों के माध्यम से किसानों को यूरिया, डी.ए.पी. एवं पोटाश जैसे खाद अतिशीघ्र उपलब्ध करायें।

श्री लालजीत सिंह राठिया (धर्मजयगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे रायगढ़ जिला के धर्मजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र में किसानों को बिजली सही ढंग से आपूर्ति नहीं हो पाने के कारण जो ग्रीष्मकालीन फसल दलहन, तिलहन लगाए हुए हैं, उसमें उनको परेशानी हो रही है। मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि वहां सही ढंग से बिजली की आपूर्ति की जाये।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। ध्यानाकर्षण। श्री अजय चन्द्राकर।

समय :

12:02 बजे

ध्यानकर्षण सूचना

(1) प्रदेश में राजस्व मामले लंबित होना.

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) (श्री उमेश पटेल, श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

राजस्व विभाग की जटिलता से सभी वाकिफ है, जहां छोटी सी छोटी त्रुटि चाहे वह विभागीय चुक से ही क्यो ना हो, उसके सुधार हेतु किसान एवं भू-स्वामी को राजस्व कार्यालयों के वर्षों चक्कर काटना पड़ता हैं। आज स्थिति यह बन चुकी है कि तहसील से लेकर संभागीय न्यायालयों तक में अलग-अलग धाराओं के लगभग 1 लाख 79 हजार मामले लंबित हैं। वहीं जिलों के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा 11 हजार मामले राजधानी रायपुर जिले में पेंडिंग हैं। दुर्ग जिला दूसरे स्थान पर है, जहां 10,631 मामले अटके हुए हैं। इसी तरह जिला बिलासपुर में 9715, राजनांदगांव में 6607, बस्तर में 3558, सरगुजा में 9302, रायगढ़ में 7775, महासमुंद में 5563, मामले लंबित हैं। सीमांकन के 14,782, कृषि प्रयोजन के लिए भूमि आवंटन के 3626, व्यपवर्तन के 5747, किसी आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को बेचने के 3147, विवादित खाता विभाजन के 9490, बंदोबस्त अभिलेखों में सुधार के 2959, चालू राजस्व वर्ष के भू-अभिलेखों में नामांतरण के 25260, भू-अभिलेख संबंधित कागज में गलत प्रविष्टि के सुधार के 27,617, अनाधिकृत भूमि कब्जा के 8416, भूमि-स्वामी की पुर्नस्थापन के 6392 इसके अलावा अन्य धाराओं के भी हजारों मामले लंबित हैं तथा भूंईया पोर्टल बनाने का उद्देश्य से ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसानों और भू-स्वामियों को परेशान करने के लिये ही बनाया गया है, जहां लगभग 35 प्रतिशत डाटा की गलत एण्ट्री की गयी है। आज ग्रामीण अंचल के किसान व भू-धारक एस.डी.एम. व तहसील कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हो चुके हैं, जिससे किसान एवं भू-धारक आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक पीड़ा भी झेल रहे हैं। शासन ने बहुत सारी सेवाओं को लोक सेवा गारंटी के दायरे में रखते हुए उनके निराकरण के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय कर रखी है, लेकिन सैकड़ों मामलों का समय-सीमा में निराकरण नहीं हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी प्रदेश की राजस्व मामलों के निराकरण में देरी और तहसील कार्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं/ परंतु माननीय न्यायालय की फटकार के बावजूद प्रदेश सरकार एवं राजस्व विभाग उदासीन है, जिसके कारण प्रदेश के किसानों व भू-धारकों में प्रशासन के प्रति काफी रोष व आक्रोश व्याप्त है।

राजस्व मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- यह कहना सही नही है कि राजस्व विभाग की प्रक्रियायें जटिल है तथा राजस्व अभिलेख ऑनलाईन करने के बाद छोटी सी छोटी त्रुटि, चाहे वह विभागीय चुक से हो, उसके सुधार हेतु किसान एवं भू-स्वामी को राजस्व कार्यालयों के वर्षों चक्कर काटना पड़ता है ।

वास्तविकता यह है कि भू-अभिलेखों के त्रुटि सुधार की अधिकारिता छ.ग. भू-राजस्व संहिता की धारा 115 के प्रावधान अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व तहसीलदार को हैं । पूर्व में धारा 115 अंतर्गत त्रुटि सुधार की शक्तियां अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के पास ही थी जिसे इस सरकार द्वारा विकेन्द्रीकृत करते हुए तहसीलदार को भी शक्तियां दी गयी है। तदानुसार ऑनलाइन भुइया एवं ई-कोर्ट में व्यवस्था किया गया है । त्रुटि सुधार संबंधी आवेदन के निराकरण की प्रक्रिया को सरलीकृत कर दिया गया है । भू-अभिलेखों की ऑनलाईन व्यवस्था से डिजिटल हस्ताक्षरित खसरा एवं बी-1 ऑनलाईन उपलब्ध है, जिसे कोई भी व्यक्ति कभी भी, कहीं से भी उसकी प्रति प्राप्त कर सकता है । ऑनलाईन प्रिंट कॉपी में बार कोड की व्यवस्था की गई है, जिससे उस दस्तावेज की सत्यता की जॉच एप्स के माध्यम से कहीं से भी की जा सकती है । कोई भी व्यक्ति किसी भी खसरा नंबर की भूमि के संबंध में समस्त जानकारी ऑनलाईन प्राप्त कर सकता है । पटवारी द्वारा किये गये गिरदावरी उपरांत की गई प्रविष्टि की ऑनलाईन जांच की जा सकती है । पंजीयन के समय गलत प्रविष्टि रोकने तथा अभिलेख दुरूस्ती की प्रक्रिया को सरलीकृत करने के उद्देश्य से पंजीयन कार्यालय एवं तहसील कार्यालय को आपस में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जोड़ा गया है ।

दिनांक 25.02.2025 की स्थिति में पूरे प्रदेश में 1,494,79 राजस्व प्रकरण लंबित हैं, जिनमें से समय सीमा केक अंदर 82,274 व समय सीमा के बाहर 67,205 प्रकरण हैं । वर्तमान में जिला रायपुर में 9,952 राजस्व प्रकरण लंबित हैं, जिनमें से समय सीमा के अंदर 6,085 व समय सीमा के बाहर 3867 प्रकरण हैं । वर्तमान में जिला दुर्ग में 9,674 राजस्व प्रकरण लंबित हैं, जिनमें से समय सीमा के अंदर 5,403 व समय सीमा के बाहर 4,271 प्रकरण है । वर्तमान में जिला बिलासपुर में 7070 राजस्व प्रकरण लंबित हैं, जिनमें से समय सीमा के अंदर 3,970 व समय सीमा के बाहर 3,100 प्रकरण हैं । वर्तमान में जिला राजनांदगांव में 5043 राजस्व प्रकरण लंबित हैं, जिनमें से समय सीमा के अंदर 2,808 व समय सीमा के बाहर 2235 प्रकरण हैं । वर्तमान में जिला बस्तर में 4,515 राजस्व प्रकरण लंबित हैं, जिनमें से समय सीमा के अंदर 3,420 व समय सीमा के बाहर 1,095 प्रकरण हैं । वर्तमान में जिला सरगुजा में 9,560 राजस्व प्रकरण लंबित हैं, जिनमें से समय सीमा के अंदर 4821 व समय सीमा के बाहर 4739 प्रकरण हैं । वर्तमान में जिला रायगढ़ में 6,540 राजस्व प्रकरण लंबित हैं, जिनमें से समय सीमा के अंदर 4,294 व समय सीमा के बाहर 2,246 प्रकरण हैं । वर्तमान में जिला महासमुंद में 6,047 राजस्व प्रकरण लंबित हैं, जिनमें से समय सीमा के अंदर 3163 व समय सीमा के बाहर 2884 प्रकरण हैं ।

पूरे प्रदेश में राजस्व न्यायालय में सीमांकन के कुल 9,080 प्रकरण लंबित हैं, जिनमें से 7,209 प्रकरण समय सीमा के भीतर एवं 1871 प्रकरण समय सीमा के बाहर हैं । राजस्व न्यायालय में कृषि प्रयोजन के लिये भूमि आवंटन के कुल 2060 प्रकरण लंबित हैं, जिनमें से 194 प्रकरण समय सीमा के

भीतर एवं 1,866 प्रकरण समय सीमा के बाहर हैं । राजस्व न्यायालय में व्यपवर्तन के कुल 4,047 प्रकरण लंबित हैं, जिनमें से 3,596 प्रकरण समय सीमा के भीतर एवं 451 प्रकरण समय सीमा के बाहर हैं । राजस्व न्यायालय में आदिवासी भूमि का गैर आदिवासी को विक्रय के कुल 1,873 प्रकरण लंबित हैं, जिनमें से 21 प्रकरण समय सीमा के भीतर एवं 1,852 प्रकरण समय सीमा के बाहर है । राजस्व न्यायालय में विवादित खाता विभाजन के कुल 8,404 प्रकरण लंबित हैं, जिनमें से 4,690 प्रकरण समय सीमा के भीतर एवं 3,714 प्रकरण समय सीमा के बाहर हैं । राजस्व न्यायालय में बंदोबस्त त्रुटि सुधार के कुल 3,059 प्रकरण लंबित हैं, जिनमें से 932 प्रकरण समय सीमा के भीतर एवं 2127 प्रकरण समय सीमा के बाहर हैं । राजस्व न्यायालय में नामांतरण के कुल 25,276 प्रकरण लंबित हैं, जिनमें से 13,619 प्रकरण समय सीमा के भीतर एवं 11657 प्रकरण समय सीमा के बाहर है । राजस्व न्यायालय में अभिलेख त्रुटि सुधार के कुल 10332 प्रकरण लंबित हैं, जिनमें से 3322 प्रकरण समय सीमा के भीतर एवं 7010 प्रकरण समय सीमा के बाहर हैं । राजस्व न्यायालय में अनाधिकृत भूमि कब्जा के कुल 8126 प्रकरण लंबित हैं, जिनमें से 2696 प्रकरण समय सीमा के भीतर एवं 5430 प्रकरण समय सीमा के बाहर हैं । राजस्व न्यायालय में भूमि स्वामी का पुन: स्थापन के कुल 6715 प्रकरण लंबित हैं, जिनमें से 2103 प्रकरण समय सीमा के भीतर एवं 4612 प्रकरण समय सीमा के बाहर है ।

लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए सतत् पर्यवेक्षण किया जा रहा है । राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए राजस्व शिविर का भी आयोजन किया गया है तथा आगे भी यह शिविर जारी रहेगा । लंबित राजस्व प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा जिला कलेक्टर एवं विभागीय सचिव के स्तर पर की जाती है तथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है । यह कहना सही नहीं है कि भुईयां पोर्टल किसानों एवं भूमि स्वामियों को परेशान करने के लिए बनाया गया है व 35 प्रतिशत डाटा की गलत एन्ट्री की गई है । सभी प्रक्रियाएं ऑनलाईन होने से आम जनता को सुविधा प्राप्त हो रही है । भुईयां सॉफ्टवेयर का निर्माण भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुरूप आम जनता की सुविधा के लिए बनाया गया है । लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत कोई भी व्यक्ति समक्ष अधिकारी द्वारा अपने आवेदन का समय सीमा में निराकरण नहीं होने पर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है । इस प्रकार प्रदेश के किसानों व भू-धारकों में प्रशासन के प्रति किसी भी प्रकार का रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर पढ़ा गया है, वह भी समय-सीमा के अंदर है या बाहर है, यह तय नहीं है । इतना लंबा उत्तर है । 3 पेज का पूरा फूल उत्तर है । अध्यक्ष महोदय, उसमें क्या प्रश्न निकालेंगे, उसके लिए समय दीजिएगा । कुल मिलाकर मंत्री जी ने यह स्वीकार तो कर लिया है कि 1,49,479 प्रकरण लंबित हैं । अब यह बताईए कि समय-सीमा के अंदर और समय-सीमा के बाहर से आपका अभिप्राय क्या है ?

श्री टंक राम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रकरणों के लिए निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है । जो अविवादित प्रकरण हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है, उसका निपटारा तीन महीने के अंदर और यदि विवादित प्रकरण है तो उसका निपटारा 6 महीने के अंदर किया जाना है । यह लोक सेवा गारंटी अधिनियम में लाया गया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने लोक सेवा गारंटी अधिनियम को बनाया है तो इनके 11-12 विषय हैं । मैं आपको दिखा देता हूं कि 11 विषय कौन-कौन से हैं ? मंत्री जी, आप मुझे यह बता दीजिए कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम में यदि आपका विभाग ही पालन नहीं कर रहा है तो आपने इन 6 महीने में कितने अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की है, यह बताईए । मैं दूसरा प्रश्न करूंगा ।

श्री टंक राम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, भू राजस्व प्रक्रिया से आम आदमी जुड़ा हुआ है और यह सतत् प्रक्रिया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप घूमाकर उत्तर मत दीजिए । मेरा प्रश्न प्वाइंटेड है और मुझे प्वाइंटेड उत्तर चाहिए । यदि आप कहेंगे कि उत्तर नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे । जब आप बोल रहे हैं कि समय-सीमा के बाहर है तो आप यह बताईए कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के जो बिन्दु हैं, उसमें क्रियान्यन नहीं किया गया तो इन 6 महीने के अंदर किस स्तर के कितने अधिकारियों के ऊपर आपने कार्रवाई की है ? यह छोटा सा प्रश्न है ।

श्री टंक राम वर्मा :- अध्यनक्ष महोदय, इसका क्रियान्वयन और निगरानी समीक्षा सतत् कलेक्टर के द्वारा, संभागायुक्त के द्वारा किया जाता है और तहसील स्तर पर हम लोग भी क्रियान्यन करते हैं । प्रकरण का निपटारा होते जाता है और नये-नये प्रकरण चाहे खरीदी एवं बिक्री के कारण हो, चाहे भौतिक कारण हो, नये-नये प्रकरण में वृद्धि होती जाती है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही प्रश्न है । आप समीक्षा करते हैं, क्या करते हैं, वह आपका विषय है । आप मंत्री हैं, आप तो समीक्षा करेंगे ही । लोक सेवा गारंटी अधिनियम का पालन नहीं हुआ है या लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जितने लंबित विषय हैं, उसमें 6 महीने के अंदर नियम का पालन नहीं करने पर किस स्तर के कितने अधिकारियों के ऊपर आपने कार्रवाई की है? मैंने फिर से प्रश्न को दोहरा दिया । जब तक उत्तर नहीं आएगा, मैं यही प्रश्न करता रहूंगा, फिर दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ूंगा ।

श्री टंकराम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, अभी लंबित प्रकरणों की संख्या बढ़ी है। मैं आपका प्रश्न समझ रहा हूं। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- आप मेरा प्रश्न समझ गये हैं तो उत्तर दे दीजिये।

श्री टंकराम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं वही बता रहा हूं कि इसकी समय-समय पर समीक्षा करते हैं। अभी बजट सत्र के बाद हमारा राजस्व पखवाड़ा चलेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा। इससे पहले प्रश्न में 28 हजार करोड़ रूपये स्वीकृत है और 13 हजार करोड़ रूपये खर्चा है, बाकी बचा है। आपका पखवाड़ा चलेगा या साप्ताहिक चलेगा, मैं उसको पूछ ही नहीं रहा हूं। आपने लोक सेवा गारंटी अधिनियम में जो समय-सीमा तय की है, उसका पालन नहीं होने पर आपने पिछले 6 महीने में किस स्तर के कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है ? मैं उसके बाद दूसरा प्रश्न करूंगा क्योंकि आपका उत्तर तो लंबा है। इसमें दो-चार प्रश्न निकलेंगे। आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिये।

श्री टंकराम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं इसी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। विधान सभा सत्र के बाद राजस्व पखवाड़ा चलेगा। उसमें यदि लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निपटारा नहीं होगा तो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जायेगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैं अब क्या पूछूं ? मैंने जो सवाल नहीं पूछा है, मंत्री जी उसका जवाब दे रहे हैं और मैं जो पूछ रहा हूं, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री टंकराम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं कि अब उसमें कार्रवाई करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप कार्रवाई करेंगे, वह तो बाद की बात है। यह तो कब बबा मरही, तहान कब बरा चुरही वाला किस्सा है।

अध्यक्ष महोदय :- आप अगले प्रश्न में आईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मुझे आपके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। मैं कितना प्रश्न पूछता हूं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मुझे उसका उत्तर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यह जो कार्रवाई करेंगे, वह भविष्य की घटना है। मैं उसे तो पूछ ही नहीं रहा हूं। आपने इसे स्वीकार किया है। इसमें 1 लाख 46 हजार से ज्यादा प्रकरण लंबित हैं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू है। उसका पालन नहीं करने पर आपने प्रदेश भर में पिछले 6 महीने में किस स्तर के किस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की है ?

श्री टंकराम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, इसमें जो धारा दी गयी है, यदि उसके अनुसार समय-सीमा पर प्रकरण का निपटारा नहीं होता है तो जो पीड़ित पक्ष है, वह अपील करेगा तो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, बहुत सुंदर उत्तर है। आप जो बोलने वाले थे, उसे मैं जानता हूं। आम जनता ही सब कार्य करेगी तो शासन-प्रशासन का मतलब ही क्या है ? अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा प्रश्न कर लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप आगे बढ़ जाईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, पहले तो आप यह बताईये कि भुइयां पोर्टल को कौन-सा विभाग संचालित करता है ? दूसरा, यदि भुइयां पोर्टल में त्रुटि दर्ज हो गयी तो उसे कौन सुधारता है और कितने दिनों में सुधारता है ?

श्री टंकराम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, भुइयां पोर्टल को एन.आई.सी. संचालित करता है और इसमें जो त्रुटि होती है, उस त्रुटि को सुधारने के लिये वहां पर नोडल अधिकारी होते हैं, वह नोडल अधिकारी उस त्रुटि को ठीक करते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, आपने एक ही उत्तर दिया है। उसे एन.आई.सी. संचालित करता है, वह तो ठीक है। मैं यह पूछ रहा हूं कि यदि उसमें त्रुटि हो गई तो उसे कितने दिनों में सुधारा जाता हैं और उसे कौन सुधारता है ?

श्री टंकराम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, त्रुटि सुधारने की समय-सीमा वही है, जैसा मैंने पहले 3 महीने और 6 महीने का समय बताया था। यदि कहीं पर नाम में, जाति में...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां विभाग के सचिव महोदय बैठे हैं। आप चिट मंगवा लीजिये। त्रुटि को 7 दिनों के अंदर सुधारना होता है। आप मुझे एक भी ऐसे प्रकरण बता दीजिये जो आवेदन लगने के बाद 7 दिनों के भीतर सुधारे गये ? आप विभागीय सचिव से पूछ लीजिये।

श्री टंकराम वर्मा :- आपके पास यदि कोई विशेष प्रकरण है तो आप मुझे बताईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई विशेष प्रकरण नहीं है। यह तो सामान्य प्रश्न है। आपके भुइयां पोर्टल में 7 दिनों के भीतर त्रुटि को सुधारा ही नहीं जा रहा है और आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपके पास इसका कोई सिस्टम है या नहीं ? क्या इसकी कोई मॉनिटरिंग हो रही है कि इसका पालन किया जा रहा है या नहीं या इसको ठीक किया जा रहा है या नहीं ? भुइयां पोर्टल की त्रुटि को सुधारना तो भगवान भरोसे है।

श्री टंकराम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, त्रुटि को सुधारने का पूरा सिस्टम है। हमारे जो तहसीलदार और एस.डी.एम. हैं, उनके पास त्रुटि सुधार के प्रकरण आते हैं, फिर वहां से संशोधन होता है और सुधार होता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रकरण आते हैं इसलिए तो 1 लाख 46 हजार प्रकरण लंबित हैं। यदि ऐसा उत्तर मिलेगा और कमिटमेंट नहीं दिखेगा तो 2 लाख 46 हजार प्रकरण लंबित हो जायेंगे। मैं जो पूछ रहा हूं, आप उसका एक भी उत्तर नहीं दे रहे हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है। अध्यक्ष महोदय मुझे डांट देते हैं कि आप जोर से बोलते हैं। मुझे आज डांट नहीं सुननी है। मैं आपसे फिर से आग्रह कर रहा हूं। आप कृपया करके मुझे बतायें कि आप कितने दिनों में पोर्टल की त्रुटि को ठीक करते हैं ? जो आवेदन लंबित रहते हैं, उसके लिये आपने क्या कार्रवाई की है ? आप मुझे यह

बताईये कि आपने एन.आई.सी. के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की या अपने नोडल अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की ? मैंने तो आपको अवधि बतायी कि त्रुटि को 7 दिवस के भीतर सुधारना है। एक भी प्रकरण 7 दिनों के भीतर नहीं सुधर रहे हैं। आप इसे बताईये।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, त्रुटि सुधार का नियम वही है कि तहसीलदार, एस.डी.एम. के माध्यम से आता है और एन.आई.सी. में जो नोडल अधिकारी बैठे हैं, वह त्रुटि सुधार करते हैं। इसकी समय-सीमा वही है। 3 महीने की समयावधि है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर 3 महीने के अंदर त्रुटि सुधार की कार्यवाही नहीं हुई है तो आपने क्या कार्यवाही की है ? आप एकाध कार्यवाही बता दीजिए कि मैंने उसमें कार्यवाही की है। 3 महीने से ज्यादा अवधि में समीक्षा में बात आई है तो किसी भी जिले के एन.आई.सी. में भुईया पोर्टल के ..। आपके ही बलौदाबाजार जिले में बहुत राजस्व के मामले लंबित है। बलौदाबाजार जिले में का बता दीजिए कि आपने उसमें कितनी कार्यवाही की है ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि पीड़ित पक्ष का आवेदन आएगा कि हमारा प्रकरण का समय-सीमा के अंदर निपटारा नहीं हुआ तो फिर उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भईया, ठीक है। भगवान मालिक है।

मैं इसमें दूसरा प्रश्न कर लेता हूँ। यह आपके तहसीलदार या एस.डी.एम. त्रुटि सुधार करते हैं। आपने अपने ध्यानाकर्षण के उत्तर में कहा है कि हमने तहसीलदार को यह अधिकार प्रत्यारोपित किये हैं मैंने उसमें प्रश्न किया था। यदि आपको याद होगा ? अभी पटवारी लोगों की आपके विभाग में क्या भूमिका है उनको क्या अधिकार प्राप्त हैं ? आपने तहसीलदार को जितना अधिकार दिया तो पटवारियों को क्या-क्या अधिकार प्राप्त हैं ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय,पटवारी जो है पूरे भू-अभिलेख का संरक्षण करता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह तो ऑनलाईन हो गया है। आपके हिसाब से तो वह 100 प्रतिशत ऑनलाईन हो गया। यह तो ऑनलाईन
हो गया है?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि यह ऑनलाईन
हो गया है तो पटवारी के पास क्या अधिकार हैं?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पटवारी प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। जैसे तहसीलदार, आर.आई. कहीं की भी जांच रिपोर्ट मंगाते हैं तो प्रतिवेदन तो पटवारी ही बनाएगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग में ऑनलाईन रिकॉर्ड है। आप भी किसान हैं। अगर वहां ऑनलाईन रिकॉर्ड है तो वहां पर पटवारी क्या करता है ? यदि कोई रिपोर्ट बनाना है तो मैं भी बटन दबाकर, किसी भी च्वाईस सेन्टर से ले लूंगा।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय,नहीं-नहीं। उसमें जो भी सुधार या कोई भी कार्य होगा। उसका प्रतिवेदन पटवारी ही बनाकर देता है तब तो उसमें आगे सुधार कार्य होगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा, आप यह बताईये। आपके उत्तर से तो मैं नहीं पूर पा रहा हूँ। आप यह समझ रहे हैं न ? भगवान करें। आप मुझे यह बता दीजिए कि उच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद, यदि आपको मालूम हो उच्च न्यायालय की टिप्पणी हुई तो राजस्व विभाग लंबित प्रकरण को कम करने के लिए, समय में निपटाने के लिए आपने क्या-क्या कदम उठाये हैं, आप यह बता दीजिए ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए तो सबसे पहले यह है कि जो प्रदेश में राजस्व के प्रकरण लंबित है, उनको निपटारा करने के लिए सबसे बड़ा आर.आई. लेवल, तहसील लेवल और जिला स्तर पर शिविर का आयोजन किया है और जो पिछले वर्ष शिविर का आयोजन किया था, उनका परिणाम अच्छा आया। उसमें बहुत से लंबित प्रकरणों का निपटारा हुआ। हमने पूरे प्रदेश में राजस्व पखवाड़ा का आयोजन किया। उसमें बहुत से लंबित प्रकरणों का निपटारा हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, ठीक है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उनसे यह पूछा।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, अपना उत्तर बता रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर वह उत्तर बता रहे हैं तो इस पर मैं क्या बोलूं। मैंने, आपसे यह पूछा है कि आपने इस पर क्या-क्या कदम उठायें ? माने आप इस उत्तर को पढ़ेंगे तो प्रदेश में राजस्व प्रकरण की बहुत भयावह स्थिति है। जो राजस्व के प्रकरण समय सीमा में लंबित हैं और जो समय-सीमा के बाहर लंबित हैं। राजस्व के लंबित मामलों में कोई भी कार्ययोजना नहीं है, यह शून्य प्रतिशत है। यदि इसकी कार्ययोजना होती तो माननीय मंत्री जी यह बताते। प्रदेश में राजस्व मामलों के लंबित होने पर आर.आई. का शिविर का आयोजन हुआ तो यह शिविर बढ़ क्यों रहे हैं ? उसके लिए क्या कार्ययोजना है ? इन्होंने अभी तक एक भी कार्यवाही नहीं की? इसमें सारी जिम्मेदारी किसानों के ऊपर है या भू-धारक के ऊपर है कि यदि वह अपना आवेदन देंगे तो हम उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे ? यदि वह आवेदन नहीं देंगे तो हम उनका निराकरण नहीं करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ कि भुईंया पोर्टल में आवेदन करने के बाद, 3-4 महीने तक मामले नहीं सुधरते। दूसरा, आप प्रदेश में शिविर लगा रहे हैं तो आप यह सुन लीजिए। यदि यह एन.आई.सी. में संचालित हैं तो जितने भी भू -माफिया है तो वह रिकॉर्ड को एन.आई.सी. से मिलकर गड़बड़ करवाते हैं। जो आम आदमी है उसको ठीक करवाने के लिए घूमता है, जिसको एन.आई.सी. ठीक नहीं करता। यदि सॉफ्टवेयर

है तो आप अपने से पैरेंटल डिपार्टमेंट बनिए, आप उसको ठीक करिये। आपने उसे एन.आई.सी. को क्यों दे कर रखा है। उसको पटवारी, आर.आई. या तहसीलदार ठीक करें। भुईंया पोर्टल को एन.आई.सी. क्यों संचालित करेगी ? यह आपके विभाग का पोर्टल है। क्या आप इस पर विचार करेंगे कि यह व्यवहारिक दिक्कत आ रही है कि पोर्टल राजस्व विभाग संचालित करेगा, इस पर आप विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, कुल मिलाकर माननीय अजय जी का विषय यह है कि पूरे प्रदेश में जितने भी मामले हैं, उसमें समय अवधि समाप्त होने के बाद भी कार्यवाही नहीं हुई है। इनकी चिंता यह है कि पूरे जिले में सभी जगहों में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या यह सुनिश्चित किया जाये कि अब आने वाले 3, 4, 6 महीनों के अंदर यह सुनिश्चित किया जाये कि पूरे प्रदेश में नीचे स्तर से लेकर ऊपर तक शिविर लगाकर समयबद्ध के साथ-साथ इन सभी प्रकरणों का, आदिवासी और गैर आदिवासी सभी के भूमि के सारे मामले का निराकरण हो। सब तो नहीं, मगर ज्यादा से ज्यादा जो प्रतिशत आपने कहा है, क्या उसको पूरा करने के लिए कोई कार्ययोजना में विभाग काम करेगा? यह बता दें तो वह संतुष्ट हो जायेंगे।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वाकई में चिंता का विषय है और लंबित प्रकरण के निपटारे के लिए ठोस कार्रवाई करेंगे और नई नीति बनायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत अच्छा। माननीय मंत्री जी, ठोस कार्रवाई करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप सुधार कर रहे हैं तो आप यह बता दीजिए कि भूईंया पोर्टल को आप संचालित करेंगे या एन.आई.सी. करेगी ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें भी विचार करके निर्णय लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, ठोस कार्रवाई करने के लिए बोल दिये हैं, इससे ज्यादा ठोस और क्या जवाब होगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- इतना लंबा उत्तर है कि मैं उसको देखा नहीं हूं। पूरा पढ़ नहीं पाया, इतना ठोस है।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 1,49,479 प्रकरण लंबित हैं। लोक सेवा गारंटी में अगर समय-सीमा के अंदर प्रकरण का निराकरण नहीं होता है तो किसान को तहसीलदार के पास अपील करने की आवश्यकता है। अगर वह किसान अपील करता है, क्या उसके बाद आपने कोई कार्रवाई की ? मैं आपको उदाहरण दूंगा।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रकरण अभी तक आया नहीं है, यदि ऐसा कुछ होगा तो मेरे को बताईयेगा, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से देखूंगा।

श्री उमेश पटेल :- अगर आप चाहें तो मैं आपको अभी उदाहरण दे देता हूं।

श्री टंकराम वर्मा :- जी, आप जानकारी दे दीजियेगा।

श्री उमेश पटेल :- क्या आप अभी चाहते हैं ? मैं अभी बोल दूं ?

श्री टंकराम वर्मा :- जो प्रकरण आपके पास आया है, उसकी मुझको जानकारी दे दीजियेगा। मैं दिखवा लूंगा।

श्री उमेश पटेल :- मैं अभी बोल देता हूं न, उसमें क्या है। पुसौर गांव का मामला है। उसने तहसीलदार के पास अपील किया है कि समय-सीमा के अंदर उसके भूईंया रिकार्ड में सुधार नहीं हुआ है और यह अपील किये हुए उसको एक साल हो गये हैं, एक साल के बाद भी किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। आप अभी माननीय सदस्य को जवाब दे रहे थे कि अपील करेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। एक भी कार्रवाई नहीं हो रही है। वही अपील एक साल से ऊपर लंबित हो गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माननीय मंत्री जी को कड़ा निर्देश चाहता हूं कि इस तरह के लंबित मामले को वह तुरंत के तुरंत हल करें और उसमें कार्रवाई करें। क्या आप उन पर कार्रवाई करेंगे ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भयावह स्थिति है, मैं आपको बता रहा हूं। यह कल का मामला है। अकलतरा में एक व्यक्ति तहसील के 02 साल से चक्कर लगा रहा था, उसने खुदखुशी करने की कोशिश की। यह पत्रिका पेपर की न्यूज है, अगर आप चाहें तो मैं पटल पर रख सकता हूं। उसको तहसील कार्यालय के 02 साल चक्कर लगाते हो गये, उसके पिताजी की मृत्यु के बाद जब पावती नहीं कटी तो उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। क्या आप इस प्रकरण को भी दिखवायेंगे और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हां, जो उमेश पटेल जी ने बोला, उसमें भी कार्रवाई करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते, आप इसी में प्रश्न करिये।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते (प्रतापपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में 1,49,479 मामले हैं, उसमें मेरी विधान सभा प्रतापपुर में 324 और वाड्रफनगर में 465 मामले लंबित हैं। मैं एक अधिवक्ता का कार्य करती थी। आज जनता का जो सबसे मार्मिक विषय है जिससे जनता प्रभावित है, वह राजस्व मामले हैं। क्योंकि जब हम लोग कोर्ट में सुबह से बैठते हैं, दूर-दूर के गावों से लोग आते हैं और वह पूरे समय इंतजार में रहते हैं कि हमारे मामलों का निपटारा होगा, हमारे आवेदन पर सुनवाई होगी। लेकिन सबसे ज्यादा दु:ख का विषय यह है कि वहां पर लोगों के आवेदन लंबित रह जाते हैं, लोग आवेदन लगाते हैं, उनका निराकरण नहीं होता है। आज मैं सदन के माध्यम से इस विषय में माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहूंगी कि जो भी आवेदन देते हैं, गांव का एक ग्रामीण पूरे समय कोर्ट में अपनी सुनवाई के लिए बैठा रह जाता है। उसके लिए अगर आप कुछ बेहतर कर सकते हैं तो करें।

क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ जनता को न्यायालय में होती है, राजस्व मामलों में होती है। माननीय मंत्री जी, इस पर आप जरूर अच्छा कार्य करें।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले भी कहा कि वाकई में राजस्व मामलों की संख्या चिंताजनक है। हमारे राजस्व विभाग के अमले राजस्व विभाग का काम करते ही हैं, साथ में जो अभी पंचायती राज एवं नगरीय निकाय के चुनाव हुए, उसमें भी कार्य किये हैं। विधान सभा सत्र के बाद हमने तय किया है कि पूरे प्रदेश में अप्रैल में राजस्व पखवाड़ा का आयोजन करेंगे। इसके बाद यदि निराकरण नहीं होता है तो वाकई में उसमें कठोरता से कार्रवाई करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- देखिए मंत्री जी बहुत स्पष्ट रूप से सभी सदस्यों की चिंता है और आपने कहा कि हालत चिंताजनक है तो वेंटिलेटर पर जाने के पहले आप ठीक कर लेंगे क्या ?

श्री टंक राम वर्मा :- जी-जी ।

अध्यक्ष महोदय :- यह पूरे सदन का विचार है, यह चिंता करने की जवाबदारी आपकी है । ध्यानाकर्षण श्री ओंकार साहू जी ।

(2) जिला चिकित्सालय धमतरी में व्याप्त अव्यवस्था.

श्री ओंकार साहू (धमतरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है - जिला चिकित्सालय धमतरी में आए दिन मरीज़ों की शिकायत रहती है कि डॉक्टर समय पर OPD में नहीं होते । कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारियों जैसे कलेक्टर ने भी इस संबंध में जिला चिकित्सालय में पदस्थ डाक्टरों को समय पर आने निर्देशित किया है किंतु कुछ डॉक्टर नहीं आ रहे हैं । धमतरी जिला चिकित्सालय में प्रतिदिन मरीज़ की संख्या में वृद्धि हो रही है किंतु सुविधा प्रतिदिन कम होती जा रही है जिसके कारण गरीब असहाय वर्ग के लोगों को निजी अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ रहा है । कई लोग जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं उनकी जान तक चली जाती है । अभी-अभी लगातार कुछ दिनों से एक शिकायत आम हो गई है कि कुछ अस्पताल के कर्मचारियों की निजी अस्पतालों में मिलीभगत है । डिलीवरी एवं अन्य केसों में अस्पताल के कुछ कर्मचारी द्वारा सुझाव दिया जाता है कि डॉक्टर की कमी है, यहां इलाज की सुविधा नहीं है । अगर आप बेहतर इलाज चाहते हैं तो आपको धमतरी के किसी निजी अस्पताल में जाना होगा एवं वही कर्मचारी निजी अस्पतालों में मरीज़ों को भेज देते हैं। अभी anesthesia के डॉक्टर नहीं हैं, surgery में समस्या है अनेक तरीके की कमियां बताकर मरीज़ों को private हॉस्पिटल में भेजा जाता है । जिससे मरीज़ को आर्थिक नुकसान सहना पड़ रहा है । जिला हॉस्पिटल धमतरी में आए दिन मशीन ख़राब रहती है । कभी एक एक्स-रे मशीन तो कभी कभी सोनोग्राफी मशीन अगर ठीक है तो सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टर

उपस्थित नहीं हैं । मरीज़ को बेहतर एवं संतुलित आहार, पौष्टिक आहार भी प्रदान नहीं किया जा रहा है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जिले में नहीं मिल पाने के कारण जिले के आम जनता में शासन प्रशासन के विरुद्ध आक्रोश व्याप्त है ।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही नहीं है कि जिला चिकित्सालय धमतरी में आए दिन मरीज़ों की शिकायत रहती है कि डॉक्टर समय पर OPD में नहीं होते, कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों जैसे कलेक्टर ने भी इस संबंध में जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टरों को समय पर आने निर्देशित किया, किंतु डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, सत्य यह है कि जिला चिकित्सालय धमतरी में सभी चिकित्सक अपने निर्धारित समय पर उपस्थित होकर कार्य संपादित कर रहे हैं ।

यह सही है कि धमतरी जिला चिकित्सालय में विगत् 2-3 वर्षों से मरीज़ों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है इस वित्तीय वर्ष में जनवरी 2025 तक 1,50,679 मरीज़ बाह्य रोगी एवं 21,619 अंत:रोगी मरीज़ के रूप में अपना इलाज करा चुके हैं। जनवरी 2025 तक जिला अस्पताल धमतरी में 2921 मेजर ऑपरेशन एवं 3246 माईनर ऑपरेशन संपादित किए जा चुके हैं । यह कहना सही नहीं है कि जिला चिकित्सालय धमतरी में सुविधा प्रतिदिन कम होती जा रही है, अपितु सत्य यह है कि जिला चिकित्सालय धमतरी जिले के पड़ोसी जिलों कांकेर, बालोद, गरियाबंद एवं दुर्ग से उपचार एवं प्रसव हेतु जिला अस्पताल धमतरी में मरीज आते हैं। सुरक्षित प्रसव (सामान्य एवं सिजेरियन प्रसव) की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। जिला अस्पताल धमतरी में कई जटिल बीमारियों से ग्रसित गर्भवतियों का ईलाज सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इससे क्षेत्र के आमजनों में जिला चिकित्सालय धमतरी पर भरोसा बढ़ा है। जिला चिकित्सालय धमतरी में दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से 25 फरवरी, 2025 तक 1,217 सिजेरियन प्रसव एवं 2,315 सामान्य प्रसव हुये हैं, कुल प्रसव संख्या 3,532 है।

यह सही नहीं है कि गरीब असहाय वर्ग के लोगों को निजी हॉस्पिटलों की ओर रूख करना पड़ रहा है कई लोग जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे होते हैं उनकी जान तक चली जाती है अपितु सत्य यह है कि धमतरी जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना अंतर्गत जिनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदाय की जाती है इस वित्तीय वर्ष में 11,211 मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है।

यह कहना सही नहीं है कि कुछ अस्पताल के कर्मचारी की निजी अस्पतालों से मिली-भगत है। डिलीवरी, सिजेरियन एवं अन्य केसों में अस्पताल के कुछ कर्मचारियों के द्वारा यह सुझाव दिया जाता है कि यहां डॉक्टर की कमी है, यहां इलाज की सुविधा नहीं है। आप बेहतर इलाज चाहते हैं तो आपको धमतरी के किसी निजी अस्पताल में जाना होगा और वही कर्मचारी निजी अस्पताल में मरीजों को भेज देते हैं। कभी एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं है, सर्जरी में समस्या है। अनेक तरीके की कमियां बताकर

मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में भेजा जाता है। सत्य यह है कि इस तरह की कोई शिकायत अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा डिलीवरी एवं अन्य सर्जरी के मरीजों को निजी अस्पतालों में भेजने के संबंध में प्राप्त नहीं हुई है। जिला चिकित्सालय, धमतरी में 02 स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं 02 निश्चेतना विशेषज्ञ कार्यरत हैं, उनके द्वारा निरंतर सिजेरियन प्रसव एवं अन्य शल्य क्रियाएं संपादित किये जा रहे हैं।

यह कहना सही नहीं है कि जिला हॉस्पिटल धमतरी में आए दिन मशीन खराब रहती है। कभी एक्स- रे मशीन तो कभी सोनोग्राफी मशीन। अगर ठीक है तो सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टर उपस्थित नहीं हैं। सही यह है कि जिला अस्पताल में एक्स-रे मशीन, सी.टी. स्केन तथा सोनोग्राफी मशीन चालू अवस्था में हैं तथा मरीजों को निरंतर सेवायें दी जा रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप इस वित्तीय वर्ष में जिला धमतरी में 12,090 एक्स-रे, 2,374 गर्भवती महिलाओं का सोनोग्राफी, 549 मरीजों का अन्य सोनोग्राफी, 808 सी.टी. स्केन तथा 1,65,960 मरीजों को पैथालॉजी जांच की सुविधायें प्रदान की गई हैं।

यह कहना सही नहीं है कि मरीज को बेहतर एंव संतुलित आहार, पौष्टिक आहार भी प्रदान नहीं किया जा रहा है। सही यह है जिला अस्पताल धमतरी में भर्ती मरीजों को शासन द्वारा निर्धारित मेनू के अनुसार स्वादिष्ट एवं पौष्टिक आहार प्रदाय किया जा रहा है। प्रदायित भोजन की गुणवत्ता की जांच हेतु एक चिकित्सक को नोडल अधिकारी बनाकर वार्ड तथा प्रभारी नर्सिंग स्टॉफ का रोस्टर बनाकर भोजन की गुणवत्ता की प्रतिदिन जांच का दायित्व सौंपा गया है, उनके द्वारा निरंतर भोजन की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। पूर्व में जिला अस्पताल में मरीजों को दिये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता खराब पाये जाने पर उक्त संस्था की निविदा निरस्त कर समान दर वाली दूसरी संस्था को भोजन प्रदायगी का कार्य नियमानुसार सौंपा गया है। अतः धमतरी जिला अस्पताल में मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण जिले की आम जनता में किसी भी प्रकार का आक्रोश नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- ओंकार जी, पूछिए।

श्री ओंकार साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी मंत्री महोदय द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया गया, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। अभी जो ये जवाब दिया गया है, मंत्री जी, आप ये बताइए कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है क्या?

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- हां, निश्चित रूप से वहां बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है। बायोमेट्रिक के अलावा फिजिकल अटेंडेंस भी हम करवाते हैं, उसकी भी व्यवस्था है।

श्री ओंकार साहू :- नहीं, ये गलत है, क्योंकि वहां बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम नहीं है। आपने कहा है कि जिला चिकित्सालय, धमतरी पर भरोसा बढ़ा है, चलिए ठीक है। क्योंकि विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि ओ.पी.डी. में वर्ष 2022-23 में 1,64,112 मरीज आए हैं और वर्ष 2023-24 में 2,21,422, लेकिन अभी हमारे पास वर्ष 2024-25 का जवाब है। अप्रैल, 2024 से जनवरी तक का है। इसमें 1,50,680 आया है। आप बताइए कि अगर मान लीजिए कि 1 साल पूरा होने पर अभी दो महीना बचा

है, इसमें लगभग 50,000 की कमी आई है। ये कमी क्यों आयी है? दूसरी आई. पी.डी. है। आई.पी.डी. भी वैसी है कि आज दिनांक तक 5,000 मरीजों की कमी पायी गयी है तो इसका भी आपको जवाब विभाग से ले लीजिए। लेकिन जो मरीज घट रहे हैं, इसके लिए चिंता है, क्योंकि इसमें आप सब जानते हैं कि आपके द्वारा जवाब दिया गया है कि धमतरी जिला नहीं, इससे लगा हुआ आपका गरियाबंद जिला, दुर्ग जिला, बालोद जिला, कांकेर जिला में यहां सब गरीब परिवार के मरीज जाते हैं तो इसके लिए आपको चिंता करनी है। एक और है कि आपने जवाब दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके द्वारा सदन से अवगत कराना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी सुविधा की बात कर रहे हैं। सुविधा के विस्तार के लिए मेरे द्वारा दिनांक 26/02/2024 को पत्र क्रमांक 51 के द्वारा धमतरी जिला चिकित्सालय के लिए मातृ शिशु अस्पताल, जोकि 100 बिस्तर के लिए और दूसरा जिला अस्पताल में सर्वसुविधायुक्त दो मेजर ऑपरेशन थिएटर के लिए और तीसरा औषधि स्टोरेज के लिए नवीन भवन के लिए अतिरिक्त मांग की गयी थी । चौथी मांग आधुनिक पोस्टमार्टम कक्ष का निर्माण एवं 4 नए शव फ्रीज़र की उपलब्धता । पांचवी मांग मोतियाबिंद सर्जरी के लिए पृथक से एक ऑपरेशन थिएटर एवं चार बेड का पृथक वार्ड निर्माण । छठवीं मांग एमआरआई मशीन की स्थापना एवं नियमित रेडियोग्राफर एवं रेडियोलॉजिस्ट की भर्ती । लेकिन आपके द्वारा पहला नम्बर, दूसरा नम्बर, चौथा नम्बर और पांचवे नम्बर को अनुपूरक बजट में लाने की बात कही थी, क्या यह हो गया है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने जवाब में भी माननीय सदस्य को बताया कि इनके द्वारा जिस बात की चिंता की गई थी । जैसे कि भोजन की गुणवत्ता की बात की गई थी तो भोजन की गुणवत्ता के लिए हमने चेंज कर दिया है । दूसरा जो इनके द्वारा सिजेरियन/ऑपरेशन न होने की बात इनके द्वारा कही गई थी तो मैंने आपको डाटा सहित बताया कि इस वर्ष 10 महीने में धमतरी जैसे जिले में कुल 3532 प्रसव हुए हैं, मुझे लगता है कि यह कोई साधारण बात नहीं है । प्रदेश के बड़े से बड़े हॉस्पीटल में इतनी बड़ी संख्या में प्रसव नहीं हो पाते हैं । यह बताता है कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं । मेजर और माइनर ऑपरेशन में भी बढ़ा है, 1217 सिजेरियन भी किया है । साथ ही साथ ओपीडी की बात है, अभी दो महीने बचे हैं और 1 लाख 90 हजार ओपीडी रहने की संभावना है । साथ ही साथ आपने वहां डॉक्टर्स की कमी की बात की थी तो वहां दो एनेस्थीसिया और दो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और वहां डॉक्टर्स की पर्याप्त पोस्टिंग भी है। इस प्रकार वहां कोई दिक्कत नहीं है । आपने ऑपथेल्मिक और ऑपरेशन थियेटर की बात कही है, आपकी चिंता जायज है और हम लोग उस पर वर्क भी कर रहे हैं सीएमपीएचटीएफ से कुछ राशि स्वीकृत भी की गई है । निश्चित रूप से उसको हम कर रहे हैं ।

श्री अजय चनद्राकर (कुरूद) :- अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए एक छोटा प्रश्न कर लीजिए ।

श्री अजय चनद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, धमतरी जिला चिकित्सालय की अव्यवस्था पर प्रश्न है । माननीय मंत्री जी बिल्डिंग के खराब होने को आप अव्यवस्था मानते हैं या नहीं मानते ? यदि वह भवन जर्जर है, खराब है और आप उसे अव्यवस्था मानते हैं तो उसे ठीक कराने के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं ? साथ में निरीक्षण करेंगे या आप देख चुके हैं और उसको अव्यवस्था नहीं मानते ? यह बता दीजिए ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं और उसी जिले से आते हैं । मैं खुद वहां गया था तो वहां भवन की हालत वाकई में जर्जर है । उसके लिए मैंने सीएमपीएचटीएफ से पहले ही निर्देशित कर दिया है कि उसको ठीक करेंगे । चूंकि भवन एक साल में तो जर्जर हुआ नहीं, काफी लम्बे समय से जर्जर हुआ होगा । मैं इस पर चिंता कर रहा हूं और आप बोलेंगे तो हम साथ में चलेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप जो अवधि बता रहे हैं, ठीक करेंगे । उसके क्रियान्वयन की कोई अवधि आप बता दीजिए कि मैं इतने दिन में क्रियान्वित करवा दूंगा ? आप बोल रहे हैं कि आपने देखा है और आपने निर्देश दिया है ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- हां । लेकिन समय सीमा तो एकदम बताया जाना संभव नहीं होता है परंतु हमने उस ओर चिंता की है, प्रक्रिया की है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता रहा हूं कि वहां शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं था तो ऑन द स्पॉट, मैंने हॉस्पीटल से निकलने के पहले नियुक्ति पत्र देकर डॉक्टर का अपाइंटमेंट किया ।

श्री अजय चनद्राकर :- माननीय मंत्री जी, हम लोग अभी भवन की बात कर रहे हैं ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- भवन तो....।

श्री अजय चनद्राकर :- सुन लीजिए । छोटे प्रश्न का निर्देश हुआ है । आपने देखा है, आपने स्वीकार किया है, आपने निर्देश दिया है, बताना संभव नहीं है तो फिर आपके सारे कथन का कोई अर्थ नहीं है । माननीय मंत्री जी यदि सदन में बोल रहे हैं तो उनके कथन का कोई अर्थ निकले कि हां साहब साल भर में, 6 महीने में नहीं करवा सकते तो दो साल में ठीक हो जाएगा । जब आप स्वीकार कर चुके कि हालत खराब है ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- मैंने भवन की हालत स्वीकार की क्योंकि मैं खुद दौरे पर गया था । पेपर में आया भी होगा कि वहां पर पानी टपक रहा था । उसके लिए हमने निर्देशित किया है और यह भवन एक साल में तो जर्जर हुआ नहीं है । वहां जगह की कमी है, नहीं तो हम संबंधित कलेक्टर को जगह खोजने के लिए निर्देशित किया है । जगह की उपलब्धता होगी तो आने वाले समय में 200 बिस्तर का नया हॉस्पीटल भी हम बनाएंगे ।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन हे।

अध्यक्ष महोदय :- आप धमतरी में कहां आ गए ? यह धमतरी का प्रश्न है।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहत हौं कि पूरा प्रदेश से जो भी मरीज रेफर होथे, हमर विधान सभा से प्रदेश मुख्यालय में आ थे, मंत्री जी आप जा के देखव, जो मेकाहारा और डी.के.एस. हॉस्पिटल हे, वहां मरीज मन अइसे पड़े रथे, वहां जा के देखव तो तरस आ थे, जब हमन अतेक कन पईसा प्राईवेट हॉस्पिटल ला देत हन तो हमर जो खुद के सरकारी संस्था हे, हमन ला दे में का दिक्कत हे ? वहां टी.व्ही. नई लगे हे, वहां पंखा नई लगे हे, आप वहां जा के देखव आदमी मन जानवर के तरह रथे। आपसे निवेदन हे, आप संवेदनशील मंत्री ओ, वहां गरीब आदमी मन जा के लावारिस जैसे पड़े रथे, आप वहां अधिक से अधिक सुविधा बनाय के कोशिश करो, मोर आपसे निवेदन हे।

अध्यक्ष महोदय :- नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं।

समय :
12.46 बजे

नियम 267 "क" के अंतर्गत विषय

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जाएगा :-

(1) श्री अजय चंद्राकर
(2) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल
(3) श्रीमती अनिला भेंडिया
(4) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते
(5) श्री कुंवर सिंह निषाद

समय :
12.46 बजे

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तुती एवं पारण

सभापति (श्री विक्रम उसेंडी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 2025 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प क्र.	**सदस्य का नाम**	**समय**
(क्रमांक - 07)	श्री धर्मजीत सिंह	30 मिनट
(क्रमांक - 06)	श्री रिकेश सेन	30 मिनट
(क्रमांक - 04)	श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल	30 मिनट

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि :- सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। माननीय सदस्य श्री धरमलाल कौशिक, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ करेंगे।

समय :

12.49 बजे **माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा**

"माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं।"

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- जी बोलिए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके साथ हुई कक्ष में बातचीत का उल्लेख नहीं करना चाहता, क्योंकि वैसी परंपरा नहीं है कि कक्ष की बात का उल्लेख करें। आप अभिभाषण के पृष्ठ 14 को देखेंगे तो एक शब्द उल्लेखित है, मेरी सरकार 18 स्थानीय भाषाओं में बच्चों को शिक्षा दे रही है। छत्तीसगढ़ में मैं भी शिक्षा मंत्री रहा हूं, ये ऐसी कौन सी 18 भाषाएं हैं जिसमें सरकार शिक्षा दे रही है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यदि इस तरह की, यदि ये टंकण त्रुटि हो या किसी तरह की त्रुटि हो या ये सत्य है तो यह स्थापित हो जाए तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। मेरे हिसाब से महामहिम के द्वारा ऐसा कथन नहीं कहलवाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली। आपकी बात आ गयी न ?

श्री अजय चंद्राकर :- आपकी कोई ?

अध्यक्ष महोदय :- मैं व्यवस्था दे देता हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें व्यवस्था का प्रश्न तो मांगा नहीं है।

व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय :- व्यवस्था इसलिए कि राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर आपका प्रश्न है। इसका निराकरण माननीय मुख्यमंत्री जी अंतिम रूप से जवाब में करेंगे। मुख्यमंत्री जी स्वयं यहां उपस्थित हैं, जब उनका उत्तर आएगा तो इस विषय पर प्रकाश डालेंगे और बातों को स्पष्ट करेंगे, जो आपने अभी ध्यानाकर्षित किया है।

श्री अजय चंद्राकर :- धन्यवाद।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए गर्व महसूस कर रहा हूं और माननीय राज्यपाल महोदय के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा जो अभिभाषण प्रस्तुत किया गया है, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो कार्य किये गये हैं और जो कार्य होने वाले हैं, उन सारी बातों का समावेश माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिभाषण में है। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता व हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर, सन् 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। इसके कारण से हम इस छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। मैं सबसे पहले इसके लिए सभी सदस्यों और प्रदेश की जनता को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। इस अवसर पर मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्मरण करना चाहता हूं। (मेजों की थपथपाहट) क्योंकि यह तभी संभव हुआ है, जब उन्होंने बड़ा दिल रखकर इस छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, जबकि उस समय की जो तत्कालीन परिस्थिति थी, उसमें जब हम मध्य प्रदेश में थे और मध्य प्रदेश में रहते हुए यदि छत्तीसगढ़ अलग राज्य के रूप में पृथक किया जायेगा तो यहां पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, यह जानते हुए भी हमारे पुरोधा व तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी ने इस छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। आज हम इस बात को देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करने के बाद 13 दिसम्बर, 2023 को हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णु देव साय जी के

नेतृत्व में इस छत्तीसगढ़ के सुशासन का पूर्ण रूप से सूर्योदय होने लगा है। प्रदेश में ''सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास'' इस ध्येय वाक्य को लेकर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नरेन्द्र मोदी जी की जो चुनाव की गारंटी है, वह गारंटी चुनाव जीतने का कोई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि वह गरीबों के विश्वास की गारंटी है कि इस देश के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी के ऊपर विश्वास किया और उनकी गारंटी पर विश्वास करने के बाद इस छत्तीसगढ़ राज्य में लोगों ने हमें जनमत दिया और जनमत देने के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया। हमारे मुख्यमंत्री जी के शपथ लेने के बाद विष्णु देव साय जी की सरकार में आज मैं यह कह सकता हूं कि यदि हम उनके सवा साल के कार्यकाल को देखें तो जिस प्रकार से नरेन्द्र मोदी जी ने अपनी गारंटी को लेकर कार्य-योजना बनाई और कार्य-योजना बनाकर कार्य प्रारंभ किया और कार्य प्रारंभ करने के बाद केवल कार्य ही प्रारंभ नहीं हुआ, बल्कि यहां की गरीब जनता के दिलों में भी जगह बनाने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णु देव साय जी के द्वारा किया गया है। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं यह कहता हूं कि यदि हम इस सरकार को ग्राफ की दृष्टि से देखेंगे तो हम लगातार ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं और ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए सफलतापूर्वक पहले हमारी डबल इंजन की सरकार बनी और अब इस प्रदेश में हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही है। बड़ी मात्रा में चाहे नगरीय-निकाय में हो, चाहे स्थानीय-निकाय पंचायत में हो, हमारे जन प्रतिनिधियों को जनता का ऐतिहासिक जन समर्थन हासिल हुआ है और हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। मैं इसके लिए भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

समय :
12.54 बजे

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं कि गरीबों के जीवन में बदलाव आया है। चाहे हम उनकी आर्थिक स्थिति की बात करें, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति की बात करें और उसके साथ जिस प्रकार से उनकी सोच में जो बदलाव आये हैं, उससे छत्तीसगढ़ प्रदेश विकास के दृष्टिकोण से लगातार आगे बढ़ रहा है। चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो। पहले की जो सरकारें बनती थीं या सरकारें बनाई जाती थीं, उसमें जनता से वायदे भी किये जाते थे और जनता को बड़े-बड़े सपने भी दिखाये जाते थे। लेकिन उसका क्या हश्र होता था ? उनके विश्वास को तोड़ने का काम होता था। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद लगातार जनता के विश्वास को कायम रखा है। मुझे याद है कि अटल जी की सरकार चल रही थी और एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी। उस समय अटल जी ने कहा था कि आज हमारी संख्या जरूर कम है और लोग हमारी हंसी

उड़ा रहे हैं कि एक वोट से हमारी सरकार चली गई। लेकिन मैं उस दिन के बारे में कहना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार बनेगी और हमारी सरकार चलेगी तो जो आज बी.जे.पी. के ऊपर हंसी उड़ा रहे हैं शायद उस दिन कांग्रेस पार्टी के ऊपर हंसी उड़ायेंगे। मैं आज इस बात को कहना चाहता हूं जिस प्रकार आज यहां जन समर्थन मिला है, निश्चित रूप से यदि हम मोदी जी की बात करेंगे तो ना केवल दिल्ली में, केन्द्र में हमारी तीसरी बार सरकार चल रही है, बल्कि प्रदेश के अनेक हिस्सों में सरकार बनाने में सफल हुई है। जहां एक वोट से हमारी सरकार गिरी थी वहीं पूरे देश की जनता का विश्वास हासिल किया है। इसी प्रकार से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास नया दौर शुरू हुआ है। प्रदेश में न्याय, राहत और विकास का नया दौर शुरू हुआ है। सेवा, सुशासन, सुरक्षा एवं विकास के संकल्पों को लेकर प्रदेश की सरकार जनता की सेवा में दिन-रात लगी हुई है।

माननीय सभापति महोदय, जो कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए हैं, जिसका अभिभाषण में उल्लेख है, मैं उसका कुछ उल्लेख करना चाहता हूं। हम पिछले 5 साल का कार्यकाल देखें तो उस समय भी प्रधानमंत्री हमारे नरेन्द्र मोदी जी थे। लेकिन भा.ज.पा. के डॉ. रमन सिंह की जगह कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनें। कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनने के बाद केन्द्र की योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिलनी चाहिए थी, वह कहीं न कहीं अवरूद्ध हुआ, कहीं न कहीं वे लाभ से वंचित हुए, जिसके कारण प्रधानमंत्री आवास बनना लगभग बंद हो गया। जो गरीबों का हक था, जो गरीबों को मिलना था, पूरे 5 साल में यह काम शुरू नहीं हुआ। उसका कोई कारण नहीं था। केवल मन की संकीर्णता, हृदय में इतनी भी विशालता नहीं थी कि यह गरीब की योजना है तो गरीब तक पहुंचनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास लगभग बंद कर दिए गए थे। लेकिन अब मुझे इस बात की खुशी है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, श्री विष्णुदेव साय जी, एक गरीब आदिवासी का बेटा इस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने कैबिनेट में निर्णय लिया और कहा कि 18 लाख गरीब लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनाकर देंगे। (मेजों की थपथपाहट) सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जब तक गरीबों का आवास बनना शुरू ना हो जाये, मैं मुख्यमंत्री निवास में नहीं जाऊंगा, यह हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। (मेजों की थपथपाहट) आज मुझे इस बात की खुशी है कि एक गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बनने के बाद 18 लाख आवास बनाने की बात की थी, आज 14 लाख आवास बनने शुरू हो गए हैं और प्रथम किश्त की राशि हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनके खातों में डाली गई है और बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास बनने शुरू हो गए हैं।

माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आवास बनने से केवल गरीबों को ही लाभ नहीं हो रहा है। इसमें रेत की भी जरूरत है, इसमें सीमेन्ट की भी जरूरत है, इसमें मिस्त्री की भी जरूरत है, इसमें रेजा की भी जरूरत है, इसमें ईट की भी जरूरत है और उसमें उनको भी पैसा मिलता है। जो रेजा का काम करने वाले हैं, उनको भी पैसा मिलता है। हमारे मिस्त्री जो काम करने वाले हैं, उनको भी पैसा मिलता

है। उसमें सीमेन्ट की भी बिक्री होती है, रेत की भी बिक्री होती है। आवास बनाने के लिए जो पैसा आता है, वह एक व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि विभिन्न माध्यम से उस पैसे का वितरण होता है, वह पैसा बाजार में आता है और और उस पैसे का बाजार में प्रचलन शुरू हो जाता है। आज हम देख रहे हैं कि उसके कारण आज छत्तीसगढ़ खुशहाली की दिशा में है। आज लोगों को काम करने का अवसर मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने गरीबों के लिए सोचा और जो इस योजना से वंचित रहे हैं, आपने उनको प्रधानमंत्री आवास देने का निर्णय लिया है मैं उसके लिए मुख्यमंत्री जी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश की जो पहचान है, वह हमारे छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसानों के रूप में, कृषि के रूप में है। हमारी छत्तीसगढ़ की पहचान कृषि है। हम इस कृषि को कैसे उन्नत कर सकें, हमारे किसान ज्यादा से ज्यादा कैसे अन्न उपजा सके, उनको खाद की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्था की सुविधाएं कैसे मिल सकें, उनके उपज का उन्हें कैसे सही दाम मिल सकें, इसके लिए हमारी सरकार आने के बाद में उस पर विचार हुआ। पिछली सरकार ने दो साल का बोनस देने की घोषणा की थी और किसानों को दो साल का बोनस नहीं मिला, लेकिन हमारी सरकार बनने के पहले हमने वायदा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम सरकार बनने के तुरंत बाद हम दो साल का बोनस देंगे और मुझे सदन में यह बात बताते हुए खुशी हो रही है कि 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया था और 25 दिसंबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी का जन्मदिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया, उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किसानों के खाते में दो साल का बकाया बोनस 3716 करोड़ उनके खाते में डालने का काम सिर्फ 10 दिन के अंदर में किया गया। (मेजों की थपथपाहट) यह किसानों और गरीबों के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विश्वसनीयता है। माननीय सभापति महोदय, इस बार हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जब से यहां पर धान खरीदी की व्यवस्था प्रारंभ की गई है तब से हम उच्चतम सोपान पर पहुंचे हैं और इतनी सुव्यवस्थित एवं पारदर्शिता के साथ धान खरीदी की व्यवस्था की गई है ताकि किसानों को धरना-प्रदर्शन न करना पड़े। हम लोगों ने पहले भी देखा है कि वे धान खरीदी की बात तो करते थे, लेकिन किसानों के ऊपर में डंडा चलाते थे। चाहे वह हमारे कांकेर की घटना हो, केशकाल की घटना हो। मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं कि जब किसान धान बेचने जाते थे तो उनके ऊपर डंडा चलाते थे। लेकिन इस साल जो धान खरीदी की व्यवस्था की गई है और पिछले साल में व्यवस्था की गई थी, उसमें एक भी किसान को कहीं पर आवाज उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। वे अपने धान को लेकर सोसाइटियों में गये और सोसाइटियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार के द्वारा 149.25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। (मेजों की थपथपाहट) यह किसानों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि की बात है। आज तक इतनी बड़ी धान खरीदी की व्यवस्था कभी नहीं हुई है। हमने

इस बार उच्चतम रिकॉर्ड को प्राप्त किया है और सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो टाईम घोषित किया गया था, सीमित समय में दिनांक 31 जनवरी को पूरी धान खरीदी की व्यवस्था समुचित रूप से की गई है। किसानों को कहीं भी धरना-प्रदर्शन नहीं करना पड़ा। जैसा किसान चाहते हैं, उसके अनुसार से उनकी धान की खरीदी की गई है।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, एक मिनट। हमर वरिष्ठ नेता जी बहुत अच्छा भाषण देवत हे। मैं हर सुनत हाववं अऊ पूरा प्रदेश के किसान मन भी सुनत होही। यह जो केन्द्र सरकार हर 170 रूपये बढ़ाय हे, ऊहू ला दिहा या तुमन अपन जेब मा भर लिहा? ओला किसान मन बर बढ़ाय हावय?

श्री धरमलाल कौशिक :- रामकुमार जी, आपको बोलने का अधिकार ही नहीं है।

श्री रामकुमार यादव :- 3100 रूपये हर तो प्रदेश के पइसा हे। 170 रूपये ला ऊहां ले भेजे हावय, ओला तुमन दिहा या अपन पॉकेट खर्चा बर रखिहौ?

श्री धरमलाल कौशिक :- रामकुमार जी, आपको बोलने का अधिकार ही नहीं है।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, अभी प्रश्नकाल नहीं है। कौशिक जी अभी माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल रहे हैं। कृपया आप टोकिये मत।

श्री धरमलाल कौशिक :- रामकुमार जी, आपको बोलने का अधिकार ही नहीं है। आप पहले बार के विधायक रहते हुए बोलते तो समझ में आता, लेकिन आप दूसरे बार के विधायक हैं। आप उस सरकार में रहे हैं, जिस सरकार ने धोखा देने का काम किया है।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, ओमा 170 रूपये ला जोड़ दिहौ।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, बैठिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे 25,49,000 किसानों से धान खरीदी की गई है। साथ ही मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हम यदि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इतिहास में 14 महीने के सरकार की कार्यकाल की बात करें तो अभी तक किसानों को जो राशि मिली है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किसानों के खाते में 1 लाख करोड़ रूपये अंतरित की गई है। (मेजों की थपथपाहट) रामकुमार जी, कितना शून्य होगा ?

श्री रामकुमार यादव :-170 रूपया काटे हो, तेखर कतका शून्य होथे ?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, आज किसानों की जो स्थिति है, हम कहीं न कहीं देखेंगे कि जिसे अन्नदाता कहा जाता है, यह अन्नदाता का सम्मान है और अन्नदाता का जो सम्मान करते हैं, यह केवल अपने पेट के लिये, अपने उदर के लिये, चावल या धान का उत्पादन नहीं करते हैं, अपने पूरे प्रदेश के लिये नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ-साथ हिन्दुस्तान के अन्य

प्रदेशों में भी केन्द्र सरकार द्वारा यहां का चावल भेजा जाता है, अन्य राज्यों में भी उस चावल का उपयोग उदरपूर्ति के लिये किया जाता है । सभापति महोदय, हम लोगों ने इस कारण से इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से बाहर चावल भेजने का काम किया है । (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, आज हम किसानों को जो पंप कनेक्शन दिये हैं, उसके साथ जो हमारे 3 HP Pump है, उस 3 HP Pump के लिये 6000 रूपये की सब्सीडी सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, जो 5 HP Pump का पंप हैं, उसके लिये 7500 यूनिट की सब्सीडी की सुविधा दी गई है और उसके साथ ही साथ में हमारे जो घरेलू कनेक्शन हैं, ऐसे लोगों के लिये जो 400 यूनिट है, उसमें 50 प्रतिशत की सुविधा दी गई है, यह छोटा-मोटा नहीं है, 42 लाख परिवार से ऊपर के लोगों को इसका लाभ मिलेगा ।

श्री रामकुमार यादव :- अभी बिजली बिल 500 रूपया आवथे, हमर समय में 50 रूपया आवत रिहिसे, अऊ अब 500 रूपया आवथे, का बात करथव ? 400 यूनिट के बिजली बिल हा फुल आवथे । तुंहर बिजली बिल मा गरीब आदमी परेशान हे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में बिजली बिल का परीक्षण हो या हमारे किसानों का कनेक्शन हो, यह कहते हुये मुझे खुशी हो रही है कि डॉ.रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, आज हमारे स्पीकर हैं, उस समय जो योजना शुरू की गई, हमारे जो एस.टी. और एस.सी. के किसान हैं, कितना भी पंप से पानी निकालेंगे, कितना भी खपत होगा, उनसे राशि नहीं ली जायेगी । सभापति महोदय, हमारे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी ने इस नीति का क्रियान्वयन करते हुये आज उससे मुक्त रखे हैं, जिससे हमारे ज्यादा से ज्यादा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसान फसल का उत्पादन कर सके और उत्पादन करने के साथ में उनका योगदान इस प्रदेश के विकास में सुनिश्चित हो सके, उसके लिये जो प्रयास हो रहे हैं, अत: धन्यवाद के पात्र हैं । माननीय सभापति महोदय, केवल इतना ही नहीं, बल्कि जो हमारे युवा साथी हैं, प्रदेश में जो हमारी पी.एस.सी. की परीक्षा होती है, परीक्षा में जिस प्रकार से यहां पर धांधली की जा रही थी, धांधली करने के कारण सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जी को युवाओं ने जो कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया...।

श्री रामकुमार यादव :- पुलिस भर्ती में कतका धांधली होए हे, तेला बतावव ? तुही मन आदमी भेजे रेहेव लागत हे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आज जो भरोसा हुआ है...।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, लगता है कि गेस्ट हाऊस में नोट गिनते-गिनते मानसिक स्थिति बिगड़ गई है । मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूँ कि ऐसा टोका-टाकी नहीं करना चाहिये, माननीय वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- पुलिस भर्ती में काखर होए हे, तेला बताना ?

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं, इसमें टोकाटाकी नहीं करनी चाहिये ।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा है, कृपया टोका-टाकी न करें ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में चर्चा हो रही है, हमारी तरफ से पहले वक्ता जो प्रस्ताव रखे हैं, वह बोल रहे हैं । हम तो समझते थे कि विपक्ष के लोग पूरी तरह से इसमें संजीदगी के साथ भाग लेंगे । आप लोग भाग ले रहे हैं कि क्या कर रहे हैं ? आपके नेता कहां हैं, सुनना चाहिये ना ? राज्यपाल जी के अभिभाषण में टोका-टाकी करने से राज्यपाल का अभिभाषण नहीं होता है । आपको यहां सुनना चाहिये और जवाब देना चाहिये । रामकुमार जी, आप तो उठकर जाओ और बुलाकर लाओ । जाओ, बुलाकर लाओ ।

श्री धरमलाल कौशिक :-सभापति महोदय, आज भरोसा किसी के ऊपर में है तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है और विष्णुदेव साय जी की सरकार पर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है तथा हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर में है । सभापति महोदय, जिस प्रकार से भविष्य के निर्माण के लिये, जो अपेक्षा उन लोग रखते हैं कि कम से कम छत्तीसगढ़ में पी.एस.सी. की परीक्षा है, वह पारदर्शिता के साथ हो, उसमें किसी प्रकार से छेड़छाड़ न हो, कांग्रेस ने जिस तरह से छेड़छाड़ की है, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में हमने आश्वस्त किया था कि हम आपको न्याय देंगे और आपको न्याय मिलेगा । उन सबको न्याय देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सारे प्रकरण की जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपा गया । (मेजों की थपथपाहट) जब सीबीआई ने जांच की तो जांच करने के बाद में वह मामला पकड़ में आया कि यहां के युवाओं के साथ में किस प्रकार से भेदभाव किया गया और युवाओं को छलने के काम पिछली सरकार के द्वारा किया गया । जिन लोगों ने छेड़छाड़ करने का काम किया, अपने पद का दुरूपयोग किया और दुरूपयोग करके जो योग्य नहीं हैं, जो काबिल नहीं हैं, जो पात्र नहीं हैं, जिनका चयन कराया गया और चयन कराने के बाद में ऐसे लोग जेल के सीखचों के पीछे पड़े हुए हैं । यदि प्रदेश के युवाओं को इस सरकार के ऊपर में सबसे बड़ा विश्वास हुआ है तो अपने अधिकारों को लेकर विश्वास हुआ है। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि पिछले समय जो पीएससी की परीक्षा हुई और उस परीक्षा का जो रिजल्ट आया, उस परीक्षा के रिजल्ट से लोग इतने खुश थे, हमारे क्षेत्र के लोगों का भी चयन हुआ है, पूरे प्रदेश में बहुत से लोगों का भी चयन हुआ है। कुछ लोग अपने गार्जियन के साथ में मुख्यमंत्री जी को बधाई देने गए थे कि आपकी सरकार आ गई तो हमारे बेटे का चयन हुआ है । नहीं तो ये लोग पढ़ते-पढ़ते थक जाते थे, बीमार पड़ जाते थे, हताश और निराश हो गए थे । पिछली सरकार में इनका चयन होने का कोई संभावना नहीं थी । (मेजों की थपथपाहट) आपने उनको आशान्वित किया है और आज यदि वह डिप्टी कलेक्टर बन रहे हैं, डीएसपी बन रहे हैं, यदि आज वे बड़े-

बड़े पदों में जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण बड़े-बड़े पदों में जा रहे हैं क्योंकि आपने पूरी पारदर्शिता के साथ पीएससी की परीक्षा आयोजित की, जिसके कारण में चयन हो सका है । आज युवा और उनके गार्जियन सरकार को बधाई दे रहे हैं ।

माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात विश्वसनीयता की होती है । कांग्रेस की सरकार में विश्वसनीयता का संकट आ गया था, उसके कारण चारों तरफ लोगों में उदासी रही । पिछली सरकार जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, अनेक घोटाले हुए और इन सारे मामलों को देखकर लोग आशा ही छोड़ दिए थे कि छत्तीसगढ़ का भविष्य सुधरने वाला है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिला है तो निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ के चाहे गरीब हो, किसान हो, महिला हो, उनके प्रति जिन योजनाओं को लेकर जो काम कर रहे हैं, वह निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं, इसके कारण उन लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं सामान्य एरिया की ही बात नहीं कर रहा हूं । कहीं न कहीं देखिए कि प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद की रही है । हमारा अधिकांश बजट लोगों के विकास में खर्च होना चाहिए, वह खर्च होने की बजाय जो नक्सल गतिविधि चल रही थी, उसके मूवमेंट के लिए बड़ी राशि लगा जाती थी, लेकिन पिछली सरकार में हम लोगों ने देखा था कि नक्सलियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, उसके कारण वे नक्सली घटना को आये दिन अंजाम दे रहे थे । आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, उसके बाद इस मूवमेंट में जो काम हुआ और पिछले 14 महीनों में 300 से अधिक नक्सलियों का सफाया किया गया है एवं 972 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है । हमारी सरकार बनने के बाद 1183 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है । आज बस्तर में अमन-चैन नई दिशा में प्रारंभ हो गया है । पहले आम सिविलियन का मनोबल गिरा हुआ था, आज सब अपने काम में लग गए हैं और उनको इस सरकार के ऊपर भरोसा है, लेकिन नक्सली अभी कहीं पर हिंसा करते हैं तो वह यह अहसास कराने की कोशिश करते हैं कि वे अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से इस देश के गृहमंत्री अमित शाह जी ने यह घोषणा की है कि आने वाले मार्च, 2026 तक के लिए हमने विस्तार से पूरे देश के लिए योजना बनाई है और उस योजना को लेकर हम काम कर रहे हैं और उसमें सहभागिता निभाते हुए हमारे युवा उप मुख्य मंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा जी कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रहे हैं और जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, उससे ये विश्वास जागृत होने लगा है कि नक्सलियों का मनोबल गिरा हुआ है और वे भागने लगे हैं और हम वहॉ पर अमन-चैन कायम करने में सफल हुए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को यह विश्वास है कि मार्च, 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का सफाया हो जाएगा और हम सबको नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ मिलेगा। यह विश्वास जागृत हुआ है। (मेजों की थपथपाहट)

समय:

1.16 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं वहॉ जो लोग नक्सल गतिविधि छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुए और अपने काम धंधे में लग गए, ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए अलग से 15 हजार प्रधान मंत्री आवास योजना स्वीकृत की गई है, ताकि उन्हें हम नए सिरे से बसा सकें और वे परिवार के साथ जीवन-यापन कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, वहॉ नियद नेल्लानार योजना के तहत 19 विभागों को लेकर एक दृष्टिकोण बनाया गया कि वहां के लोगों को पानी कैसे मिल सके, उनके लिए लाईट की व्यवस्था कैसे हो सके, वहॉ के बंद स्कूलों को किस प्रकार से खोला जा सके। अध्यक्ष महोदय, वहॉ के स्कूलों को खोलने का काम, आंगनबाड़ी का निर्माण, सड़क एवं सी.सी. रोड्स का निर्माण, पहुंचविहीन क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने का काम, वहॉ के लोगों को दिल्ली और रायपुर के आम आदमी से जोड़ने के लिए टॉवर लगाने का काम किया जा रहा है। इस प्रकार से नक्सल क्षेत्र एवं वहॉ के परिवारों के लिए जो बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं, इससे निश्चित रूप से बड़ी कामयाबी मिल रही है और वहॉ नए विकास के कार्य शुरु हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, बस्तर में ओलंपिक खेल का जो कार्यक्रम हुआ, उस खेल के माध्यम से वहां के आम लोगों के मन में बड़ी रुचि पैदा हुई कि इन खेलों में हमें भी भाग लेना है। उस बस्तर ओलंपिक में 1 लाख 65 हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया इसलिए हम उसे ऐतिहासिक खेल कहते हैं क्योंकि उस एरिया में इतने लोग निकलकर मैदान में जाकर विभिन्न खेलों में भाग लें, क्योंकि जहां पर लोगों को केवल एक भय सता रहा था, जिसके कारण उन्हें किसी गतिविधि में भाग लेना संभव नहीं था, किन्तु इस बस्तर ओलंपिक ने तो कमाल ही कर दिया कि 1 लाख 65 हजार से अधिक लोगों ने उसमें भाग लिया और उनमें नया विश्वास जागृत हुआ। आज जैसे रायपुर, बिलासपुर जैसे मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं, उस मानसिकता के साथ वहॉ पर लोग काम करने के लिए उतारू हुए हैं। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जब आप पहले निर्वाचित मुख्य मंत्री बने, उस समय सबसे बड़ी जो समस्या थी कि लोग अपने उदर पोषण के लिए बच्चे, परिवार को लेकर यहॉ से पलायन करते थे, क्योंकि उनके पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय आप उनको 3 रुपए किलो में 35 किलो चावल देने की योजना शुरु किए, जिसे कि बाद में 1 रुपए प्रति किलो किया गया, जिसके कारण आप चाऊर वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। (मेजों की थपथपाहट) इस निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट का मार्गदर्शन आया कि जहॉ एक तरफ अन्न भरा हुआ है और दूसरी तरफ लोग भूख से मर रहे हैं, तो केन्द्र सरकार के द्वारा इस योजना को लागू किया गया। लगातार यह योजना चलती रही और आज मुझे यह बताने में खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री

जी के द्वारा हमारे 67 लाख 94 हजार परिवार, अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, नि:शक्तजन राशनकार्डधारियों को दिसंबर 2028 तक, मुफ्त में चावल देने की योजना बनाकर घोषणा की है और ऐसे लगभग 68 लाख परिवारों को मुफ्त में चावल मिल रहा है (मेजों की थपथपाहट)। आज सभी को मुफ्त में चावल मिलने से एक बड़ी राहत मिल रही है। यह योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोविडकाल में शुरू की है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी जैसे ही निर्वाचित होकर आये, उसके बाद उनके द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना को प्रारंभ किया गया। उनको दिसंबर, 2028 तक मुफ्त में चावल मिलेगा, जिससे उन लोगों के जीवन में निश्चिंतता आ गयी है। उनको खाना खाने के लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उनके घरों में अनाज की उपलब्धता है। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में चावल देने की जो योजना शुरू की है, उसकी तुलना में यदि हम यूरोप की पूरी आबादी को जोड़ ले, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी यूरोप की आबादी से ज्यादा चावल मुफ्त में हमारे देश में दे रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) इसी प्रकार से मैंने छत्तीसगढ़ की बात की है।

अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने महतारी वंदन योजना लागू करने की घोषणा की थी। इसके पहले कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी कि हम बेरोजगारी भत्ता के रूप में 1000 रूपये देंगे। लेकिन वह 1000 रूपये नहीं दे पाये। हमारी सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में जारी किया कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम महतारियों के खाते में 1000 रूपये देंगे। एक परिवार में जितनी भी महतारी हैं, हम उन सब के खातों में रूपये डालेंगे। इसमें एक परिवार की बात नहीं की गयी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल में उनको पैसे नहीं दे पायी।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- यादव जी, जब माननीय सदस्य अपनी बात को रोक नहीं रहे हैं तो आप बैठ जाईये।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार बनी।

श्री रामकुमार यादव :- नेता जी, नेता जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- एक मिनट रूक जाईये, उसके बाद मैं बैठ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद 70 लाख महिलाओं के खाते में महतारी वंदन की राशि जाना शुरू हो गयी। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक जगह कथा में गया था।

अध्यक्ष महोदय :- आप एक मिनट रूक जाईये। यादव जी का बोलना बहुत जरूरी है। इनका कुछ छूट गया था। आप बोलिये।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, कौशिक जी बहुत अच्छा भाषण देवत हे। हमन ला बहुत अच्छा लगत हे कि ए मन महतारी मन ला 1000 रूपये देथे। लेकिन 6 महीने पहली जो एकर से जुड़े

हे। अभी में हर कई झने मंत्री मन ला देखथ रेहेव कि ओ मन सामूहिक विवाह में गे रिहिन हे अउ सामूहिक विवाह में कतका कतका झन के शादी कराये हे। अब ए मन ओकर शादी तो करवा दे हे। लेकिन अब ओकर नाम कब जुड़ही ? ओ मन कहात रिहिसे कि जो हमर शादी में आत रिहिसे, ओ मन कौन रिहिसे ? तो दूसरा मन कहत हवय कि ओ महाराज हा गृहमंत्री हे, ओती कहाथे मुख्यमंत्री हे अउ अरूण साव हर घलोक हमर गांव में गये रिहिसे। ओ मोला कहिथे कि मोर शादी में जब अरूण साव हा आये रिहिसे तो मोला महतारी वंदन के पैसा हर कब मिलही ? तो में हर कहिथव कि में हर कौन ला बतावव। आप मन हर ओकर नाम ला जोड़ देवव।

अध्यक्ष महोदय :- अभी तोर शादी तो नइ होये हे। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- उहु ला जोड़व। उ मन के महतारी वंदन मा नाम कब जुड़ही ?

अध्यक्ष महोदय :- मुख्यमंत्री जी हर तोर शादी के चिंता करही। तै चिंता मत कर। कौशिक जी, अब आप आगे अपनी बात रखिये।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- यादव जी, कम से कम तोर होने वाली बाई के नाम तो बता दे। उहु ला मिल जाही।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह दूसरे बारे के विधायक हैं, अभी भी उनको कोई लड़की देने के लिये तैयार नहीं है। (हंसी) क्योंकि भरोसा नहीं है। (हंसी) इसलिए आप जब शादी करेंगे तो हम आपकी शादी ऐसे ही नहीं करायेंगे। हम आपकी शादी मुख्यमंत्री कन्या दान योजना में करायेंगे। उसमें आपका एक पैसा नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री जी यहीं रायपुर में कन्या दान योजना में आपकी शादी करायेंगे। उसमें मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद देने के लिये शामिल रहेंगे और हम लोग भी उपस्थित रहेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- कौशिक जी, रामकुमार यादव भाई के लिये पिछली बार यहीं पर तो एक महिला सदस्य बैठी थीं। पिछली बार के सदन में हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था कि आप भी कुंवारे थे और वह भी कुंवारी थी। आपको शादी कर लेनी थी। अभी तक तो सब हिसाब-किताब पूरा हो गया होता। (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिक :- आपको पेंशन भी मिलती।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता रहा था कि महतारी वंदन योजना का उपयोग कैसे करते हैं। सरकार की उसके पीछे जो सोच रही है कि हमारे प्रदेश की महतारियों को आर्थिक रूप से संबल मिलेगा, उनमें आत्मनिर्भरता आएगी और उसके साथ ही साथ वे जो छोटे-छोटे कार्यों के लिए चाहे बेटे के ऊपर हो या पति के ऊपर आश्रित रहती हैं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैं एक जगह कथा सुनने के लिए गया था। वहां पर महिलाएं कथा करा रही थीं तो मैंने उनसे यह पूछा कि आप लोगों को कथा कराने के लिए चंदा-वंदा ठीक मिला। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, विधायक

महोदय। हमें कथा के लिए जो चंदा-वंदा मिला, वह तो ठीक है, लेकिन हम लोगों ने यह तय किया है कि हमें कथा करानी है, हमें चंदा मिला या न मिले। हम सब महिलाओं ने यह तय किया है कि आप लोग जो हमें महतारी वंदन योजना में पैसा दे रहे हैं हम उसी से कथा को संपूर्ण करवा लेंगे। हमको दूसरों के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। (मेजों की थपथपाहट) मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक जगह पर राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। उन्होंने ऐसा सोचा कि वहां अयोध्या कितने लोग दर्शन करने जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। इसलिए हम अपने क्षेत्र में ही राम मंदिर बना रहे हैं। जो वहां पर दर्शन करने नहीं जा पाएंगे वह यहां पर दर्शन करने के लिए आएंगे। अब प्रदेश के लोगों की सोच में कितना परिवर्तन आया है। आज सब लोग सकारात्मक दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं। इसलिए महतारी वंदन योजना का केवल पैसा ही आधार नहीं है कि हमारी सरकार ने उस योजना में महतारियों को पैसा दिया। उसका मूल आधार यह है कि उनमें आत्मबल जागृत हुआ और उसके साथ में परिवार के मुखिया होने के नाते, वह अपना परिवार कैसे चलायें ? उनको यह दिशा और दृष्टि मिली है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे प्रदेश में इस प्रकार की योजनाएं सफल हो रही हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार हम लोगों ने तेन्दू-पत्ते का जिक्र किया है। बस्तर या सरगुजा क्षेत्र में जहां भी तेन्दू-पत्ता तोड़ते हैं, जो हमारा वनांचल क्षेत्र है उस क्षेत्र में तेन्दू-पत्ता संग्रहण दर 4000 रूपये उसे बढ़ाकर साढ़े पांच हजार रूपए कर दिया है। यह थोड़ा बहुत नहीं है, बल्कि हमारे 12 लाख 50 हजार संग्राहक हैं जिनको हमारे छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा तेन्दूपत्ता तोड़ने और उनको बोनस का लाभ दिया जा रहा है। आज हम उनके जीवन की आर्थिक स्थिति देखेंगे। तेन्दू-पत्ते को हरा सोना कहा जाता है। इस हरे सोने के माध्यम से उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। प्रदेश में सरकार आती रहती है और सरकार जाती रहती है। यहां महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि प्रदेश में सरकार किसकी है, किस पार्टी की सरकार है ? यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी की सरकार आने के बाद सरकार के द्वारा गरीबों के जीवन में क्या बदलाव हुआ है, यह किसी सरकार की सार्थकता होती है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार की सार्थकता दिखायी दे रही है। मैं इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय कौशिक जी, आप और कितना समय लेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी तो अपना भाषण शुरू किया है। (हंसी) केवल एक पृष्ठ ही हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- आपका 40 मिनट का समय पूरा हो चुका है, मगर आप बोल सकते हैं, आप अपना भाषण दीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण जल्दी समाप्त कर दूंगा। बाकी सदस्यों को भी बोलना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रामलला दर्शन पर कहना चाहूंगा। हम सब पता नहीं कब से बाट जोह रहे थे कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनेगा, भगवान राम अपने भवन में जाएंगे और वहां पर रहेंगे। इसकी 500 सालों की संघर्ष गाथा है। इन 500 सालों की संघर्ष गाथा का पड़ाव महल में आकर खत्म हुआ है। जब इस देश में यशस्वी नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री बनें तो भगवान राम का वनवास समाप्त हुआ और उन्होंने पंडाल से लेकर अपने भव्य महल में आकर प्रवेश किया। जिस प्रकार से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया है ...।

समय
1.28 बजे

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक भोजन अवकाश के समय में वृद्धि की जाये। मैं समझता हूँ कि इससे सदन सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमश:)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांचे हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने से दुनिया के लोग खुश हुए होंगे, लेकिन यदि किसी में सर्वाधिक खुशी दिखायी दी तो छत्तीसगढ़ के भगवान राम के मामाओं के चेहरे में खुशियां दिखाई दी हैं कि अधोध्या में हमारे भांजे के भव्य महल का निर्माण हुआ है। इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा "रामलला दर्शन योजना" प्रारंभ की गई कि भगवान राम का दर्शन कर सकें। आज हजारों की संख्या में पूरे छत्तीसगढ़ से लोगों को गाजे-बाजे के साथ स्वागत करके रेल्वे स्टेशन से उनको अयोध्या दर्शन के लिए प्रस्थान कराया जाता है। मुझे भी कई बार जाने का अवसर मिला है। अध्यक्ष महोदय आप भी गये होंगे, माननीय मुख्यमंत्री भी गये हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक भी गये हैं। जब उनको रेल्वे स्टेशन में विदाई देने के लिए जाते हैं, वहां पर उनका चेहरा देखने लायक रहता है। उनको माला पहनाई जाती है, टीका लगाया जाता है, उनको गाजा-बाजे के साथ ले जाकर ट्रेन में बिठाते हैं। जब वहां से लौट करके आते हैं, इस बात की चर्चा अपने गांव में करते हैं कि हम अपना इतना पैसा खर्च करके जायेंगे तो इतना अच्छा दर्शन नहीं हो सकता जितना भारतीय जनता पार्टी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा रामलला तीर्थ दर्शन योजना के तहत दर्शन कराया गया है। आज यह गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए मुझे मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री जी अयोध्या में रामलला का दर्शन करने जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे मुंगेली में उप मुख्यमंत्री जी को मालूम है कि

लोग उनको ताना देते हैं कि उनको ले गये थे, हमको कब ले जायेंगे। हमारे पुन्नूलाल मोहले जी बैठे हुए हैं, हम लोग बैठे हुए हैं। इसकी संख्या को बढ़ाना पडेगा और ट्रेनों की बोगी की संख्या को भी बढ़ाना पड़ेगा तब हमारा रामलला का दर्शन सफल होगा। क्योंकि अभी लोगों की मन की प्यास बुझी नहीं है। वहां पर अदभूत नजारा देखने को मिलता है। वास्तविक में सरकार वही है, किस प्रकार से लोगों की जनभावना है, उन भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करती बल्कि उन भावनाओं का सम्मान कैसे कर सकते हैं, यह हमारी विष्णु देव जी की सरकार से देखना चाहिए और सीखने की आवश्यकता है। (मेंजो की थपथपाहट) इस प्रकार से जो योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी हम बहुत जल्दी प्रारंभ करने वाले हैं। मैं उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि लोगों की आस जो और कहीं न कहीं तीर्थ दर्शन करने जाने की है, उन लोगों को भी उसका लाभ मिलेगा। आपने उस योजना को प्रारंभ किया था और जब इधर के लोग इधर बैठे, अध्यक्ष महोदय, उनको तो कुछ अच्छा लगता ही नहीं था। उनको तो केवल यही अच्छा लगता था- नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी, इससे ज्यादा नई जानव संगवारी। मैं पहले अभिभाषण में इस बात का संकेत किया था और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को मैंने बोला था। आपने तो परिश्रम किया, आपको सलाहकार बहुत मिल जायेंगे और आपको मुफ्त में सलाह देने वालों की कमी नहीं है। उनको चक्कर में आप यह नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी में फंस गये हो। आप इसको तत्काल रोक दीजिए नहीं तो आपका हश्र 5 साल में दिखेगा। आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि जिस बात को मैंने पहले नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उल्लेख किया था, आज वह उनका हश्र दिखाई दे रहा है। इधर 71 की ताकत में बैठे हुए थे, आज उनको जनता ने उखाड़कर के इधर बैठा दिया है। (मेजों की थपथपाहट) सरकार बनाकर चलाना और सरकार बनाने के बाद में जनता की नब्ज को पकड़ना आना चाहिए। आप मनमानी मत कीजिए। आप मनमानी करेंगे तो मनमानी का यह हश्र होता है। इसलिए जनभावना का सम्मान होना चाहिए। जनता की भावनाओं का आदर होना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी उन्हीं जनभावनाओं का सम्मान करते हुए नई-नई योजना को लांच कर रहे हैं।(मेजों की थपथपाहट) जिस प्रकार से केन्द्र सरकार के द्वारा चारधाम की यात्रा के निर्माण के काम शुरू किये गये हैं। हमारे यहां पर सूरजपुर जिला स्थित कुदरगढ़, डोंगरगढ़ में मॉ बम्लेश्वरी मंदिर, बिलासपुर जिला का मॉ महामाया रतनपुर मंदिर, सक्ती जिला स्थित मॉ चन्द्रहासिनी मंदिर, दंतेवाड़ा जिला स्थित दंतेश्वरी मंदिर 5 माता जी के स्थान हैं। इनको एक बृहद योजना बना करके हमारी यात्रा कैसे अच्छी हो सके, उसके लिए जो योजना बनाई गई है और आने वाले समय में उस योजना का हमको लाभ मिलेगा। हमारी रक्षा करने वाली हमारी मातायें हमारे प्रदेश के अलग-अलग कोने में विराजमान हैं, वहां तक सुगमता के साथ में यात्रा हो सके, उसके लिए बृहद योजना बनाई गई है, मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं । (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और नई योजना की बात करता हूं कि मुख्यमंत्री जी की जो सोच है वह किसानों तक

सीमित नहीं है बल्कि उसके आगे कि हमारे ऐसे खेतिहर मज़दूर जो खेती में काम तो करते हैं लेकिन उनके पास खुद का खेत नहीं है । एक नयी योजना पंडित दीनदयाल योजना के अंतर्गत ऐसे लोगों को जोड़ा गया ।

श्री उमेश पटेल :- नाम बदले हैं कि नयी योजना है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- नयी योजना है । हमारे लगभग 5 लाख 63 हज़ार ऐसे लोगों को 10 हज़ार रुपए सालाना देने हेतु उनकी किश्त की राशि डाल दी गई है और निश्चित रूप से उन लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा । (मेजों की थपथपाहट) क्या आप लोगों ने 10 हजार रूपये दिया था ?

श्री उमेश पटेल :- नहीं-नहीं, योजना नयी है कि नाम बदले हैं ?

श्री धरमलाल कौशिक :- मैंने तो बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना ।

श्री उमेश पटेल :- नहीं-नहीं, आप इतना बता दीजिये कि योजना नयी है कि नाम बदले हैं ?

श्री धरमलाल कौशिक :- अरे नहीं भाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना है, नयी योजना है और हम लोगों ने 10 हजार रूपये की राशि दी है । (मेजों की थपथपाहट) हमारे उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने अभी महतारियों के लिए चिंता की है और महतारियों के लिए चिंता करके महतारी सदन और महतारी सदन के लिए 202 ग्राम पंचायतों को चिन्हांकित किया गया और वहां पर राशि दी गयी, वहां पर 25 लाख रूपये की लागत से महतारी सदन का निर्माण किया जाएगा । वर्षों से इनकी यह मांग रही है, हम लोग आज भी जहां जाते हैं तो महतारी लोग मांग करते हैं कि महतारीयों के लिए एक अलग भवन बनाकर दिया जाए । आप गांव में 10 सामुदायिक भवन दे दीजिए लेकिन 10 सामुदायिक भवन देने के बाद में उनकी अलग मांग है और मांग इसलिए है कि आजकल वे जागरूक हो गई हैं, उनकी बैठकें होती हैं । उस बैठक के लिये सर्वसुविधायुक्त भवन चाहिए और उस भवन के लिए हमारी सरकार के द्वारा योजना बनाई गई और योजना बनाकर जिस प्रकार से आज उसका क्रियान्वयन हो रहा है तो निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूं कि इसका लाभ और बल्कि आने वाले समय में चूंकि यह तो प्रथम साल में 202 एक identify करके किया गया हैं, इसमें और वृद्धि होगी और पूरे प्रदेश में महतारियों का जो मान और सम्मान है उस मान-सम्मान को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के भवन की व्यवस्था योजना बनाकर की गयी है । मैं हमारे उपमुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक आपकी सरकार रही तब तक हम सड़कों की बात करते रहे लेकिन आपकी सरकार के बाद में जब congress की सरकार आई और उसके बाद में सड़कों का निर्माण कार्य बंद हो गया और सड़कें यदि बनी हैं तो केवल एक जिला में, जहां 5-5 मंत्री विराजमान थे, लगभग विकास की सारी योजनाएं वहीं पर रही लेकिन बाकी जगह की जब बात करेंगे तो आपके समय में हम लोगों ने जो सड़कें बनवाईं चाहे पीडब्ल्यूडी की सड़क हो, हमारी प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, मुख्यमंत्री सड़क योजना हो, इस 5 साल में इस सरकार ने नयी सड़क बनाने का नहीं बल्कि उस सरकार के द्वारा,

पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा उसका पेच रिपेयर कराना भी उनके लिए संभव नहीं हुआ और यह कह सकते हैं कि 5 साल में पेच रिपेयर वह सरकार नहीं करा पाई और जो सरकार पेच रिपेयर नहीं करा पाई उससे जनता कितनी उम्मीद करे और इसलिए जो बदलाव हुआ तो मैं हमारे उपमुख्यमंत्री अरुण साव जी को बधाई देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे अरुण साव जी के द्वारा लगभग चिन्हांकित किया गया है और चिन्हांकित करने के बाद में सड़कों के लिए जो राशि उपलब्ध कराई गई है । आज नई सड़कों के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है । मैं इसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूं । (मेजों की थपथपाहट) केंद्र सरकार नितिन गडकरी के द्वारा यहां पर जो राशि दी जा रही है, सी.आर.पी.एफ. की सड़क के लिए राशि दी जा रही है । हमारे केंद्रीय सड़क के लिए जो राशि दी जा रही है और हमारे खुद के PWD विभाग के द्वारा, राज्य के द्वारा नवीनीकरण के लिए जो राशियां उपलब्ध कराई जा रही हैं, अब जनता की उम्मीद जगने लगी है कि वह जो सड़क है अब सड़क गड्ढे में तब्दील नहीं होगा बल्कि गड्ढा जो है अब सड़क के रूप में कुछ दिन के बाद में दिखाई देने लगेगा इसके लिए राशि की व्यवस्था की गई है । (मेजों की थपथपाहट) इसके साथ ही साथ केवल उतना ही नहीं बल्कि नल जल योजना को लेकर आज खूब चर्चा हुई है और हमारे उप मुख्यमंत्री जी जवाब देते-देते थके नहीं, अंत तक जवाब दे रहे थे, लेकिन आपका उसमें कोई दोष नहीं है, आपकी नीयत साफ है और आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई है कि एक-एक घर तक नल जल कनेक्शन पहुंचनी चाहिए और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए आपने नए सिरे से प्रारंभ किया है। लेकिन पूरे 5 साल में क्या हुआ? पूरे 5 साल में एक बार उसका टेंडर हुआ। पहले कैबिनेट में उसको इनके द्वारा निरस्त किया गया। निरस्त करने के बाद में कलेक्टर को अधिकार दिया गया और अफरा-तफरी मची और उस जल जीवन मिशन के पैसे का भ्रष्टाचार हुआ है। आज हम ठेकेदार की बात करें, आज अधिकारी की बात करें, हम कार्रवाई की बात करें तो उसके लिए यदि कोई दोषी है तो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार है। जिसके कारण में जो अफरा-तफरी मची हुई है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके लिए ये लोग दोषी हैं। (मेजों की थपथपाहट) जिसके कारण एक साल में नई समीक्षा किये हैं। आपके समय जो बंद थे, उसको चालू करने का काम किये हैं।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन एक साल में का करथौ। एक साल में एक बाल्टी पानी नहीं मिलथे। साहब, एक साल होगे हे। छत्तीसगढ़ के जनता मन ला एक बाल्टी पानी नहीं मिलथे।

श्री उमेश पटेल :- आप डेढ़ साल से सरकार में हैं। अब तो आरोप मत लगाइए, कार्रवाई करिए न? अगर आरोपी लगा रहे हैं तो कार्रवाई भी तो नहीं कर रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- एक बाल्टी पानी नहीं मिलथे। डेढ़ साल ले का करथे। खाली बइठे भाषण ही दिहौ का। डेढ़ साल में का करे हव तेला बतावव न, एक बाल्टी पानी नहीं मिलथे। तीन कोस में जावथे, हमर दाई मन उहां के पानी ला लावत हाव।

अध्यक्ष महोदय :- धरमलाल कौशिक जी, 50 मिनट हो गये हैं। कृपया समाप्त करें।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं 5 मिनट में समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- हां।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार समीक्षा कर रहे हैं और अब सुनिश्चित कर रहे हैं कि वहां तक पानी पहुंचनी चाहिए। कार्रवाई की जहां तक बात है, मैंने आज ही तीन-चार उदाहरण दिया है और मैंने उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया है कि आपने एक के खिलाफ में एफ.आई.आर. कराया है? उनको 2 साल, 3 साल के लिए डिबार किया है। केवल इसमें कार्रवाई, इसके पहले भी कार्रवाई किए हैं और कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन केवल कार्रवाई कर हम ये दिखाना नहीं चाहते कि आपकी सरकार थी इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं। आपकी सरकार ने उस पानी को पहुंचाने का काम नहीं किया, यह प्रमुख है और हमारे मुख्यमंत्री हिम्मत के साथ में साहस के साथ में उनके घर तक पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम इसलिए उनको बधाई देना चाहते हैं।(मेजों की थपथपाहट) ताकि हमारी सारी योजना पूरी हो जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी नौकरी में जहां-जहां पद खाली हैं, युवाओं की आशा जगी है और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी विभागों की समीक्षा करने के पश्चात् उन विभागों के विज्ञापन जारी होने लगे हैं और जारी होने के बाद नौकरी मिलना शुरू हो गया है, इस बात की मुझे खुशी है।

श्री रामकुमार यादव :- आपने 3000 लोगों को निकाल दिया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप 14,000 शिक्षकों के भर्ती 5 साल में नहीं कर पाये।

श्री नीलकंठ टेकाम :- जो 3000 हैं, वह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से हटाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है।

श्री रामकुमार यादव :- कलेक्टर साहब जी, अभी 3000 ला निकाले हौ। ओमन बहरी मुठा धरे खोजथे कि कोन निकाले हे।

श्री नीलकंठ टेकाम :- कोर्ट के आदेश के बावजूद भी गलत भर्तियां हुई थीं।

श्री धरमलाल कौशिक :- टेकाम जी, इसी विधान सभा की बात है और मैंने ही प्रश्न लगाया था। बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाए कि 4,80,000 लोगों को हमने नौकरी दी। आप थे न। आप भी थे। बिलासपुर में जब गए तो वहां पर भाषण दिए कि 5,00,000 लोगों को नौकरी दी और जब हमने यहां पूछा..।

श्री धर्मजीत सिंह :- भैया, नौकरी तो छोड़ो गोबर बेचकर कोई कार ले लिया, बताये, कोई स्कूटर ले लिया है, बताये। मुझे आज तक स्कूटर कार वाला नहीं दिखा।

श्री उमेश पटेल :- भैया, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। आप मेरे साथ खोखरा गांव चलिए, जहां गोबर से गोबर गैस बनाकर 12 घर को सप्लाई की गयी थी।

श्री धर्मजीत सिंह :- अब कोई विद्वान होगा। मैंने 30 साल पहले भी देखा था, गोबर से लाइट जलती थी, लेकिन कोई कार नहीं खरीदा है भाई। (हंसी) लेकिन अब इनके यहां इसलिए कार खरीद सकता है, क्योंकि एक गाय डेढ़ क्विंटल गोबर देती थी, पता नहीं उसे क्या खिलाते थे और कैसे गोबर निकलता था? (हंसी) भगवान मालिक है।

श्री राजेश मूणत :- वह कौन सी गाय थी?

श्री नीलकंठ टेकाम :- उस गाय के बारे में रामकुमार जी बतायेंगे।

श्री उमेश पटेल :- वो जो आप लोग प्रसव सुधार कर रहे थे न, वही गाय थी। (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा था कि पांच लाख नौकरियों की बात करते थे, 4 लाख 80 हजार नौकरियों की बात करते थे । पूरे प्रदेश में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे और हमने जब विधान सभा में जवाब मांगा तो मुख्यमंत्री जी ने बड़ी मुश्किल से बताया कि हमने 20 हजार लोगों को नौकरियां दी हैं। हमने उसी समय कहा कि बोर्ड को निकलवाइए, नहीं तो आप गाय की बात करते हैं, उसी के गोबर से उसकी शानदार पुताई की जाएगी और उसके बाद इनको होर्डिंग निकालना पड़ा । ये केवल बढ़ा चढ़ाकर बात करते थे, केवल दिखाने की बात करते थे, हमारी सरकार दिखाने की बात नही करती ।

श्री उमेश पटेल :- कौशिक भईया, विधान सभा में किसी चीज की घोषणा हो जाती है, उसको तो मानते हो ना ?

श्री धरमलाल कौशिक :- 20 हजार ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्वीटर में जो लिखा जाता है, उसको तो मानते हैं ना ? वह तो डिलिट करना पड़ गया ।

श्री राजेश मूणत :- अरे, इधर देखकर बात करो ना, ये क्या दोनों-दोनों ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, शिक्षा को लेकर काफी चर्चा हुई । लेकिन मुझे अच्छा लगा कि पैरेंट्स और टीचर्स की बैठक हुई कि पांचवी की परीक्षा का भी मूल्यांकन होना चाहिए, जैसे बोर्ड की परीक्षा होती है । मुझे ऐसा लगता है कि उसमें काफी सुधार की आवश्यकता है । बच्चे जब पढ़ने जा रहे हैं तो वे अपना नाम तो लिख लें । लेकिन जिस प्रकार से पांच साल में शिक्षा के क्षेत्र को इन्होंने चौपट करने का काम किया । छठवीं में बच्चे पढ़ने चले जाएं और उन्हें नाम और पिता का नाम भी न लिख सकें । आखिर हमारी शिक्षा की क्या स्थिति है ?

श्री उमेश पटेल :- धरम भइया, पांचवी की परीक्षा नहीं होगी, यह निर्णय कब हुआ था, यह बता दीजिए ?

श्री धरमलाल कौशिक :- बोर्ड की जो परीक्षा हो, निश्चित रूप से जो निर्णय हुआ है वह शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए हुआ है और मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं (मेजो की थपथपाहट) ।

श्री उमेश पटेल :- ये हुआ कब था, यह तो बता दीजिए ?

श्री धरमलाल कौशिक :- पीएमश्री सकूल की योजना है । प्रधानमंत्री जी की योजना है ।

श्री रामकुमार यादव :- स्वामी आत्मानंद स्कूल के बाद वो बने हे, ओखर लेबल लगा दे हौ ।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं, नहीं । हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है ।

श्री रामकुमार यादव :- जैसे फिलिम मा अमिताभ बचचन ला धरमेन्दर बना दे, वइसने ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपकी योजना है स्वामी आत्मानंद योजना । हम लोगों ने उस समय कहा था कि मुख्यमंत्री जी आप इसका सेटअप बनवा लीजिए, इसकी भर्ती की प्रक्रिया कर लीजिए, आप भवन बनवा लीजिए । आप चला रहे हैं अच्छी बात है, नया प्रयोग करना चाहिए । लेकिन इसको कलेक्टर के प्रसाद पर्यन्त पर छोड़ दिया गया कि कलेक्टर जब तक चाहे, तब तक चलाए और कलेक्टर नहीं चला सकते तो मत चलाए । अभी कल ही बोल रहे थे कि स्वामी आत्मानंद स्कूल में टीचर नहीं हैं, बैठने की व्यवस्था नहीं है । आपसे किसने कहा था कि उसको कलेक्टर के भरोसे छोड़ो ? कलेक्टर को जब तक डीएमएफ की राशि मिल रही थी तब तक कलेक्टरों ने चलाया और अब कहां से चलाए, डीएमएफ की राशि में परिवर्तन हो गया है । यह जो हश्र हो रहा है उसके लिए हमारी सरकार दोषी नहीं है । यदि कोई दोषी है तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार (मेजो की थपथपाहट) । ये लोग स्वामी आत्मानंद के नाम को डुबाने में लगे हैं और शुरू से नाम को डुबाने में लगे हैं । इसके कारण यह सब हश्र हुआ है ।

श्री उमेश पटेल :- भईया, अभी स्वामी आत्मानंद स्कूल का नाम क्या है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- स्वामी आत्मानंद ।

श्री धर्मजीत सिंह :- स्वामी आत्मानंद जी को हम सब लोग नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वे छत्तीसगढ़ के महापुरूष हैं ।

श्री उमेश पटेल :- आप लोगों ने नाम दिल दिया । स्वामी आत्मानंद का बोर्ड बदल गया है, पीएमश्री लिखा गया है । आप किस दुनिया में हो भइया ?

श्री धर्मजीत सिंह :- हम इसी दुनिया में हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- हम लोग ऐसा नहीं बदलते ।(व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- प्रधानमंत्री के नाम के स्कूल मा गुरूजी नइ हे । इंजन से इंजन जुड़त जात हे, चार ठी इंजन हो गे हे । अउ गुरूजी नइ हे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- हमारी सरकार आत्मानंद जी का बहुत सम्मान करती है और कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय :- धरमलाल जी, 60 मिनट हो गए हैं । कृपया समाप्त करें, भोजन अवकाश भी देना है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप लोग नाम बदलते हो ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अटल जी के नाम पर था नया रायपुर, उसमें इन्होंने और कुछ जोड़ दिया । कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम पर था, उसमें कुछ और जोड़ दिया। अपने नाम की पट्टी कैसे लगाएं, इनकी केवल ऐसी ही योजना है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप उधर मत देखिए, इधर देखिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अब वहां पटेल साहब के सिवाय कोई देखने लायक है भी नहीं तो उन्हीं को देख रहे हैं साहब ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने रायपुर की नालंदा परिसर की तर्ज पर 13 नगरीय निकायों में सर्व सुविधायुक्त हाईटेक लाईब्रेरी का निर्माण किया है। आज पी.एस.सी. की परीक्षा देनी हो, अन्य Competitive एग्जाम हो, उसकी तैयारी के लिए, हमारे युवाओं के लिए संसाधन मुहैया हो, उस दृष्टिकोण से एक बड़ा निर्णय लिया गया है, इस बड़े निर्णय से आने वाले साल में जो सलेक्शन होगा, निश्चित रूप से उसमें वृद्धि होगी। बाकी परीक्षाओं में भी वृद्धि होगी। इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल जी द्वारा यहां पर अभिभाषण प्रस्तुत किया गया, मैं उसका समर्थन करता हूं। जिस प्रकार से सवा साल में पूरे छत्तीसगढ़ में चाहे हमारा किसान हो, महिला हो, विद्यार्थी हो, युवा हो, गरीब हो, उसके अलावा मैं उस चैप्टर को छोड़ दिया हूं, जो हमारे व्यवसायी हैं जिसके लिए हमने नई उद्योग नीति लाई, बाकी बहुत सारे कार्य किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 14 महीने के अंदर इस छत्तीसगढ़ में लोगों का विश्वास जितने काम किया है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। (मेजों की थपथपाहट) जो परीक्षा होती है, उसमें हमारा ग्राफ कहां पर है, उसमें मुख्यमंत्री जी ने परीक्षा दी, हमारे 10 नगर-निगमों में 10 के 10 महापौर भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए। (मेजों की थपथपाहट) मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यह मैनेजिबल नहीं, आम जनता को पूर्ववर्ती सरकार के उपर विश्वास नहीं था, हमको आम जनता के उपर विश्वास रहा, सीधे जनता के अधिकार का जो हनन हुआ था, इसलिए हमने पार्षद से ही जनता को अधिकार दिया और जनता ने अपने अधिकारों का उपयोग करके 10 महापौर का चयन किया है, थोड़े बहुत वोटों से नहीं किया, उन्होंने विशाल अंतर के वोटों से जिताया है। (मेजों की थपथपाहट) अगर हम नगरपालिका की बात करें, 49 नगरपालिका में 35 नगरपालिका के अध्यक्ष जीतकर आए। 114 नगर पंचायत में से 81 नगर पंचायत अध्यक्ष जीतकर आए। अध्यक्ष महोदय, एक भ्रम और दूर हुआ है। कांग्रेस आखिरी में EVM के उपर ठिकरा फोड़ती है, हम EVM के कारण हार गये, हमारा एक चुनाव पार्टी के द्वारा सिंबालिक रहा, दूसरा चुनाव सील मुहर से रहा। इस सील मुहर से जो चुनाव हुआ, आज की स्थिति में हमारे 33 जिला हैं, 30 जिला में हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे। हमको जिला में जनता का बहुमत मिला है। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, मैं अभी एक दिन के लिए घर गया

था। कल दो बजे तक निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से मिलता रहा, सरपंचों से मिलता रहा, जनपद सदस्यों से मिलता रहा। इस बार लोगों ने जिस प्रकार से आंधी उड़ाई, पेपरों में तो लिखा, भाजपा के सुनामी में कांग्रेस खो गयी, बह गयी, सुपड़ा साफ हो गया, पता नहीं क्या-क्या लिखा है। हम केवल सरकार नहीं चला रहे हैं, इसीलिए मैंने इस बात को इंगित किया है। सरकार के साथ हमने जनता का मन जितने का काम किया है, वे जैसा चाहते हैं, उनके अनुसार काम कर रहे हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही भोजन अवकाश के लिए अपरान्ह 03.00 बजे तक के लिए स्थगित।

(01.54 से 03.00 बजे तक अंतराल)

समय :

3.01 बजे

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमश:)

सभापति महोदय :- माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में 19 माननीय सदस्यों के संशोधनों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। संशोधन बहुत ही विस्तृत हैं, मैं पूरे संशोधनों को नहीं पढ़ूंगा, केवल संशोधन प्रस्तुतकर्ता सदस्यों के नाम तथा संशोधनों की संख्या को ही पढ़ूंगा। जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित होंगे, उनके ही संशोधन प्रस्तुत हुए माने जायेंगे :-

क्र.	सदस्य का नाम	संशोधनों की संख्या
1.	डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष	56
2.	श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य	21
3.	श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य	144
4.	श्री भोलाराम साहू, सदस्य	11
5.	श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य	30
6.	श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य	14
7.	श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य	42
8.	श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य	12
9.	श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य	15

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य द्वारा प्रस्तुत कृपज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर एक साथ चर्चा होगी। श्रीमती अनिला भेंडिया जी। (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती अनिला भेंडिया (डौंडी लोहारा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। आज सत्ता पक्ष के हमारे वरिष्ठ सदस्य ने बहुत बढ़िया भाषण दिया है, परंतु मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे सत्ता पक्ष के साथी मनमानी की बात करते हैं। अभी हम लोगों को मनमानी की बात देखने को मिली, जब त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई। प्राय: यह देखने को मिला है कि गांव में पंचायतों में पंच व सरपंच के चुनाव हुए तो हमारे प्रत्याशियों को यहां तक कि वहां पर घुसने भी नहीं दिया गया और उनके द्वारा दिये गये recounting के letter को भी स्वीकार नहीं किया गया और उनको फेंक दिया गया। इसी तरह कई जगहों में मशीनें भी खोली गईं, जबकि यह अपराध की श्रेणी में आता है। क्या यह बताने की बात है कि यह मनमानी बी.जे.पी. की सरकार कर रही है या कांग्रेस की सरकार कर रही है ?

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, मैं एक सेकण्ड बोलना चाह रहा हूं।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सभापति महोदय, अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है।

सभापति महोदय :- गजेन्द्र जी, आप इनको बोलने दीजिए।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, मैं वही बोल रहा हूं। मैं आपकी ही बात बोल रहा हूं। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं। आप मेरी बात सुन लीजिए। इनकी सरकार में जब भिलाई नगर-निगम में चुनाव हुआ था तो शाम को कोई दूसरा चुनाव जीता था और अगले दिन किसी दूसरे को प्रमाण पत्र दे दिया गया था। यदि आप ब्लेम कर रहे हैं तो पहले अपने पुराने कार्यकाल को देखिये, तब बात करिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, मनेन्द्रगढ़ में भी वही हुआ है। मनेन्द्रगढ़ में भी वही हुआ है। आपकी सरकार वही कर रही है। ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अभी आपकी सरकार में क्या हुआ है, आप इसको देखिये। अभी आप अपनी सरकार की बात करिये। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय :- गजेन्द्र जी, आप बैठिये।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सभापति महोदय, मनमानी की बात तो अभी यहां देखने को मिल रही है। जिला के जिला आप लोगों ने आदेश दिया है कि यहां पर कांग्रेसियों की बात न सुनी जाए। आज वही स्थिति है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में हमारे साथियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यहां तक विधायकों की बात भी नहीं सुनी गई। जो जिला निर्वाचन अधिकारी थे, उनके द्वारा बात

नहीं सुनी गई। तो क्या यह लोकतन्त्र है ? यहीं पर तो लोकतन्त्र की हत्या हो रही है। सरकार की ओर से हमारे माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा गलत बात को अभिभाषण के द्वारा कहलवाया गया है कि विकसित राज्यों की सूची में हमारा छत्तीसगढ़ है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। परन्तु आज क्या हो रहा है ? अमेरिका से हमारे भारतीय नागरिकों को कैदी की तरह बांधकर लाया जा रहा है। क्या यही हमारे भारत का विकास है ? क्या यही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकास है ? आप लोगो ने हमारे माननीय राज्यपाल महोदय जी के द्वारा गलत अभिभाषण कहलवाया गया है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल जी का छत्तीसगढ़ निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग भी उनको याद करते हैं, मेरे ख्याल से पूरे देश की जनता उनको याद करती है। परन्तु आज माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा क्या बुलवाया गया है ? कि कुल साल की बाधा से, कमजोरी से प्रगति रूक गई थी। अटल जी ने सदन में जो बात कही थी, शायद आप लोगों को याद नहीं है। आप लोग कहते हैं कि भारत का विकास नहीं हुआ। पहले जो भी सरकारें थीं, उन्होंने विकास किया, उन्होंने कम्पनियां बनाई, कालेज खोली, बड़-बड़ी फैक्ट्रियां बनवाई, तभी तो आज भारत यहां तक पहुंचा है, यह अटल जी का शब्द थे। अटल जी के इस वाक्य का आपकी सरकार में कोई असर नहीं पड़ रहा है। आप लोग खाली स्व. अटल जी का नाम ले-लेकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। परन्तु उनका जो गुण है, उस गुण को बी.जे.पी. का एक भी आदमी अपनाने का काम नहीं कर रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा अभी भी पूर्व की सरकार के कई स्वीकृत विकास के काम हैं, जिनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। क्यों ? द्वेष भावना की वजह से आप लोगों के द्वारा इस तरह का कार्य किया जा रहा है। जैसे कि मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2023-24 के बजट में कई विकास कार्य थे, वहां टेण्डर भी हो गया था, आप लोगों ने टेण्डर को भी निरस्त कर दिया। कई कामों का पैसा भी वापस बुला लिया गया। यह पूरे प्रदेश में हुआ है। आप लोगों ने द्वेष भावना की वजह से यह किया कि कांग्रेस की सरकार में स्वीकृत कार्य को करना ही नहीं है। क्या यही आपकी सरकार की नीति है ? क्या यही आपकी सरकार की योजना है ? आप लोग बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ऐसे कैसे सबका विकास होगा। यह आप लोगों की नीति है।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- सभापति महोदय, इनकी व्यापारियों के साथ सधी-बधी नीति थी और आज इन लोगों हमारी नीति पर प्रश्नचिन्ह उठा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि चुनावी प्रत्याशा में बगैर फण्ड के जो निविदा निकाली गई, उसको निरस्त तो होना ही था। उसमें नया क्या विषय है। अगर भ्रष्टाचार के दम पर 5 साल तक छत्तीसगढ़ को रोका नहीं गया होता तो छत्तीसगढ़ विकसित राज्य की तरफ बढ़ गया होता।

श्री रामकुमार यादव :- सबके विकास के बारे मा कुछ बोलिहा ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, वह अधोसरंचना, निर्माण, सारी जनता के लिए था। कोई हमारे कांग्रेस के किसी व्यक्तिगत व्यक्तियों के लिए नहीं था। आप लोगों ने इसको निरस्त करवाकर बहुत गलत किया है। तो आप लोग इसमें ऐसा कैसे कह सकते हैं ? आप लोग भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार बहुत कह रहे हैं। भ्रष्टाचार की बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं। मैं आज पेपर में पढ़ रही थी कि बिना निविदा, बिना टेण्डर के इतनी सड़कें बन गईं। मैं बिलासपुर साइड कहीं का पढ़ रही थीं।

श्री सुशांत शुक्ला :- वह तो आपके कार्यकाल को दैनिक समाचार-पत्र आज प्रकाशित कर रहे हैं। आपके समय तो अघोषित आपातकाल था।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- प्रकाशित कर रहे हैं तो कार्रवाई करो न, आपकी सरकार है।

श्री सुशांत शुक्ला :- आपके समय तो प्रेस के ऊपर अघोषित आपातकाल था।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- तो आप जांच करा लीजिये न।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आपकी सरकार है, कार्रवाई करो न, कार्रवाई करने से किसने रोका है ? आप में दम नहीं है, हिम्मत नहीं है, इसलिए नहीं कर रहे हो।

श्री रामकुमार यादव :- जांच कराओ, जांच कराओ।

श्री सुशांत शुक्ला :- क्योंकि आपकी सरकार, [xx][3] कैसे आता है, बताता हूं। विष्णुदेव के सुशासन (व्यवधान) श्री रामकुमार यादव :- ये खाली बोलत भर हे, जांच कराओ। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- सुशांत जी, बैठिये, बैठिये। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, दम की बात करते हैं तो जांच करवाईये न। दम की बात करते हैं तो जांच करवाईये। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- ई.डी. सी.डी. पी.डी. सबके जांच करवावा न। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- सुशांत जी, बैठिये, बैठिये। प्लीज बैठिये, बैठिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है (व्यवधान)। पूर्व मुख्यमंत्री जी में हैं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, की बात आई है तो वे जांच करवायें।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- बात हम लोगों से मत करिये।

सभापति महोदय :- बैठिये-बैठिये। अनिला जी, आप अपनी बात करिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अगर दिखाना है तो चलिये।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- हम लोगों ने और बहुत देखा है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, भरा शब्द विलोपित होना चाहिए।

सभापति महोदय :- अनिला जी बोल रही हैं। आप लोग बैठ जाईये।

---

[3][xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला किया गया।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, यह [xx][4] की बात हटवाई जाये। वे सदस्यों के साथ की बात कैसे कर सकते हैं?

एक माननीय सदस्या :- सभापति महोदय, वे की बात कर रहे हैं। उसको विलोपित करवाईये। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, यह गलत बात है। वे की बात कैसे कर सकते हैं? उसको विलोपित करवाईये। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- प्लीज, बैठिये। अनिला जी बोल रही हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय जी, वह बात विलोपित करवाईये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, पहले वह शब्द विलोपित होना चाहिए।

सभापति महोदय :- यदि कोई असंसदीय बात या भाषा है तो हम उसको स्वयं विलोपित कर देंगे। अनिला जी, आप बोलिये।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सभापति महोदय, हाल ही में आरक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियां देखने को मिली है। क्या यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है? यह भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। जब कांग्रेस सरकार कुछ करेगी तो भ्रष्टाचार है और आप लोग करे तो वाहवाही होती है, आप लोग पीठ थपथपाने का काम करते हैं। आप लोग यही काम कर रहे हैं। जनजाति संग्राहकों को वनोपज के अच्छे दाम मिल रहे हैं। कौन से दाम मिल रहे हैं? साल भर में आपने कितने वनोपजों की खरीदी की है? उस समय जब हमारी सरकार थी तो हम लोग कोदो, कुटकी, रागी सब वनोपज खरीदते थे। हम मिलेट की भी खरीदते थे, लेकिन आप लोगों ने साल भर से कोई जनजातियों को सुविधा देने का काम नहीं किया है। यह जनजाति लोग हमारे बस्तर में निवास में कर रहे हैं, सरगुजा में निवास कर रहे हैं। ऐसे लोगों का वनोपज जीविकोपार्जन करने का साधन है। ऐसे में भी आप लोगों ने साल भर से कोई खरीदी नहीं की है और आप लोगों के द्वारा यहां पर माननीय राज्यपाल से गलत भाषण दिया जा रहा है। वैसी आज हमारे किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखे हैं। किसानों को संतोष तब से है जब हमारी सरकार आयी थी। उस समय पूर्व सरकार ने किसानों के लिए 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की शुरूआत करना था तब आपके बैठे हुए सदस्य लोगों को क्या कहना रहता था कि एक एकड़ में 20 क्विंटल धान नहीं होता है तो कैसे खरीदेंगे? यह बात आप लोगों के साथियों के तरफ से आता था। आज आप लोग जो 3100 रूपये प्रति क्विंटल दर तय किए हैं वह पूर्व सरकार की देन है। अगर वह नहीं देते तो आज आपकी सरकार इतना पैसा कहां से देती और आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। पूर्व सरकार की जो देन है, उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। उसी तरह से हमारे किसानों को धान खरीदी में परेशानियां आईं। किसान भाईयों को बहुत-सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पूरे प्रदेश के कई किसानों ने अपना धान भी नहीं

[4][xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला किया गया।

बेच पाया है। टोकन की सीमा निर्धारित भी नहीं थी। टोकन हेतु जो ऑनलाईन व्यवस्था थी, उसमें कई केन्द्रों में इंटरनेट की थी व्यवस्था ठीक नहीं थी, कवरेज नहीं था, जिसके कारण किसान अपना धान नहीं बेच पाये और आप लोगों ने आदिवासी जल-जंगल-जमीन की कल्याण के संबंधित विशेष प्रयासों का यहां उल्लेख कर रहे हैं। उसी तरह से आप लोगों ने दुर्गम इलाकों में हमारे आदिवासियों को, मध्यम वर्ग के लोगों की रोजगार की बातें कर रहे हैं। आज आप लोगों ने उनको कौन सा रोजगार उपलब्ध कराया है? यह खाली कागजों में या यहां भाषण देने से ही नहीं होता, हकीकत धरातल में आनी चाहिए कि आपकी सरकार ने सालभर में कौन सी व्यवस्थाएं दी है, रोजगार दी है। वैसे ही आप लोग खेती-किसानी को हाईटेक करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, वह बहुत अच्छी बात है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अनिला जी, आप अच्छा बोल रही हैं। बस एक कमी है। आप कलकत्ता वाले सेठ का पता लक्ष्मी जी को बता देना। कोई आपत्ति नहीं है। वह सेठ भर का पता लक्ष्मी जी को बता देना। (हंसी)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप जानते हैं तो आप ही बता दीजिये। आप लोग खेती-किसानी को हाईटेक करने के लिये कार्य कर रहे हैं, अच्छी बात है । आपने अब तक कितने हाईटेक किये हैं और कहां किये हैं, सरकार ड्रोन दीदी की बात करती है, हमारे प्रदेश में कितने हैं, यह बताईये ? सभापति महोदय, कितने किसानों को वहां व्यवस्था दे पाते हैं, यहां चार-छैः जगह इस तरह की व्यवस्थायें हैं, क्या इस तरह से हाईटेक किसानी हो पायेगी, आपको इसे बढ़ाना चाहिये । सभापति महोदय, अगर एक ड्रोन दीदी को प्रायवेट कराते हैं तो 2200 से 2500 कीमत आती है, उस कीमत में कौन किसान इस कार्य को करा सकता है, सरकार को इस व्यवस्था को बढ़ानी चाहिये । सभापति महोदय, हाईटेक की बात यहां हो रही है, हमारे किसान यहां धान लगाये हैं और भी फसल लगाये हैं, उसमें जैविक उत्पादन हेतु बिचौलियों के पास खाद की व्यवस्था है, परन्तु शासकीय दुकानों में किसानों के लिये खाद की व्यवस्था नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं कि प्रदेश के हमारे किसान भाई खुश हैं ? सभापति महोदय, आज किसान खाद के लिये दर-दर भटक रहे हैं, उनको खाद नहीं मिल रहे हैं, किसान परेशान है । सभापति महोदय, आप लोगों कहते हैं कि किसानों को इतना लाभान्वित किया, इतनी धान की खरीदी हुई, बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में किसानों को जो खाद-बीज मिलना चाहिये, वह समय में नहीं मिल पाता है । सभापति महोदय, आप लोगों ने हमारी मॉ-बहनों के सशक्तीकरण की बात की है, महतारी वंदन बहुत अच्छी बात है, हमारे प्रदेश में महतारी वंदन योजना चल रही है, आप मान रहे हो कि बहनें बहुत खुश है, परन्तु वृद्ध महिला जिनको आप लोग 500 रूपये दे रहे थे, आप लोगों ने उसमें भी कटौती कर दिया? सभापति महोदय, उनको 1000 रूपये, 1500 रूपये मिलना चाहिये, उनका 500 रूपया काटकर उन्हें 1000 रूपया दे रहे हो ? हमारे कई भाई लोग बोल रहे थे कि महतारी वंदन योजना जो शुरू किया है, उसके बाद में तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है, न किसी को फार्म मिल रहा है ? सभापति महोदय,

नई बहू-बेटी आई हैं, वहां बहुत सारी व्यवस्थायें नहीं हो पा रही है, यह भी बात है और कई महिलाओं को मिलना चाहिये, उनको भी नहीं मिल रहा है, इसमें भी अनियमितितायें हुई है । सभापति महोदय, आपकी घोषणा के मुताबिक प्रदेश के हर घर के महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलना है, जो बचे हैं उन लोगों को भी फार्म भरवाकर इन योजनाओं को लागू करना चाहिये । सभापति महोदय, इसी प्रकार महिला, शिशु एवं बालक-बालिकाओं के लिये स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की निष्कृयता है । सभापति महोदय, प्रदेश में स्वास्थ्य केन्द्रों की हालत बद् से बद्तर है, वहां महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ भी नहीं है, शिशु रोग विशेषज्ञ भी नहीं है, आज स्थिति इतनी खराब है कि हमारे गांव से लोग रायपुर तक आते हैं, मेकाहारा में पता चलता है कि आयुष्मान नहीं चल रहा है, सरकार की योजनायें बंद हो चुकी है । आप लोग इसमें बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, जो धरातल में होनी चाहिये, उस चीज को करना चाहिये । सभापति महोदय, हमारी स्व-सहायता समूह की बहनों को आप महतारी वंदन तो दे रहे हैं, जैसे आपकी सरकार में चिटफंड कंपनियों ने लाखों लोगों के पैसे लूटकर चले गये थे, उसी तरह से हमारी कई महिला समूहों के बहनों को, कई एजेंट पैसा लेकर भाग गये हैं, उसके खिलाफ इस सरकार के कान में अभी तक जूँ तक नहीं रेंग रही है । सभापति महोदय, महिलाओं के साथ इस तरह कैसे सशक्तीकरण की बात हो रही है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, आप लोग उसके लिये कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं ? आप लोगों ने महिलाओं से वादा किया कि सिलेण्डर में 500 रूपया छूट देंगे, आप 1000 रूपये बढ़ा रहे हैं तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आपने जो बात रखी है कि गैस सिलेण्डर की सब्सीडी हम जल्दी देंगे, यह भी नहीं हो रहा है, इस तरह से महिलाओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं । सभापति महोदय, आप लोग उसी तरह रेल्वे नेटवर्क की बात कर रहे हैं, कितनी रेल्वे बंद हो गई है, आवागमन में लोगों को परेशानी हो रही है, कितने का टिकट वापस नहीं हुआ, कितने का पैसा वापस नहीं हुआ, बहुत सी अव्यवस्थायें हुई है । सभापति महोदय, आप रेल्वे के नेटवर्क विस्तार की बात करना तो छोड़ ही दीजिए, आपके डबल-ट्रिपल-चौबल इंजन की सरकार में यह संभव ही नहीं है कि आप रेल्वे की व्यवस्था को सुधार पायेंगे। सभापति महोदय, इसी तरह सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर में उड़ान योजना की सेवायें भी आपने शुरू कर दी है और पता नहीं व्यवस्था कब तक चलती है और कब चरमरा जायेगी, इस सरकार में इसका भी कोई भरोसा नहीं है।

सभापति महोदय, आप लोगों ने खनिज की भी बात की । प्रदेश में खनिजों का सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं होने के कारण छत्तीसगढ़ के भी राजस्व में कमी आई है क्योंकि आज हर क्षेत्र में परेशानी हैं । हम विपक्ष हैं, इसलिए हम लोग ही नहीं कह रहे हैं, पक्ष के साथियों से पूछिए कि उनके क्षेत्र में भी खनिज और रेत का कैसे दोहन हो रहा है ? यहां पर मेरे जिले की बात है, मैं नाम गिना दूंगी कि सत्ता पक्ष के सुख भोगी लोग नदी के रेत को निकाल-निकालकर गड्डा कर लिए हैं, मुरम वगैरह सब खतम कर दिए हैं । यहां किसी का नाम लेना उचित नहीं है इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, परन्तु मैं

यह दोषारोपण जरूर करूंगी कि सत्ता पक्ष के लोग मिलकर मेरे जिले में ऐसा काम कर रहे हैं । यह कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश खनिज सम्पदा राज्य है, पर कई जगह औद्योगिक क्षेत्र के नाम से लाखों पेड़-पौधा काट दिए गए हैं, जंगलों में हजारों प्रकार के जीव जन्तु रहते हैं, उन सबको आप लोग नष्ट कर रहे हैं । क्योंकि आप लोगों ने राज्यपाल महोदय से कहलवाया है कि हम लोग मां के नाम पर एक पेड़ लगा रहे हैं । यह बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मां के नाम पर एक पेड़ लगा रहे हैं, परन्तु आज हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में हजारों लाखों पेड़ अंधाधुंध कट रहे हैं, उसका कोई ईलाज नहीं है, पेड़ों की कटाई पर कोई रोक नहीं लगा रहा है । हंसदेव बांगों की जो कटाई है, वहां पर कितने आदिवासी लड़ रहे थे, कितने आदिवासियों को जेल में डाला गया, कितने आदिवासियों की बेरहमी से पिटाई की गई, परन्तु वहां पेड़ को काटने से रोकने का कोई उपाय नहीं किया गया। उसी तरह से आप लोग राज्य मार्ग बना रहे हैं, वहां भी इतने पेड़ पौधे कट रहे हैं, उनका कोई हिसाब नहीं है । गांव में हमारे किसान भाई सिंचाई हेतु नाली निकालने के लिए एक या दो पेड़ भी काट देंगे तो उसके लिए जुर्माना होगा और उसके लिए दुनिया भर का नियम बताएंगे । किसान के लिए वह चीज नहीं होगी, बाकी सभी चीजों के लिए आप पेड़ काट सकते हैं, हमारे गरीब किसानों के लिए पेड़ काटने में आप लोग रोक लगा देते हो ।

सभापति महोदय, ऐसे ही प्रदूषण की बात भी है । प्रदूषण भी यहां बेतहाशा हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनके ऊपर कोई फाईन नहीं है क्योंकि वे बड़े लोग हैं । वहीं गांव के गरीब लोग फैक्ट्री लगाएंगे तो उसके लिए आप फाईन करते हैं, परन्तु यहां बड़े-बड़े उद्योगपति लोग हैं, वे बिना नियम के फैक्ट्री भी लगाएंगे, कितना प्रदूषण होगा, उसका कितना धुंआ निकलेगा, फिर भी आप लोग उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे । राज्यपाल महोदय के भाषण कई जगह दिया गया है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना में इतना पैसा दिया गया है, विश्वकर्मा योजना में इतना पैसा दिया गया है । युवाओं को ट्रेनिंग कराने में आप लोगों ने इतना खर्च किया, परन्तु कितने लोगों को व्यवसाय दिया गया ?

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, सरकार के खिलाफ अईसे भाषण चलथे कि कौशिक जी ह सुत भूलईस हे ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सभापति जी, इतने ट्रेनिंग देने में लाखों-करोड़ों रूपए खर्च होते हैं, परन्तु आप लोगों ने कितने लोगों को व्यवसाय दिया, यह आप यहां बता दीजिए । आप लोग पूर्व सरकार की बहुत कमियां गिना रहे हैं, पर अभी आप लोग क्या कर रहे हैं ? सिर्फ ट्रेनिंग देने के लिए पैसा निकाल रहे हैं और ट्रेनिंग हो भी रहा है या नहीं, उसकी भी गारंटी नहीं है । ट्रेनिंग में कौन खा रहा है, कौन जा रहा है ? आपने 10-20 लोगों को ट्रेनिंग दिया है तो कम से कम उनके लिए व्यवसाय भी आना चाहिए । छत्तीसगढ़ में बहुत सी प्राकृतिक जगह है, जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को पर्यटन के क्षेत्र में

बहुत सुन्दर बना सकते हैं, हमारे आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं, पर इसके लिए बजट में बहुत कम पैसा रहता है, जिसके कारण न तो हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं और न हम यहॉ के पर्यटन को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में पर्यटन के क्षेत्र में शासन को आय के साधन बहुत हैं, परंतु ये सरकार सालभर से इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अभी बोल रहे हैं कि सरकार ने 9 हजार से अधिक रिक्त पदों की भर्ती आरंभ कर दी है, पर हमें तो कहीं नहीं दिखता। पहले हमारे बड़े भैय्या आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी शिक्षा मंत्री थे, आजकल उन्हें आप लोगों ने केन्द्र में भेज दिया, क्योंकि यहॉ ज्यादा बोलते थे, शायद इसलिए भगा दिए, तो वह शिक्षकों की भर्ती के लिए निकाले थे, आज तक उसका अता-पता नहीं है और जो भर्ती हुए थे, ऐसे हमारे 3000 शिक्षकों को आप लोगों ने निकाल दिया है। तो इसी प्रकार से आप युवाओं को रोजगार देंगे? यही छत्तीसगढ़ का विकास है? हमारे छत्तीसगढ़ में युवाओं को बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं।

सभापति महोदय, शिक्षा नीति में भी अभी आप अच्छा पकड़े कि 18 भाषा तो कौन सी 18 भाषा है? आप बोले ना कि बता दो, तो हम लोग भी जान लेंगे। 18 भाषा तो खैर हम लोगों को आती नहीं। हम लोगों को ज्यादा नहीं आता, सही बता रहे हैं। सरकार अगर बताएगी, तो 18 भी है, बोलते हैं, तो सुन भी लेंगे। शिक्षा क्षेत्र में बोल रहे हैं कि हम लोगों ने ये किया, वो किया, बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। परंतु एक स्कूल का पता चला है, आपको बता रही हूं कि दो टीचर थे, अऊ एक टीचर चुनाव लड़ डारिस, अऊ एक टीचर स्कूल बंद करके भाग गे। तो यही स्कूल की व्यवस्था है? अभी आदरणीय बड़े भैय्या कहत रहिस, आत्मानंद स्कूल, आत्मानंद जी की एक अच्छी सोच लेकर पूर्व सरकार ने काम किया था कि हमारे गांव के बच्चे इंग्लिस मीडियम में पढ़ेंगे, क्योंकि आज हर प्रतियोगी परीक्षा अंग्रेजी में होती है। चूंकि हमारा छत्तीसगढ़ अंग्रेजी में बहुत पीछे है, इसलिए यहॉ के बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में भी पीछे रह जाते हैं, यह अच्छी सोच लेकर स्कूल खोले थे, जिसे आप लोगों ने इसे शायद बदलकर पीएमश्री विद्यालय प्रारंभ कर दिया। अच्छी बात है। प्रधान मंत्री जी कुछ अच्छा फंड-वंड देंगे, तो अच्छी बात है, स्कूल अच्छा बढ़ेगा, पर ये भी है कि जो आत्मानंद है, उसे भी सरकार को फंड देना चाहिए।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, आत्मानंद स्कूल के नाम पर इधर की ईंट इधर का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा की तर्ज पर स्कूल खोले और फिर आ गए प्रधान मंत्री जी के ऊपर।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अरे, बढ़िया तो बोल रही हूं।

सभापति महोदय :- अनिला जी आपको निर्देशित की थीं ना बैठने के लिए, आप सम्मान कीजिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुन्डरदेही) :- सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ की प्राविण्य सूची में जितने भी नाम थे, सबसे ज्यादा स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चों के नाम थे।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- मैं तो प्रधान मंत्री जी की तारीफ कर रही हूं कि आप पीएमश्री कर दिये, तो अब तो समय से भक्कम पैसा मिलेगा। वहॉ अब चाक, पेंसिल की अटकलें नहीं आयेंगी। गुरुजी लोगों को इधर-उधर झांकना नहीं पड़ेगा कि आज चाक नहीं है, तो आज कॉपी नहीं है, तो आज पुस्तक नहीं है। अब पीएमश्री हो गया है, तो अब बम्फार आएगा। हर चीज पहले से। है कि नहीं? तो ये नीति शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों की है। पर ये भी कहना चाहूंगी कि आप ग्रामीण क्षेत्र में जाकर देखिए, बहुत बुरी स्थिति है। पूर्व की सरकार ने एक स्कूल जतन योजना चालू की थी। वह बहुत अच्छी योजना थी। पचासों साल से स्कूल भवनों में कोई रिपेयरिंग नहीं हुई थी, कभी कुछ नहीं हुआ था, उन कामों की रिपेयरिंग के लिए इसमें पैसा आया था, उस पैसे को भी आपकी सरकार के आते ही वापस कर लिया गया। तो ये तो फिर नन्हे-मुन्ने बच्चों के साथ अन्याय है।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, हमारी वरिष्ठ सदस्या जिस स्कूल जतन योजना की बात कर रही हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चूने में कलर मिलाकर पोते हैं और पलस्तर के नाम पर स्कूलों की क्या झिर्री उड़ रही है, यह तो अपने क्षेत्र में खुद जॉच करवा सकती हैं, प्रदेश की तो दूर की बात है। आप ढाई सौ करोड़ रुपए सिर्फ बिलासपुर संभाग में बर्बाद कर दिए। माननीय पूर्व मंत्री जी भी बैठे हैं, सदन में आरोप लगा सकते हैं। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- सभापति महोदय, यदि आपको लगा रहा है, तो आप जांच तो खुद ही करा सकते है। सभापति महोदय, ये हमेशा बिना तथ्य के आरोप लगाते हैं। जो माननीय सदस्या बोल रही हैं, सरकार आपकी है, आपको कहीं लग रहा है, तो आप जांच करा लीजिए। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- आप छोंड़िए, यही तो बताना चाह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आप जांच कराइए ना। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- आप जांच कराइए ना। (व्यवधान)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आपकी सरकार है ना, आप कराइए ना। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- जॉच होगी, तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई भी होगी। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- चलिये, जिसको जांच करानी है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में चलिये।

एक माननीय सदस्य :- माननीय सभापति महोदय, पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र में जाने के लिए कह दीजिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, इस सरकार को आये डेढ़ साल हो गये। यह बता दे कि इन्होंने कितने विधान सभा क्षेत्र में कितने स्कूल भवन स्वीकृत किये हैं ? यह बच्चों की बहुत बात करते हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, इतने घोटाले हैं कि जांच कराने के लिए 5 साल भी कम है। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- केवल सदन में बात करने से काम नहीं चलेगा।(व्यवधान) आप बताईये कि 15 सालों में कितने स्कूल भवन स्वीकृत किये हैं ? (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- क्यों 15 सालों में इतने ही घोटाले निकले थे ? आप इसे मत भूलिये।

सभापति महोदय :- बैठिये, बैठिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, इनकी सरकार की यह स्थिति है कि यह डेढ़ साल में मंत्री नहीं बना पा रहे हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, आप स्कूल भवन की बात छोड़ दीजिये। यह स्कूल के शौचालय नहीं बना पा रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, ये महाराज जी हर बात में खड़े हो जात हे। बिच्छी के जगह सांप के बिल में हाथ डाल देत हवव।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अनिला भेंडिया जी बहुत वरिष्ठ सदस्या हैं। वह प्रतिपक्ष की तरफ से बोल रही है। कृपया आप टोका-टाकी मत करिये। उनकी बातों को सुनिये।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार कम से कम चूना, सीमेंट तो पोतवाइस हे। तुहूं मन ओकरो बर कर देवव ना। वइसने करे बर कर देवव। पर वो योजना ला बंद काबर करे हव, में हर ये चीज ला पूछत हव ? आपने स्कूल जतन योजना को बंद क्यों कर दिया ? आपको उस योजना को बंद नहीं करना था। इसके अलावा जो कॉलेज, हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन के उन्नयन की बात थी, उसके लगे हुए टेण्डर को भी आप लोगों ने वापस कर दिया। यह कहां का न्याय है ? उन स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे। क्या उन स्कूलों में हम कांग्रेस के लोग जाकर बैठेंगे ? आप इसमें भी द्वेषपूर्ण भावना दिखा रहे हैं।

सभापति महोदय, वैसे ही यह आयुष्मान योजना की बात कर रहे हैं। आज कहीं पर, किसी भी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा है, सब जगह बंद है। आज मरीज भटक रहे हैं, गांव के लोग भटक रहे हैं। आज वे यहां आते हैं तो वहां जाओ, वहां जाते हैं तो यहां जाओ कह दिया जाता है। ब्लॉक स्तर के स्वास्थ्य केंद्र को रिफर सेंटर बन गये हैं क्योंकि वहां पर डॉक्टर नहीं हैं और यदि डॉक्टर हैं तो व्यवस्थाएं नहीं हैं और मशीनें नहीं है। तो फिर मरीज जाये तो किधर जाये ? उन्हें मजबूरी में प्रायवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है और प्रायवेट अस्तपालों में लाखों रूपयों का बिल आता है, जिसे चुकाने के लिये लोगों को अपनी जमीनों को बेचने की नौबत आ रही है। आप आयुष्मान कार्ड के लिये जल्दी से जल्दी उचित कार्रवाई कराये और उसका निराकरण करिये। क्योंकि यह स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात है।

सभापति महोदय, यह गैस कनेक्शन की बात कर रहे थे। इन्होंने लोगों को गैस कनेक्शन तो दे दिया है परंतु गांव में 1200 रूपये, 1500 रूपये का गैस सिलेण्डर कौन भरवायेगा ? सब पठउव्वा में टांग कर रखे हैं। उन लोगों के लिये लकड़ी ही जिंदाबाद है, वे तो लकड़ी को फूंक लेते हैं, उसी में उनका काम हो जाता है। आप धुंआ से मुक्ति की बात करते हैं। आप लोग चलिये, जंगल में जाकर देखिये कहीं पर मुक्ति नहीं मिला है। सब लोग आज भी लकड़ी जला रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने गैस सिलेण्डर में 500 रूपये की छूट भी नहीं दी है और जो गैस इतनी महंगी हो रही है, उसे सस्ती भी नहीं करा रहे हैं। जब आपकी डबल इंजन, त्रिपल इंजन की सरकार चल रही है तो अब तो आपको इसका निराकरण कर ही लेना चाहिए।

सभापति महोदय :- अनिला जी, थोड़ा संक्षेप में अपनी बात रखिये। आपको बोलते आधे घण्टे हो गये हैं।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सभापति महोदय, अभी तो में हर शुरू करे हव।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, यह हमारे दल की पहली वक्ता हैं।

सभापति महोदय :- मैंने कहा कि संक्षेप में अपनी बात रखिये। मैंने एकदम से बंद करने नहीं कहा।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सभापति महोदय, यह प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं। यह अच्छी बात है कि गरीबों को आवास मिलना चाहिए। आप लोगों को ग्रामीण स्तर पर कुछ देखने को भी मिल रहा होगा परंतु शहरी स्तर में आपको कहां प्रधानमंत्री आवास देखने को मिल रहा है ? आप लोग नगरीय क्षेत्र में आवास की बात करते हैं। आवास कहां है ? कौन से नगर पालिका, नगर पंचायत में आवास बने हैं ? मेरे तो एक भी नगर पालिका, नगर पंचायत में आवास स्वीकृत नहीं हुए हैं। आप लोग केवल बड़ी-बड़ी बात करते हैं। क्या आप लोग केवल मीडिया में छाये रहने के लिये या पेपर में छाये रहने के लिए ऐसी बातें करते हैं ? हमारे क्षेत्र में तो आवास स्वीकृत नहीं हुए हैं, इसलिए हम तो नगरीय क्षेत्रों की बात करेंगे। कहीं पर आवास स्वीकृत हुए ही नहीं है।

सभापति महोदय, आप लोग तेंदूपत्ता के बारे में बोल रहे हैं कि आपने चार हजार रूपये से दर बढ़ा दी। 4 हजार रूपये तक तेंदूपत्ता की दर किसने बढ़ाई थी ? पूर्व सरकार ने 4 हजार रूपये तक राशि बढ़ाई थी, तब तो आज आपने साढ़े पांच हजार रूपये किये हैं, नहीं तो आप कहां करते ? हमने ढाई हजार से बढ़ाकर 4 हजार रूपये किये थे, तब आप लोगों ने बढ़ाकर साढ़े पांच हजार रूपये किये हैं। इसमें भी पूर्व सरकार का बहुत बड़ा योगदान था। उसी तरह से आप लोगों ने सोलर सिस्टम की बात की। आप हर जगह सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, गांव में लगा रहे हैं, ऑफिसों में भी लगा रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। परंतु क्या आपने उसको कभी जाकर देखा है ? वहां पर उस कार्य को सुधारने के लिये न कोई फंड है, न आपके पास कोई मैकेनिक है, न ही वहां पर आपके कोई जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो गांव में

जाकर यह देखे कि यदि कहीं सोलर पंप या सोलर लाइट लगी है, तो क्या वह चल रहा है या वह जल रहा है या खराब हो गया है, इसे देखे। इसको सुधारने के लिए आपके पास न कोई फंड है, न ही आपके पास कोई अधिकारी है। आप लोगों ने माननीय राज्यपाल महोदय से बहुत बड़ी-बड़ी बातें कहलवायी हैं तो आप लोगों को इसके संधारण के लिए व्यवस्थाएं करनी चाहिए। तभी आपका यह सोलर सिस्टम स्थापित करने का लक्ष्य सफल होगा।

माननीय सभापति महोदय, आप लोगों ने बहुत से गांवों में सड़कें बनाने की बात की है, आप लोग बहुत से गांवों में पुल-पुलिया बनाने की बात कर रहे हैं। परन्तु मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगी कि कम से कम जो बजट में आया है, उसकी तो प्रशासनिक स्वीकृति दे दीजिए। प्रदेश के बहुत से गांवों में पुल-पुलिया का निर्माण करना बहुत जरूरी है क्योंकि कई गांवों में जहां पर बच्चे नदी की दूसरी ओर आंगनबाड़ी जाते हैं, और उस तरफ अपने स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। जहां पर पुल-पुलिया का निर्माण करनरा बहुत जरूरी है, जो बजट में आया है, लेकिन आप लोग उसकी भी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। बजट में आने के बाद भी आप उसकी प्रशासनिक स्वीकृति क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रदेश में सड़कों की स्थिति बहुत जर्जर है। पूर्व सरकार के द्वारा अधोसंरचना मद में जो काम चल रहे थे, केवल वही काम हुए हैं। उसके बाद साल भर से आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से किसी पंचायत में एक ईंट रखने तक का काम नहीं हुआ है। यहां पर आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हम प्रदेश की जनता का भरोसा जीत रहे हैं। आप इतना भी जीत का गुरूर न करिये क्योंकि 5 सालों बाद आपका यह गुरूर टूट जाएगा। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण का विरोध करते हुए, अपनी बात समाप्त करती हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं श्री धरमलाल कौशिक जी द्वारा रखे गए कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर सदन में माननीय राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण दिया है, वह सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, बल्कि वह इस सरकार की इच्छाशक्ति का प्रतीक है।(मेजों की थपथपाहट) हमारी सरकार के द्वारा जो क्रांतिकारी निर्णय लिये गये थे या आगे लिये जाने हैं, उनका यह दस्तावेज है। मैं यह भी कह सकता हूँ कि यह अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा है, जिसे हमने छोड़ा है और इस प्रदेश में लव और कुश भी यह नहीं बन सकते, जो उसको रोक सके। (मेजों की थपथपाहट) इस प्रदेश में यह घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है क्योंकि इसके पीछे माननीय मोदी जी की गारण्टी है । हमारे गरीब आदिवासी परिवार का जो सुदूर वनांचल के बेटे माननीय विष्णु देव साय जी हैं, इस प्रदेश को उनका सबल, सफल, शांत और सरल नेतृत्व मिला है। मैं इस सदन में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ही देख रहा हूँ कि पहले दिन से ही माननीय विष्णु देव साय जी को विरोधी दल के लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं।

मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसलिए उनको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह आदिवासी का बेटा है। इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बनकर, इतने बड़े-बड़े कार्यों को कैसे कर रहा है ?(शेम-शेम की आवाज) लेकिन आपको इस हकीकत को मानना होगा कि श्री विष्णु देव साय बेहद अनुभवी नेता हैं। आज जो भाजपा शासित राज्य के भी मुख्यमंत्री हैं, उनसे वह वरिष्ठ हैं और उनको अनुभव है। यहां पर जो पीड़ा दिख रही है जिसे वह हल करना चाहते हैं। उन्होंने उस पीड़ा को देखा, भोगा और सुना भी है। इसलिए वह तत्पर होकर गांव, गरीब और किसानों की कल्याण की बात कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमने इस प्रजातंत्र के मंदिर में 25 वें रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किया है। मुझे इस बात का सौभाग्य है कि जब वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना तो हमारे पास बैठने की जगह भी नहीं थी। हम लोगों ने राजकुमार कॉलेज के जशपुर हाल में टेंट में विधान सभा का सत्र लगाया। माननीय विधान सभा अध्यक्ष के रूप में पंडित राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल थे। वहां उस सदन में हम सब थे। वहां से छत्तीसगढ़ का सफर शुरू हुआ और आज इस सदन में हम बैठे हैं और आगे भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय विधान सभा अध्यक्ष के नेतृत्व में अपनी नई विधान सभा को बनते हुए हम लोग देखकर के आये हैं। छत्तीसगढ़ उसी तेजी से आगे बढ़ते हुए आगे बढेगा। इसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है। यह जानते हुए भी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, उन्होंने प्रदेश को बनाया। यह पूरी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए..।

श्री विक्रम मंडावी :- धर्मजीत भैया, उस समय आप भी इधर ही थे।

श्री धर्मजीत सिंह :- हॉ, मैं था न। मैं कहां इंकार कर रहा हूं। मैं बता ही रहा हूं कि वर्ष 2000 में यहीं था। 25 साल हो गये हैं। अटल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए और अटल जी के आदर्शों से प्रेरणा लेकर काम करने के लिए सुशासन की दिशा में, सुशासन पुरूष के उसमें सरकार ने रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। (मेजों की थपथपाहट) मैं राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में जो सबसे पहला प्रश्न उठाऊंगा, कालम 55 और 56 में है कि राम का ननिहाल हमारे छत्तीसगढ़ में है। राम के बारे में नवधा रामायण और राम की भक्ति गांव-गांव में होती है जिसमें आप सब भी अतिथि बनकर जाते हैं। उसी राम के प्रति आदर भाव प्रकट करने के लिए जब 500 साल की जद्दोजहद के बाद भगवान श्रीराम का मंदिर अयोध्या में बना, उस मंदिर में दर्शन के लिए हम अपने धर्मप्रेमी छत्तीसगढ़ के भाईयों और बहनों को भेजने का कार्य कर इस सरकार ने पुण्य का काम किया है। (मेजों की थपथपाहट) राजनीति में अगर धर्म का समावेश नहीं होगा तो वह राजनीति जनता के कल्याण के काम नहीं आती है। इसलिए हम छत्तीसगढ़ की जनता को वहां पर भेजने का काम किये हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में छत्तीसगढ़ का 5 एकड़ में पैवेलियन बना। उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के हजारो लोग रूके, भोजन प्राप्त किये, कुंभ का स्नान किये। यह छत्तीसगढ़

सरकार की धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, यहां की संस्कृति के प्रति, एकता के प्रति और इस छत्तीसगढ़ की अस्मिता के प्रति आस्था है कि महाकुंभ में भी छत्तीसगढ़ का मंडप सजा हुआ था। हम लोगों को माननीय विधान सभा अध्यक्ष महोदय हवाई जहाज में ले करके कुंभ गये। उन्होंने कुंभ जाने के लिए सभी को आमंत्रित किया जिसमें आप लोग भी थे। आप लोग नहीं गये। आप 5-7 लोग गये थे, बाकी सब नहीं गये। एक पूर्व मुख्यमंत्री जी ने यह कह दिया कि तीर्थ यात्रा में अपने पैसे से जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय महोदय, हमारे देश की, हमारे प्रदेश की, गांव की परंपरा है कि कोई भी मोहल्ले का भी आदमी ले जाता है तो उसके साथ तीर्थ जाते हैं। उसको पैसा नहीं देते हैं। फिर मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसा बोलने वाले लोग जरा मुझे यह बतायें कि सरकार के पैसे से हज की यात्रा में आपकी जुबान नहीं खुलती है। सरकार के पैसे हज भेजे जाने वालों के बारे में आप एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम कुंभ जाते हैं तो आप कुंभ में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि आपकी पूरी पार्टी धर्म विरोधी, हिन्दु धर्म विरोधी, कुंभ विरोधी, भगवान राम की विरोधी है। यह सब ठीक नहीं है। इनकी पार्टी का भगवान मालिक है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। दिल्ली में चुनाव होता है, शून्य। महाराष्ट्र, हरियाणा में चुनाव होता है, वहां हार गये। यहां नगर निगम, ग्राम पंचायत के चुनाव में हार गये। आपकी पार्टी तो अभी आई.सी.यू., कोमा, वेन्टीलेटर में है। पहले उससे निकलने का इतंजाम करिये। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बर्दाश्त करने की क्षमता पालिये। आपके एक नेता खड़े होकर बोल दिये कि एक महिला वंदन के सिवा इसमें और क्या नया है। इसमें क्या नया नहीं है और कौन सी पुरानी चीज का करें, अभी मैं बता देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हज के लिए जो सरकारी पैसा जाता है, उसमें इनको आपत्ति नहीं होती है लेकिन अगर प्रयागराज और कुंभ जाने के लिये या अयोध्या जाने की बात आ गयी तो आपको तकलीफ होने लगती है क्योंकि आप हजवालों के भरोसे में ही राजनीति कर रहे हैं । (शेम-शेम की आवाज) आप जब तक हजवालों के भरोसे में राजनीति करोगे तब तक यही हाल रहेगा जैसा अभी है ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, बहुत अच्छा बोलत रिहिस हे, हमू वहां नहाय बर गे रहेन । साहब के संग मैं भी नहाय बर गे रहेओं लेकिन एक बात है । हम राम के भी सम्मान करत हन अउ जिंदगी भर करत रहिबो लेकिन छत्तीसगढ़ में गुरू घासीदास बाबा जी के जैतखाम ला टोरे-फोरे जाथे तेकर एमन ओला जांच करथे तेला जेल भेज देथे । ऐमन का बात करही ? (व्यवधान) छत्तीसगढ़ में गुरू घासीदास बाबा जी के जैतखाम ला... (व्यवधान)

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- ता का होगे संगवारी भाई हो, ओ जैतखाम ला कौन हर तोड़िस ? (व्यवधान) तोरे विधायक साथी रिहिस हे । (व्यवधान) जैतखाम ला तोड़े के जांच होईसे हे । (व्यवधान)

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

सभापति महोदय :- चलिये, बैठ जाईये ।

श्री नीलकंठ टेकाम :- आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं । धर्म के नाम पर राजनीति करना चाह रहे हैं ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- गुरू घासीदास बाबा के जैतखाम को तोड़ने वाले (व्यवधान) को सरकार जेल भेज रही है, आपको विरोध करना चाहिए ।

सभापति महोदय :- माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, धर्म के नाम पर कौन राजनीति कर रहा है यह तो पूरे देश की जनता देख रही है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- पुलिस विभाग की कार्यवाही से तय हो गया है और समाज यही मांग करता रहा कि फर्जी आरोपी की जगह में वास्तविक आरोपी को जेल भेजें । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- धर्म आधारित ही होना चाहिए, राजनीति तभी सफल होती है । महात्मा गांधी ने रामराज्य लाने के लिये बात की, आप बोलिये कि महात्मा गांधी जी गलत हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- राम ले ज्यादा तुमन हमन ला मानिहा, मोर नाम खुद रामकुमार हे । मोर ददा हा राम भगवान ला कतका मानय । मोर नाम ला राम भगवान के नाम से रख देहे हे, (व्यवधान) ऐमन का बात करही । तुमन केवल धर्म के नाम पर राजनीति करने वाला हव । एक-दूसरे ला लड़ाने वाला हव । गुरू घासी दास बाबा जी के जैतखाम के रक्षा नइ कर पात हे ।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप बैठिये । धर्मजीत जी आप अपनी बात करिये ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप जब विधायक नहीं बने थे तब से हम लोग जानते हैं कि उस महान जैतखाम का निर्माण डॉ. रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब कराया गया था । आप लोग क्या बतायेंगे ? (मेजों की थपथपाहट) आप लोग तो पोताई भी नहीं करा सकते हो, जैतखाम-जैतखाम कर रहे हो । पूज्य बाबा गुरू घासीदास के लिये, अभी उसकी तरक्की के लिये वहां पर विकास के लिये भी इस सरकार की सरफ से संकल्पबद्ध कार्यक्रम आ रहा है उसका निर्माण छत्तीसगढ़ की डॉ. रमन सिंह की सरकार ने कराया था । (मेजों की थपथपाहट) आप लोगों का इसमें कहां रोल है ?

श्रीमती शेषराज हरवंश :- खाली बनाये ले नइ होए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, किसी भी प्रदेश के विकास के लिये राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास बहुत जरूरी है और वर्ष 2024-25 में राज्य मद के 899 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा किया गया । केंद्रीय सड़क निधि के तहत् वर्ष 2024-25 में 1204 करोड़ रूपये के 17 कार्य स्वीकृत किये गये । धनबाद और विशाखापट्टनम जैसे शहरों को जोड़ने के लिये एक्सप्रेस-वे तैयार किया जा रहा है । सरगुजा-बस्तर और बिलासपुर में हवाई उड़ान योजना अंतर्गत विमान सेवाएं शुरू की गयी हैं । क्या आपको लगता है कि हवाई जहाज नहीं उड़ना चाहिए ? आपको क्या लगता है कि वहां की हवाई सेवा आरंभ करने के लिये यह सरकार प्रयास नहीं कर रही है, यदि आपको हर चीज में बुराई

दिखेगी तो ऐसे में... ।

श्री विक्रम मण्डावी :- धर्मजीत भैया, जगदलपुर वाला हवाई सेवा बंद हो गया।

श्री धर्मजीत सिंह :- बंद हुआ होगा ।

श्री लखेश्वर बघेल :- यह सरकार आने के बाद बंद हो गया । हमारी सरकार में 5 साल चला, आपकी सरकार आने के बाद बंद हो गया, इसको भी बता दीजिये ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं कहां इंकार कर रहा हूं कि बंद नहीं हुआ होगा लेकिन एक प्रयास जारी है, उसको रेगुलर कैसे करना है उसके लिये प्रयास जारी है । उसमें कई किस्म की टेक्निकल समस्याएं रहती हैं, कई प्रकार का बीड होता है, कई प्रकार का आक्शन होता है, कई प्रकार का कम्पनसेशन देना पड़ता है, यह चीज कोई सरकारी ऑर्डर से हवाई जहाज उड़कर नहीं जाता है । जो एलायंस कम्पनी वाले हैं, एयरलाईन कंपनी वाले हैं, उनको सरकार करोड़ों रूपये का क्षतिपूर्ति देती है, चलाने का प्रयास हो रहा है और यह विकास की दिशा में एक बहुत सकारात्मक पहल है । रेल के बारे में नेता जी ने बोल दिया । रेल बंद हो गया, हो गया । आप जब घर बनवाते हैं तो क्या उसी घर में रहते हैं ? जब घर बनता है तो कहीं थोड़ी देर के लिये बाहर रहना पड़ता है । रेल की लाईन बिछाई जा रही है उसमें आप पैसेंजर ट्रेन चलाकर लोगों की जान-माल की हिफाजत करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं ?

श्री रामकुमार यादव :- कोयला वाला भागत हे।

श्री धर्मजीत सिंह :- भाई, सुन सीरियस मैटर हे।

श्री रामकुमार यादव :- भाई, कोयला वाला भागत हे न।

श्री धर्मजीत सिंह :- रेलवे का 26 परियोजनाओं के माध्यम से 2768 किलोमीटर।

श्री उमेश पटेल :- सुनिए न भैया, ट्रेन की क्या स्थिति है? कितने एक्सीडेंट हुए हैं? इसमें तो मत बोलिए। पूरा देश जान रहा है। आपके मंत्री आते है, आंसू बहा देते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, नहीं, मैं तो स्वीकार भी नहीं कर रहा हूं न। मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन खुश पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा।

श्री उमेश पटेल :- उसको छोड़ दीजिए। उस विषय से आगे बढ़ जाइए।

श्री धर्मजीत सिंह :- बिलासपुर के स्टेशन का पुनर्निर्माण हो रहा है, विकास हो रहा है। एक तो मेरे उसलापुर का भी हो रहा है। उसलापुर स्टेशन जो एकदम कचरा रिजेक्टेड पड़ा था, उसको बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने पैसा दिया है। (मेजों की थपथपाहट) एक अंडर पास भी बन रहा है, जिसमें लोग गुरू अमेरिकी लोग जाएंगे। अब आदरणीय भाभी जी कहां चली गयी? आज बहुत बढ़िया भाषण दी हैं। मैं इतने दिन के 10 साल से उनके साथ विधायक के रूप में मतलब 6 साल से तो हूं। मंत्री थीं तो उनका कॉन्फिडेंस कमजोर था क्योंकि इधर से रेडी टू ईट वाला मामला आते रहता था। उनका आत्मबल थोड़ा कमजोर था, लेकिन आज वे बहुत ही आत्मविश्वास से भाषण दे रही थीं। मुझे उनके भाषण को सुनकर

बहुत प्रसन्नता हुई। आपकी जो लोकप्रिय सरकार थी, आपने ये रेडी टू ईट को महिलाओं से लूट लिया था। हमने दिया।

श्री रामकुमार यादव :- कहां दिया?

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, दिया।

श्री रामकुमार यादव :- कागज में दिया।

श्री धर्मजीत सिंह :- कागज में नहीं सिर्फ चार जिले में दिया।

श्री रामकुमार यादव :- चुनाव में दिया।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, दिया। अब देखिए, उस कलकत्ता वाले सेठ को तो नहीं दिया। (शेम-शेम की आवाज) कलकत्ता वाले सेठ को तो नहीं दिया।

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता जी सुन रहे हैं। ये रामकुमार जी को 1 दिन के लिए मुझे आप लोग दे दीजिए, मैं उनका परीक्षण कराना चाहता हूं। (मेजों की थपथपाहट) पूरे ढंग से उनका परीक्षण कराना चाहता हूं कि कुछ हुआ तो नहीं है, वे बार-बार उठ रहे हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- हम एक सप्ताह के लिए आपको दे देंगे।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- नेता जी पहली हॉस्पिटल ला ठीक कर लेबे ओखर बार परीक्षण करवा लिहौ। हॉस्पिटल मन के बुरा स्थिति हे। कहां ठीक हो पाही।

श्री उमेश पटेल :- एखर बिहाव घलो करवा देबे। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- हमारे नेता प्रतिपक्ष, इतने सीनियर नेता बैठे हैं, वे सुन रहे हैं, आप लोग नहीं सुन रहे हो, थोड़ा सुन तो लेने दीजिए। मैं तो उन्हीं को देख कर बोल रहा हूं। आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं। रेडी टू ईट वाली हमारी भाभी जी चली गईं। कौन कलकत्ता वाला यहां प्रकट हुआ? अचानक बीज निगम में बैठक होती है। क्या-क्या सब सेटिंग होती है? महंत जी, हम लोग आपको तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो बिल्कुल पाक साफ तरीके से थे न, वहां बैठे थे। पर दरबार में आप भीष्म पितामह की कुर्सी पर बैठे थे। आप कुछ बोल भी नहीं पाते थे और आपके सामने में द्रोपदी का चीरहरण होता था। कई किस्म के मामले हो जाते थे, पर आप कुछ बोल नहीं पाते थे, पर आप इन सब पापों से दूर थे। माननीय सभापति महोदय, कलकत्ता का आदमी आता है। (मेजों की थपथपाहट) कलकत्ता का आदमी रेडी टू ईट ले जाता है। बीज निगम यहां ठीक से बीज देने का काम नहीं कर सकते। बताइए इन बच्चों को क्या खिलाये होंगे और क्या दिए होंगे? भगवान ही मालिक है। आप लोगों ने क्या रेडी टू ईट को भी कमाई का जरिया बनाकर रखा थ। ये बहुत ही आपत्तिजनक है और इन्हीं सब चीजों का भुगतान तो भुगतना पड़ रहा है न? नगरीय निकाय चुनाव हुआ। राज्य में तो पहले डायरेक्ट चुनाव होता था। इन लोगों ने नियम बदल दिया। पार्षद वाला करो, पार्षद पार्षद खेलेंगे और थानेदार, दरोगा, पुलिस कप्तान,

ये पकड़ कर पार्षद ले आए। भेड़, बकरी के समान बंद किये, मेयर बन गया। 10 में 10 मेयर बने। मेयर ऐसे बनते हैं जहां पर जनता वोट डालती है और जनता के वोट की गिनती होती है। (मेजों की थपथपाहट) 10 के 10 मेयर हम जीतकर आए। ये है चुनाव। ये है प्रजातंत्र के प्रति आस्था। ये है प्रजातंत्र के प्रति सम्मान कि जनता को अधिकार दो कि वह अपना प्रतिनिधि खुद चुने।

श्री उमेश पटेल :- भैया, आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं? ये अपना-अपना सोचने का तरीका हो सकता है। आप सही, आप गलत कोई भी हो सकता है। अगर यही है तो फिर मुख्यमंत्री का सीधा चुनाव क्यों नहीं कराते? जिला पंचायत का सीधा चुनाव क्यों नहीं कराते ?

श्री धर्मजीत सिंह :- यही तो बात है न। आपके नेता दिल्ली के यही कहते हैं कि मोदी जी किसी दिन डायरेक्ट इलेक्शन करवा देगा? लो मोदी जी खड़े हैं, आप राहुल गांधी को खड़े करिए, दोनों में वोट पड़ेगा क्या हाल होगा, क्या हाल होगा समझे हो? (मेजों की थपथपाहट) आप कहां जाओगे? मोदी जी और राहुल गांधी दोनों देश के नेता के रूप में चुनाव लड़ेंगे, जनता किसको वोट देगी? मोदी जी को ही देगी न? उसे कहां से देगी? उसको कहां से देंगे? आलू से सोना निकालने वाले को नहीं देंगे।

श्री उमेश पटेल :- आलू से सोना कौन निकाला था, मैं बताउंगा। अभी इसके बाद मेरा भाषण है, उसी पर बात करूंगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- आलू से सोना बनाने वाले को कौन वोट देगा? (हंसी) सभापति जी, छत्तीसगढ़ शक्ति पूजा का केन्द्र है । यहां हमारी कई माताएं विराजमान हैं । दंतेवाड़ा, बम्लेश्वरी, चंद्रहासिनी, महामाया वगैरह वगैरह । हमारी सरकार यह मानती है कि नारी की पूजा नहीं होती वहां देवता भी नहीं आते और जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता विराजते हैं और इसलिए छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाओं को उस गरीब परिवार का बेटा जो मुख्यमंत्री बना है, उसने सबसे पहला आदेश किया कि हम एक-एक हजार रूपया महीना गरीब माताओं, बहनों को देंगे । यह सरकार अपने वायदे पर अडिग है और आज जब मैं बोल रहा हूं एक-एक पैसे का भुगतान हमारी माताओं और बहनों को हमारी सरकार ने किया है । (मेजो की थपथपाहट) आप जैसे नहीं कि किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना में देंगे बोले और उसको चार बार में देते थे ।

श्री विक्रम मंडावी :- अभी कितने हिस्से में दे रहे हैं ?

श्री धर्मजीत सिंह :- हम किसानों की भलाई सोचते हैं । 25 लाख 49 हजार किसानों से 149 लाख, 25 हजार मेट्रिक टन धान खरीदा । 5 लाख 62 हजार भूमिहीन किसानों को 10-10 हजार की राशि दी । किसान सम्मान निधि से 24 लाख 31 हजार 993 किसान लाभान्वित हुए । किसानों की संख्या बढ़कर 25 लाख 9, 514 हो गई । इस तरह से 77,500 से अधिक नए किसान योजना से लाभान्वित होने के दायरे में आए हैं । 14 महीने में 1 लाख करोड़ की राशि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों के खाते में गई और 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से हमने धान खरीदा और न

केवल खरीदा, आप लोग चिंता जाहिर कर रहे थे कि पैसा नहीं मिल रहा है, एक-एक पैसा किसानों के खाते में पहुंच चुका है । यह वो सरकार है (मेजो की थपथपाहट) । हम बगैर किसानों के जी भी नहीं सकते, हम बगैर किसानों की तरक्की के छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ा भी नहीं सकते । यही वह सरकार है जिसने 68 लाख परिवारों को 5 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है । हम रोटी का भी इंतजाम करते हैं, तरक्की का भी इंतजाम करते हैं । रोटी, कपड़ा और मकान फिल्म सरीखे मकान का भी इंतजाम करते हैं । 68 लाख परिवारों को 5 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय इस सरकार ने लिया है ।

सभापति महोदय, जल जीवन मिशन में तो लागू होने के पहले ही जेल रोड में बंगला था, वहां पर लम्बा चौड़ा लेनदेन हुआ । पैसा वैसा खा गए तो सब ठेकेदार, यही बोल दिया था विधान सभा में चोर-उचक्के टाइप के सब ठेकेदार काम ले लिए थे, इसीलिए जल जीवन मिशन अस्त-व्यस्त और त्रस्त है, उसको सब ठीक करेंगे । तेंदूपत्ता में अभी 52 लाख संग्राहकों को 5500 रूपए की दर से भुगतान किया जाएगा ।

सभापति महोदय, नक्सल समस्या के बारे में बहुत बात आती है । नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में हमारे देश के गृह मंत्री का दो-तीन बार दौरा हुआ । उनके मार्गदर्शन में यह तय हुआ है और कोशिश जारी है कि 2026 तक नक्सली हिंसा को प्रदेश से समाप्त किया जाए और उसी दिशा में 14 महीने की अवधि में बहादुर जवानों के द्वारा 300 से अधिक नक्सली मार गिराए गए हैं, 972 नक्सली आत्म समर्पण कर चुके हैं, 1183 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं । आत्म समर्पित नक्सलियों के तथा नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए पुनर्वास नीति के तहत् 15 हजार प्रधानमंत्री आवास देने जा रहे हैं । नक्सल प्रभावित 26 गांवों में पहली बार ध्वजारोहण हुआ है । यहां त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन में सुकमा जिले के पेंटाचिमली, केरलापेंदा, दुलेड, सुन्नम गुडा और पुवर्ती जो कि एक नक्सल लीडर का गांव है, वहां पहली बार मतदान हुआ । सुकमा जिले के चिंतागुफा स्वास्थ्य केन्द्र में इलाज की बढ़िया सुविधा मिल रही है। 19 साल बाद दंतेवाड़ा जिले के पोटाली गांव में पुन: स्वास्थ्य सेवा प्रारंभ की गई। सभापति महोदय, मैं इसमें कुछ आंकड़े और पढ़ना चाहता हूं। 1 दिसंबर, 2023 से 26 फरवरी 2025 तक मृत नक्सलियों की संख्या 305 है। वर्ष 2019 से 2023 तक सिर्फ 219 थी। (मेजों की थपथपाहट) बस्तर के अति संवेदनशील...।

समय :

04.00 बजे

श्री द्वारिकाधीश यादव :- धर्मजीत भैया, 15 साल वाला पहले का आंकड़ा बताईए न।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, अति संवेदनशील 46 मतदान केन्द्रों में पहली बार मतदान हुआ। बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर के अतिसंवेदनशील 26 नक्सल गांव में गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस

के अवसर पर झंडा फहराया गया। नक्सल उन्मूलन के लिए ऑल इंडिया रेडियो में स्थानीय भाषा में प्रचार-प्रसार करके उनसे जुड़ने की कोशिश हो रही है। 10 हजार रूपए प्रतिमाह 3 वर्ष तक दिये जाने का प्रावधान है। पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना करके समर्पण किये जो रहे नक्सलियों को भी प्रधानमंत्री आवास के तहत् आवास का प्रावधान है। सुरक्षाबलों की प्रभावी कार्रवाई के फलस्वरूप माओवादी घटनाओं में व्यापक कमी आई है। नवीन सुरक्षा कैंप 1 वर्ष 2 माह में 53 फारवर्ड सुरक्षा कैंपों की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित 4 अतिरिक्त CRPF बटालियन एवं उपलब्ध CAPF कंपनियों के रिप्लायमेंट द्वारा क्षेत्र में 22 एवं मानक्षेत्र में 9 नवीन कैंपों की स्थापना की गई है। एक वर्ष 2 माह में सड़क और पुल का निर्माण हुआ है। RRP एवं RCPLWEA योजना अंतर्गत 49 मार्ग 238 किलोमीटर और 9 पुल का निर्माण हुआ है। मोबाईल टॉवर एक वर्ष दो माह में 525 में से 325 अपग्रेड कर दिए गए हैं। NIA और SIA 18 नवीन प्रकरण दर्ज करके राज्य अन्वेषण ब्यूरो के साथ 14 प्रकरण सौंपे गये हैं। सुरक्षाबलों द्वारा आयोजित अभियानों, माओवादी सप्लाई नेटवर्क के विरूद्ध भी कार्रवाई की जा रही है, माओवादी कार्यक्रम की समीक्षा भी की जा रही है। नियद नेल्लानार कार्यक्रम के तहत् बस्तर के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, उन्हें मूलधारा में जोड़ने के लिए 15 फरवरी, 2024 को नियद नेल्लानार पहल की घोषणा की गई। मैं इसका उद्देश्य भी बता देता हूं। बस्तर में घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाकर ग्रामीणों के बीच परस्पर विश्वासपूर्ण संबंधों का आधार तैयार करना है। जिला सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर में नये स्थापित सुरक्षा कैंपों के आस-पास 5 किलोमीटर की परिधि में 16 विभागों की भागीदारी से 25 व्यक्तिमूलक योजनाओं और 18 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। मैं आधारभूत जानकारी देना चाहता हूं। दंतेवाड़ा में दो कैंप हैं, स्थापित सुरक्षा कैंपों के अंतर्गत ग्रामों की संख्या 6 है। बीजापुर में 16 कैंप है, सुरक्षा कैंपों के अंतर्गत ग्रामों की संख्या 53 है। सुकमा में 12 कैंप हैं, गांव की संख्या 40 है। नारायणपुर में 7 है, गांव की संख्या 19 है। कांकेर में 1 कैंप है, गांव की संख्या 7 है। प्राथमिक शाला इन क्षेत्रों में 64 है, प्राथमिक शाला खोलने का लक्ष्य है, उसमें से 23 नये प्राथमिक शाला स्वीकृत तथा 5 स्थापित किये गये हैं। (मेजों की थपथपाहट) उचित मूल्य की दुकान 41 लक्ष्य है, उचित मूल्य की दुकान 41 स्वीकृत है, 18 पूर्ण कर स्थापित कर दिये गये हैं। आंगनबाड़ी 137 लक्ष्य है, 130 स्वीकृत है। वहां पर 42 आंगनबाड़ी केन्द्र दे दिए गए हैं। इसमें और भी बहुत सी योजनाएं हैं जिनको मैं बोलना चाहता था, पर समय बहुत हो रहा है। नक्सलाईट क्षेत्रों में सोलर लाईट की भी व्यवस्था हो रही है। स्ट्रीट वेंडर मूंगफली ठेले वाले, अंडे ठेले वाले, चाय ठेले वाले जो गरीब होते हैं, , इनको भी सरकार प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत् 31956 आवेदनों पर 55 करोड़ 61 लाख रूपए का ऋण ठेले व्यापारियों को दिया गया है। पी.एम. विश्वकर्मा योजना के तहत् 18 व्यावसायियों को 49 हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित

किया जा रहा है। सभापति महोदय, मैं इनको अंतर बता रहा हूं कि इनकी सरकार में और हमारी सरकार में क्या अंतर है और इनको क्यों विरोध नहीं करना चाहिए। जब आप लोग वर्ष 2018 में सरकार में नहीं आये थे तो आपने गंगाजल उठाकर कसम खाई थी कि हम शराबबंदी करेंगे। आपने कसम खाई थी और उसके कारण आपकी सरकार बनी।

श्री रामकुमार यादव :- हम नहीं कहे रहे हन भाई। बिल्कुल नहीं कहे रहे हन। तुमन 15 लाख रूपये देबो कहे रहे हो, तेला बताओ।

श्री धर्मजीत सिंह :- तोला तो ओ टाइम टिकट ओ तक नहीं मिले रीहिस हे। ते बइठ न यार। आपने टी.एस. बाबा साहब के नेतृत्व में घोषणा पत्र बनाया और घोषणा पत्र बनाने के बाद जब आपकी सरकार आ गई तो आपने उनको दूध की मक्खी के समान निकालकर फेंक दिया। उप मुख्यमंत्री टी.एस. बाबा जी का इस सदन में जितना अपमान मैंने देखा है, उतना अपमान शायद मैं आगे भी नहीं देख पाऊंगा और आज भी नहीं देख पा रहा हूं। आप लोगों ने उनका इतना अपमान किया। आप सब चाटुकारिता करते हुए हां में हां मिलाते थे और सत्ता के गलियारे में घूमते रहते थे। आप लोग हवाई जहाज में दिल्ली जाते थे और दिल्ली में बैठकर लॉबिंग करते थे। आप क्यों बात करेंगे ? आप लोगों ने टी.एस. बाबा का इतना अपमान किया। यहां पर एक महापुरूष बैठते थे। उन्होंने उनको हत्यारा तक बोल दिया था। क्या आप अपनी पार्टी में इतनी मर्यादा खोकर रहेंगे ? आप गंगाजल की कसम खाते हैं और हम मोदी जी की गारंटी में राम मंदिर बनवाते हैं। हम मोदी जी की गारंटी में महाकुंभ में बहुत बड़ा मेला लगाते हैं, जहां पर 66 करोड़ लोग आते हैं। (मेजों की थपथपाहट) आपके राज में क्या होता था ? महादेव सट्टा ऐप। वह महादेव सट्टा ऐप वाला अपने कार्यक्रम में दुबई में हीरोइनों को नचवाया। बड़ी-बड़ी हीरोइनें थीं। कौन-कौन थीं ?

श्री विक्रम मण्डावी :- भैया, आपकी सरकार ने कहा था कि हम उस दुबई वाले को एक सप्ताह में लाएंगे, लेकिन उसको अभी तक नहीं लाया गया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- लाएंगे। दुबई कोई कोण्डागांव थोड़ी न है कि जाकर ले आये। (हंसी) दुबई से उसको लाने में में टाइम लगेगा। यदि दुबई कोण्डागांव होता तो भेजकर अभी एक घण्टे में उसको मंगवा देते, लेकिन वह दुबई है। वहां पर शेख लोगों के यहां जाओगे तो यदि उनकी इच्छा नहीं होगी तो आप भी वहां से नहीं आ पाओगे। (हंसी) महादेव सट्टा ऐप। आपकी सरकार में पब्लिक सर्विस कमीशन में कहा के महापुरूष को बैठाया गया था। जो एकदम अयोग्य व्यक्ति है, उसको कलेक्टर और जो बहुत योग्यता रखा है, वह बेचारा अपने घर में रो-गा रहा है और मूंगफली ठेला खोलने की सोच रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्य हो कि उन्होंने कड़ाई से पेश आकर उसकी जांच कराई। वह जेल की सलाखों की शोभा बढ़ा रहे हैं। वह जेल के अंदर हैं। उसकी जांच होगी और यदि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई होगी तो उसमें इसी प्रकार से कठोर दण्ड दिया जायेगा। आपने राजीव मितान क्लब

बनाया और अपने लोगों को माल-पानी दिया कि खाओ-पियो मौज करो। हमने बस्तर ओलम्पिक का आयोजन कराया है। उसमें बस्तर के 1 लाख से ज्यादा लोग खेले हैं और वह ओलम्पिक सरकार के नियंत्रण में हुआ है। हमने रेडी टू ईट को महिलाओं को देने का काम किया। कांग्रेस पार्टी में तो अभी इतना झगड़ा चल रहा है। एक विधायक अभी यहां पर नहीं हैं। उनको उनका एक छोटा सा जिलाध्यक्ष निकाल दिया तो मैंने उस विधायक का बयान पढ़ा कि चपरासी कलेक्टर को निकाल रहा है। यह आपकी ही पार्टी के विधायक का बयान है। यह मेरा बयान नहीं है। चपरासी कलेक्टर को निकाल रहा है, यह बयान आपके विधायक जी ने दिया है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि विधायक जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है और उन्होंने इस बात को कहा भी है। पेपर या कहीं भी उनकी बात आ रही है, लेकिन उन्होंने यह बात नहीं कही है और न ही कहीं पर यह बात प्रमाणित है।

श्री धर्मजीत सिंह :- उन्होंने प्रेस में बयान दिया है।

श्री उमेश पटेल :- इनकी पूरी बात प्रमाणित नहीं रहती है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- विधायक जी ने ऐसा बयान कहीं नहीं दिया है और उन्होंने यह बात साफ कर दी है।

श्री रामकुमार यादव :- उन्होंने कहीं बयान नहीं दिया है। ऐखरे खातिर मैं कहथो कि ऐमन जो कहथे, ओहा लबारी रहिथे। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, मैं आपको दूसरी बात बता देता हूं। रतनपुर में आपकी ही पार्टी के लोगों ने अपने विधायक का पुतला जला दिया। आप बोल दीजिए कि वह भी नहीं जलाया गया है तो मुझे खुशी है और आपको मुबारक हो। मैं तो आपका शुभ चिंतक होने के नाते बोल रहा हूं कि आप लोग अपने विधायक की इतनी तो मर्यादा रखिये कि एक छोटे से चुनाव के चक्कर में विधायक का अपमान कर रहे हैं और आप लड़ाई लड़ने के लिए महाबलि सेना के सामने खड़े होना चाहते हैं। आप कहां से खड़े हो जाएंगे ? इसीलिए मैं अपनी बात समाप्त करते हुए बोलता हूं -

तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं,
कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं।

मैं आपको बता रहा हूं कि जमीन नहीं है, जमीन नहीं है, लेकिन आप यकीन नहीं कर रहे हैं, इसलिए पूरे देश में।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- धर्मजीत भैया, वास्तव में यह बात आपके दल के लिए लागू हो रही है।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी अभी पूरे देश में आई.सी.यू. में जा रही है। आपको बिहार में भी आर.जे.डी. जैसा क्षेत्रीय दल कम टिकट देगा। अरविन्द केजरीवाल आपके साथ चुनाव लड़ना पसंद नहीं किए। पंजाब में भी नहीं लड़ेंगे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- यह गलत बात है। अरविन्द केजरीवाल के प्रस्ताव को हमारे दल ने ठुकराया है। आप सरासर गलत बोल रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- हमको मत बताईये।

'हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है,
हम जहां से जायेंगे, वह रास्ता हो जायेगा।
परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता,
किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, इसलिए मैं नेक सलाह देता हूं कि विष्णुदेव साय जी, आपके, हमारे सबके इस धरती के माटी पुत्र हैं। साफ-सुथरे व्यक्ति हैं। गरीब आदिवासी परिवार का बेटा है, जिसने गरीबी को देखा है। वह कुछ करना चाहते हैं तो उसमें आपका रचनात्मक सहयोग चाहिए। आप विरोध के लिए विरोध मत करिये। कोई कमी हो, कोई भ्रष्टाचार दिखे, कोई बात हो तो आप जरूर बोलिये। यह जीरो टालरेंस की सरकार है, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक भले आदमी को काम नहीं करने देना, बात-बात में यह सरकार कौन चला रहा है, कहकर प्रश्न पूछा जाता है। पिछली सरकार को कौन चलाता था ? अब बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। पहले क्या होता था ? कोरबा में कोयले की रायल्टी कौन काटता था ? शराब की तस्करी कौन करता था ? शराब का 2200 करोड़ रूपये का घपला किसने किया ? बड़े-बड़े लोग जेल के अंदर हैं और उसके बाद आप ऊंगली दिखाते हैं। तो ऊंगली दिखाने के पहले याद रखिये कि जब आपकी एक ऊंगली हमारे ऊपर उठती है तो तीन ऊंगलियां आपकी तरफ भी ईशारा करती है कि अपने गिरेबान में झांककर देखों। (मेजों की थपथपाहट) जब आप देखोगे तो आप इस प्रकार की बात नहीं करोगे। अगर आप इस प्रकार की बात नहीं करोगे तो इस प्रदेश की जनता के सही विपक्ष का प्रतिनिधित्व करोगे। आप सरकार का विरोध डटकर करिये, आपके विरोध में हमको भी आनंद आयेगा। आपके विरोध से ही सरकार जागृत रहेगी। लेकिन विरोध के लिए विरोध करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री मत करिये। क्योंकि प्रजातन्त्र के हम दोनों चक्के हैं। बिना आपके हम अधूरे हैं और बिना हमारे आप अधूरे हैं। इसलिए मिल-जलुकर इस छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पर आगे ले जायेंगे, यही जनता के जनतंत्र में दिए गए निर्णय का सम्मान होगा। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। धरम लाल कौशिक जी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द। (मेजों की थपथपाहट)

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय सभापति महोदय, मैं कोशिश करता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय अभिभाषण तक सीमित तक रहूं। लेकिन चूंकि आपने पूर्व वक्ताओं को सीमाओं को लांघते हुए समय दिया है तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे भी मौका देंगे।

सभापति महोदय, सर्वप्रथम हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा और यह propaganda फैलाने की कोशिश की गई कि राहुल गांधी जी ने आलू से सोना बनाने का कथन किया है। मैं सत्यता बताता हूं। सत्यता यह है कि भारतीय जनता पार्टी के आई.टी. सेल ने इस propaganda को करवाया है। राहुल गांधी जी यह कह रहे थे कि नरेन्द्र मोदी जी ऐसा कहते हैं कि एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। उसमें पहली वाली लाईन को काटकर आई.टी. सेल ने ऐसा propaganda किया कि आज भी विधान सभा में खड़े होकर इस propaganda को कर रहे हैं। यह घोर और बहुत ही अपमानित करने वाली बात है। इस तरह की असत्य बात को, यदि आप चाहेंगे तो मैं पूरा वीडियो और फुटेज आपकी टेबल पर रखना चाहूंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिये मैं कल इसको प्रस्तुत करूंगा। सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि इसको एक-एक विधायक को दिखाया जाये ताकि इस बात की सत्यता सामने आ जाये।

माननीय सभापति महोदय, राजीव गांधी किसान न्याय योजना में बात कही गई कि जब हम सरकार में थे तो हमने बोनस की राशि को 4 किश्तों में दिया। लेकिन मजबूर किसने किया ? आपकी केन्द्र सरकार ने हमें मजबूर किया। केन्द्र सरकार ने उस समय की तात्कालिक सरकार को यह कहा कि अगर आप बोनस की राशि देंगे तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। यह केन्द्र सरकार ने कहा और हमें मजबूर होना पड़ा और एक नई योजना "राजीव गांधी न्याय योजना" बनानी पड़ी, जिसके तहत हम प्रति एकड़ के हिसाब से बोनस की राशि दे रहे थे। आपको यह पता है कि जब हमारी सरकार चल रही थी, आपके पास 10 एकड़ है और आपके पास 10 एकड़ का पंजीयन है तो बोनस की राशि 10 एकड़ पर मिलती थी। आप कितना क्विंटल बेचा है उसके हिसाब से बोनस की राशि वितरित नहीं होती थी बल्कि उस समय जमीन के पंजीयन के हिसाब से बोनस की राशि वितरित होती थी। हमें यह केन्द्र की सरकार ने मजबूर किया तभी हम चार किश्तों में बोनस की राशि देने के लिए मजबूर हुए थे। यह आरोप मत लगाईये कि आप चार किश्ती में बोनस राशि देते थे। मेरा तो यह खुला आरोप है कि जब पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय इन्होंने दो वर्ष का बोनस राशि नहीं दिया था। यह आपने [xx] किया था। आपने लोगों ने किसानों के साथ [xx] किया था और वह [xx] का भुगतान आप अभी कर रहे हैं। इस बार आप फिर से नया [xx] धो रहे हैं और नया [xx] यह है कि किसानों का राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्ती का पैसा आप से नहीं दे रहे हैं। यह आपकी नीयत को दिखाता है, किसानों के प्रति आपकी निष्ठा को दिखाता है कि किसान के बारे में आप क्या सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी न आज किसानों की थी, न पहले किसानों की थी, न आज है न आगे किसानों की रहेगी। यह पार्टी सिर्फ धर्म की राजनीति करके वोटबैंक अपने पास रखने की कोशिश करती है। आप धर्म की

क्या बात कर रहे हैं। अगर हम लोग कुंभ मेले में नहीं गये थे तो हमारे साथी लोग गये थे। कुछ लोग अपने पारिवारिक कारण से नहीं गये थे, कुछ लोग अपने स्वयं काम के कारण नहीं गये थे। उसके कारण से आप वह बात कैसे कहेंगे? आपकी तीसरी बार केन्द्र में सरकार बनी है। हज के लिए जो सब्सिडी मिलती है, उसको आप क्यों बंद नहीं करते हैं? हमारी भगवान श्रीराम जी की आस्था के बारे में आप प्रश्न पूछेंगे, आप हमारी आस्था को प्रश्न चिन्ह लगायेंगे। नहीं। यह प्रदेश भगवान श्रीराम का ननिहाल है और यहां हमने कौशिल्या माता का मंदिर बनवाया। जब हमने कौशिल्या माता का मंदिर बनवाया तो हमने आपके सारे साथी को बुलया था कि आईये मंदिर का दर्शन करिये, लेकिन वहां मंदिन देखने के लिए एक भी साथी नहीं गये। आप उसको क्या बोलेंगे? हमने तो आपके आस्था पर कभी प्रश्न नहीं उठाया। क्योंकि आदमी के पास नहीं आने की कई प्रकार के पारिवारिक परिस्थितियां हो सकती हैं। माननीय सभापति महोदय, ये आबकारी के बारे में बात कर रह हैं, महादेव एप्प के बारे में बात कर रहे हैं कि हमने इतने लोगों को जेल में डाला। मैं चुनौती देता हूं कि वह दो तोते हैं, अगर मुझे 5 दिन भी मिला तो यहां पर एक आदमी नहीं बचेगा, सब के सब अंदर रहेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

श्री धर्मजीत सिंह :- आप किस चीज में अंदर करेंगे?

श्री उमेश पटेल :- कुछ नहीं। जब तोता रहेगा तो अपने आप बन जाता है। बस, दो तोते की आवश्यकता है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- कैसे अंदर हो जायेंगे? जो अंदर होने वाले हैं, वे तो अंदर हो ही रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- बस दो तोते की आवश्यकता है। जब ऐसे करके पर्चा उठायेंगे (हाथ से इशारा करते हुए) तो वह घर के अंदर हो जायेगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मतलब आप जादूगर हैं।

श्री उमेश पटेल :- हाँ, बिल्कुल जादूगर हूं।

श्री रामकुमार यादव :- पांच साल के बाद पता चलही कि तोता कहां बईठही। जइसनहे बोये रहेओ तइसनहे पाइहा।

श्री केदार कश्यप :- उमेश जी, आप जादू जानते हैं तो आपके बाबा जी को सिखाईये कि एक तरफ से आलू डालकर दूसरे तरफ से सोना कैसे निकालेंगे? वह जादू कैसे करेंगे उसको बता दीजिएगा। आप लोग आलू खरीद-खरीद कर रखे हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, आप मुझे अनुमति दीजिये, फिर मैं यहां पूरा फुटेज डालूंगा। खासकर जो मंत्री लोग हैं, इनको दिखाईये कि यह लोग विधान सभा के अंदर गलत बयानी दे रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति को जबरदस्ती उसके बाद डाल रहे हैं। आपके आई.टी. सेल ने किया। आपको इस तरह की गलत बयानी शोभा नहीं देता है। आई.टी. सेल ने जो किया वह किया।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, इनके गृह मंत्री बोले थे कि बी.ए. कर लो, फिर बारहवीं कर लेना । आपके गृह मंत्री ने उत्तरप्रदेश के संदर्भ में बोला था ।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, अभी उमेश जी बोल रहे हैं ।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, विधान सभा के अंदर में गलतबयानी कर रहे हैं, जिस व्यक्ति ने इस बात को कहा नहीं है, जबरदस्ती उसके बारे में विधान सभा के अंदर फैलाया जा रहा है । सभापति महोदय, मैं तो सभी सदस्यों को चुनौती देता हूँ कि इस बात पर आप मेरे साथ ओपन डिबेट करिये । सभापति महोदय, संसदीय मंत्री जी शायद बाद में आये हैं, आप पूरा अध्ययन कर लीजिए, यह सही नहीं है ।

समय
4.21 बजे

(सभापति महोदय (धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुये)

एक माननीय सदस्य :- उमेश भाई, वह तो नाम भी नहीं ले रहे हैं, आपको कैसे मालूम कि आलू निकालकर सोना बनायेगा ?

श्री उमेश पटेल :- जैसा कि आप तोता समझ गये थे ना, वैसे मैं भी समझ गया था । माननीय सभापति महोदय, इस सरकार के बारे में बहुत सारी बातें कहा जा रहा था कि नगर निगम में नहीं आये, चुनाव में आप नहीं आये, आप चुनाव के पहले क्या बोल रहे थे कि ओबीसी को 50 प्रतिशत आरक्षण देंगे ? आपने ओबीसी वर्ग के लिये सर्वे भी कराया और ओबीसी को कितना आरक्षण है ? शून्य । सभापति महोदय, जिला पंचायतों में शून्य आरक्षण है । मैं गलत तो नहीं हूँ ना ? शून्य आरक्षण, शून्य आरक्षण, यह है ओबीसी के प्रति आपका नजरिया । आप कहां 50 परशेंट से शून्य में आ गये ? सभापति महोदय, मैंने जिला पंचायतों में आरक्षण को देखा या तो एस.सी. है या एस.टी. है या अनारक्षित है । महिला-पुरूष का अलग है या तो एस.सी. या तो एस.टी. या तो अनारक्षित, ओबीसी तो था ही नहीं, गिनती मात्र नहीं था ? सभापति महोदय, रायगढ़ ब्लॉक के 82 पंचायत में तीन महिला और तीन पुरूष सिर्फ 6 ओबीसी हैं, यह कितना प्रतिशत हो गया, 8 प्रतिशत और कहां 50 प्रतिशत की बात कर रहे हैं ? भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी के प्रति यह नजरिया है । सभापति महोदय, आदिवासी की बात कर रहे हैं, अभी हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि आदिवासी मुख्यमंत्री है, इसलिये आपको सहन नहीं हो रहा है । हम तो चाहते हैं कि वह अपना काम करें, मुख्यमंत्री के रूप में अपना तेवर दिखायें । यहां तो यही समझ नहीं आता है कि मुख्यमंत्री का काम कौन कर रहा है ? सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी की राईस मिलरों के साथ मीटिंग होती है, हमें यह पता चलता है कि पटाक्षेप हो गया । वह फिर नहीं होता है और पुन: हड़ताल चले जाते हैं, आपको बाहर से आदेश कौन दे रहा है, इस सरकार को कौन चला रहा है ?

सभापति महोदय, यह हम नहीं कहते हैं, इसे लोग कहते हैं कि काम कहां होगा, किधर होगा, हमको बताओ तो, समझ में नहीं आता ? आदिवासी मुख्यमंत्री के लिये...।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी कामों पर अभी पंचायत चुनावों और आपके नगरीय निकाय चुनाव में जनता की मुहर लग चुकी है, हमें आपके मुहर की जरूरत नहीं है । (मेजों की थपथपाहट)

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मैं आपको मुहर लगा भी नहीं रहा हूँ और कभी लगाऊँगा भी नहीं ? (हंसी) मेरा मुहर हाथ पर ही लगेगा, लेकिन मैं आपको यह बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री की बात विपक्ष कर रहा है, उसे विपक्ष नहीं कर रहा है, समूचा छत्तीसगढ़ जानना चाहता है कि मुख्यमंत्री कौन है ? हम लोग जनभावनाओं को यहां प्रस्तुत कर रहे हैं ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, मुख्यमंत्री एक ही हैं विष्णुदेव साय जी, यह पिछले पांच साल की कहानी याद करके सदन को गुमराह कर रहे हैं । पिछले पांच साल तक छत्तीसगढ़ की जनता पूछती रही है कि ढ़ाई-ढ़ाई साल का कौन था ?

श्री विक्रम मण्डावी :- सभापति महोदय, जब व्यक्ति एक है तो इंजिन कैसे तीन-तीन हो गया ? इंजिन ट्रिपल कैसे हो गया ?

श्री सुशांत शुक्ला :- [xx] ?

श्री उमेश पटेल :- आप कुछ बोल रहे हैं ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, एक समय था जब आप सब लोग गये थे और वहां पर छत्तीसगढ डोल रहा है, और बाबा-बाबा बोल रहा है, कौन बाबा है, आप थोड़ा अपने भाषण में बताईयेगा ? यह पूरा सदन जानना चाह रहा है।

श्री उमेश पटेल :- बिल्कुल बतायेंगे । पूछिये ना ? आप पूछिये, हम बतायेंगे।

श्री केदार कश्यप :- हम आपसे पूछ ही रहे हैं, वह बाबा कौन है ?

श्री उमेश पटेल :- तोते वाले बाबा ।

श्री सुशांत शुक्ला :- योगी बाबा तो यूपी में है ।

श्री रामकुमार यादव :- बाबा, बाबा मत कहाव भई, तुमन ला डेढ़ साल होगे हे, कुछू नई मिलिस, धरादेव छत्तीसगढ़ ला [xx] ? (हंसी)

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, यह सरकार जो पुरानी योजना है, अभी प्रथम वक्ता धरमलाल कौशिक जी का भाषण चल रहा था । उन्होंने कहा कि इस सरकार ने एक बेहतर स्टेप लिया है । यह सरकार 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं वापस से करा रही है । मैंने तो पहली बार देखा कि किसी पार्टी की सरकार अपने ही निर्णयों को वापस ले रही है । यह जो निर्णय 2008-2009 के आसपास हुआ था। मेरे ख्याल से तब शायद शिक्षा मंत्री अजय जी थे । ये तब हुआ था और उसको

वापस लेकर बोल रहे हैं कि वाह, क्या निर्णय है । सभापति महोदय, आप नाम बदल रहे हैं और इसे 'नई योजना' बोल रहे हैं । हमने मजदूर न्याय योजना शुरू की, उसको आपने दीन दयाल उपाध्याय भूमिहीन किसान मजदूर योजना आरंभ की है । वहां 7 हजार और यहां 10 हजार दे रहे हैं । इंन्फ्लेशन को जोड़ दोगे तो उसमें 3 हजार बढ़ ही जाएगा ।

माननीय सभापति महोदय, महतारी वंदन योजना के बारे में बहुत बात होती है, बिल्कुल ठीक है । आपने अपनी घोषणा-पत्र में इस बात को रखा और उसके बाद उसको किया । ठीक है, हमारे माननीय सदस्य ने इस बात को रखा, पर आप उन बुजुर्ग महिलाओं के साथ क्यों दुर्व्यवहार कर रहे हैं ? आपने उनका पेंशन बंद कर दिया। महतारी वंदन मिलेगा तो पेंशन नहीं मिलेगा । आपने यह नई चीज कहां से शुरू कर दी । यह तो आपने घोषणा-पत्र में कहीं नहीं लिखा था । आपने कहा था कि प्रत्येक विवाहित महिला को महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जाएगा । आपने बुजुर्ग महिला के पेंशन की राशि को बंद कर दी । उसके बाद किया तो किया । एक बार पोर्टल बंद कर दिया, उसके बाद वह ओपन ही नहीं हो रहा है । जो नई शादी होकर महिलाएं आई हैं, वह बार-बार घूम रही हैं, आफिस के चक्कर लगा रही हैं कि कब पोर्टल खुले तो हम लोग भी उसमें अपना आवेदन भरें । कईसे बबा, तोर इहां भरावथे ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सब जगह भर रहे हैं । आप भरेंगे तो मिल जाएगा। आप तो भर ही नहीं रहे हैं ।

श्री उमेश पटेल :- एकाध जगह उदाहरण बता दीजिए । सभापति महोदय, जहां तक स्व सहायता समूह और रेडी टू ईट की बात आती है । बहुत सारे सदस्य यह कहते हैं कि स्व सहायता समूह में यह हुआ, रेडी टू ईट में यह हुआ । आपकी सरकार बने डेढ़ साल हो गए हैं, आपने उसको कहां बदला है ? आप सिर्फ आरोप लगाते हैं । आरोप के अलावा कुछ नहीं है, अब आप सत्ता पक्ष में आ गए हैं । आरोप मत लगाईए, आरोप लगाने का काम हमारा है, आप कार्रवाई करिए । अगर वह योजना गलत थी तो उसको बदलिए । आप कुछ कर रहे हैं, वह तो दिखे । काम वही करना है, बस आरोप लगाना है ।

माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के क्रमांक 18वें नम्बर पर मैं बड़ा चौक गया । उसमें लिखा है कि छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है, जहां स्वामी विवेकानंद ने अपनी किशोरावस्था बिताई है । स्वामी जी के विचार हम सबके लिए प्रेरक हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं । स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि मुझे 100 उत्साही युवक दे दो, मैं पूरे विश्व को बदल दूंगा । मेरी सरकार ने युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दी है । सभापति जी, स्वामी विवेकानंद जी यहां रहे, हम इसको डिनॉई नहीं कर रहे हैं । लेकिन यह इस सरकार की उपलब्धि है ? आप क्या बताना चाह रहे हैं ।

श्री केदार कश्यप :- सभापति जी, सरकार की यह उपलब्धि है कि आप युवाओं को, उनके सपनों को आपकी सरकार में जिस तरीके से बेचने का काम किया । आप तो उच्च शिक्षा मंत्री थे, आप ज्यादा

अच्छी तरीके से समझते हैं । आपकी सरकार ने उनके सपनों को बेचने का काम किया और जो लोग पात्र नहीं थे, उनको आप लोगों ने जिस तरीके से पुरस्कृत किया था । यह पूरे प्रदेश के युवाओं ने देखा है । आज सीजीपीएससी में जिस पारदर्शिता के साथ में भर्तियां हो रही हैं, उसके लिए पूरा युवा वर्ग आज मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं । (मेजों की थपथपाहट)

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मैं तो कहीं और बोल रहा था, इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का उल्लेख किया है । स्वामी विवेकानंद जी यहां आये, यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन यह इस सरकार की उपलब्धि नहीं हो सकती। दूसरी चीज, आप युवाओं की बात करेंगे । यहां पर 33 हजार की घोषणा करके आजतक वहां शांति से बैठे हुए हैं । जब प्रतियोगी परीक्षा के लोग जाते हैं, तो इनके मंत्री उनको क्या-क्या उत्तर देते हैं। क्या-क्या उत्तर देते हैं? ज्यादातर लोग [XX][5] हो तुम लोग, लायक ही नहीं हो। इस तरह के उत्तर देंगे? युवाओं को आप किस रास्ते पर ढकेल रहे हैं? देख लीजिए, इनकी ये स्थिति है। नौकरी नहीं है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- सभापति महोदय, ये मंत्रियों को बोल करके [XX] शब्द कोड कर रहे हैं, इसे विलोपित करने की हम मांग करते हैं।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, नहीं, [XX] कोई ये तो है नहीं।

सभापति महोदय :- उसे देख लेंगे, देखकर कर लेंगे।

श्री उमेश पटेल :-चलिए, मैं बात को वापस लेता हूं। बहुत सारे लोग लायक नहीं हैं।

सभापति महोदय :- नहीं, आप वापस मत लीजिए। [XX] शब्द को देख लेंगे, असंसदीय होगा तो विलोपित कर देंगे।

श्री उमेश पटेल :- ठीक है, मैं उसे वापस ले लेता हूं।

सभापति महोदय :- अब तो विलोपित हो ही गया, जरुरत क्या है।

श्री उमेश पटेल :- आपकी आज्ञा होगी, तो मैं उसको बदल देता हूं।

सभापति महोदय :- बदल दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- कि बहुत सारे लोग लायक नहीं हैं, ऐसा कहा गया। अब ठीक है? वही तो है, मैं कहां मना कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, ये महिलाओं की बात करते हैं। हमारे आदरणीया ने फ्लोरामैक्स के बारे में प्रश्न लगाया था। फ्लोरामैक्स में महिलाओं की गाढ़ी कमाई को लूटा गया। किसी प्रदेश में एक सरकार अभिभावक की तरह होती है और जो जनता है, वह एक बच्चे की तरह होती है। आपके मंत्री क्या जवाब देते हैं-यहॉ से उठो, नहीं तो जेल में डाल देंगे। यहॉ से उठो। महिलाओं के प्रति ये जवाब है। आप बोलेंगे कि हम लोग युवाओं और महिलाओं के लिए बजट बना रहे हैं।

[XX][5] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया

उद्योग मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- माननीय उमेश भाई, ये फ्लोरामैक्स वाला किसकी सरकार में हुआ? आपको मालूम है या नहीं है? इसे कौन चालू कराया था? (शेम-शेम की आवाज) आपकी सरकार में हुआ था और हमारी सरकार ने इसे बंद कराया है और जो आरोपी हैं, उन्हें जेल भेजा है।

श्री उमेश पटेल :- सरकार किसकी थी, इसके ऊपर मैं जा ही नहीं रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि सरकार अभिभावक की तरह होती है, घर के एक मुखिया की तरह होती है और जो छत्तीसगढ़ की जनता है, वह एक बच्चे के समान है। उसे आप किस तरह से हंकाल रहे हो? हटो यहां से, नहीं तो हम तुमको जेल में डाल देंगे-हटो यहां से नहीं तो हम तुमको जेल में डाल देंगे। एक मंत्री बोल रहे हैं कि तुम लोगों के बीच में से कोई लायक ही नहीं है, एक विधायक गला पकड़ ले रहे हैं, एक विधायक अपने पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हैं कि मेरे बेटे को जबरदस्ती फंसा दिया गया। इस सरकार में यह हो रहा है। इस सरकार में और क्या हो रहा है?आप कानून-व्यवस्था की बात करते हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ की जनता सरकार को पालक मानती है, तो कवर्धा को भी याद करना चाहिए, बिरनपुर को भी याद करना चाहिए, नारायणपुर को भी याद करना चाहिए, जशपुर के कुनकुरी को भी याद करना चाहिए । (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- और बलौदा बाजार को भी याद करना चाहिए। (व्यवधान) आप क्या बात कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- और लोहारीडीह को भी याद करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- लोहारीडीह को भी याद करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आप राजधानी की बात कीजिए कि राजधानी के पास कलेक्ट्रेट को जला दिया गया। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिए। रामकुमार जी, आप बैठिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, छरछेद की जो नृशंस हत्या हुई, उसे भी याद करना चाहिए।

सभापति महोदय :- आप बैठिए ना। वह बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वह बोल लेंगे ना। वे जो बोलेंगे, अब वह बोलेंगे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, 24वें नंबर में महामहिम जी ने इन्होंने कहवाया कि राष्ट्रीय राजमार्ग में तेजी से काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ रोड एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड से काम हो रहा है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। मैं उदाहरण के पहले एक बात कहता हूं कि सरकार की नीयत कितनी खराब है कि जिस चीज का टेंडर हो चुका है, जिस चीज का काम पूरा हो चुका है, उसे डेढ़ साल से रोककर रखे हैं सिर्फ इसलिए कि समय होने दो, नहीं तो ये कॉग्रेस पार्टी के लोग स्वीकृत कराए हैं, करके उसका श्रेय ले जायेंगे। टेंडर हुए डेढ़ साल हो गए। एक ओव्हरब्रिज पास हुआ था,

जिसमें भूमि अधिग्रहण का काम भी हो गया है, टेंडर भी हो गया है लेकिन डेढ़ साल से वह काम शुरु नहीं हो रहा है, फाईल में साईन नहीं हो रहा है। क्यों? वहॉ के लोगों की क्या गलती है? एक रेल्वे ट्रैक के कारण खरसिया आज दो हिस्से में है। हम लोग ओव्हर ब्रिज बनाकर उस दो हिस्से को बराबर करना चाहते थे। लेकिन डेढ़ साल से उस ओव्हर ब्रिज को बनने नहीं दिया गया है। आप डेव्हलपमेंट करें, पूंजीगत व्यय भी करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपका जो यह व्यवहार है, आप उसको बदलिये। यह आपका लोगों को देखने का जो नजरिया है और आप पार्टी का चश्मा पहनकर हर चीजों को देखना बंद करें। अब आप सरकार में बैठ गये हैं, आपका नजरिया सबके लिये एक बराबर होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हमने आत्मानंद स्कूल शुरू किये। यह सदन है और आज हम विपक्ष में बैठे हैं, यह सत्य है। इसको कोई नकार नहीं सकता। हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी, हम इसे भी नहीं नकार रहे हैं, तभी हम यहां बैठे भीं हैं। लेकिन हमारी कुछ योजनाएं बहुत अच्छी थी। उसमें एक स्वामी आत्मानंद स्कूल की योजना थी। आप लोग भी दबी जुबान में इस बात से सहमत है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल एक योजना थी, जो बहुत अच्छी योजना थी। आपने क्या किया ? आपने उसके नाम के बोर्ड को हटा दिया और उसका नाम पी.एम. श्री स्कूल कर दिया। हमको कोई दिक्कत नहीं है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- सभापति महोदय, कहां आत्मानंद स्कूल बंद हुए हैं ? आप सुबह से वही बोल रहे हैं। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। हमने फोन भी लगाया कि क्या किसी आत्मानंद स्कूल का नाम बदल दिया गया है ? वह बोले सभी स्कूलों में स्वामी आत्मानंद के नाम का ही बोर्ड लगा हुआ है। स्वामी आत्मानंद स्कूल अलग चल रहा है और पी.एम. श्री स्कूल अलग चालू कर रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, चल तो रहा है लेकिन हमन कहत रेहेन कि ओ मा चाक, मिट्टी नहीं हे। लइका मन बर गुरूजी नहीं हे।

सभापति महोदय :- राजेश जी, आप अपनी सीट में जाकर बोलिये। वह मंत्री जी की सीट है।

श्री राजेश अग्रवाल (अम्बिकापुर) :- सभापति महोदय, पी.एम. श्री स्कूल के लिये जहां-जहां से मांग आयी थी, उसे किसी आत्मानंद स्कूल को दे दिये होंगे। लेकिन हमारे सरगुजा में एक भी आत्मानंद स्कूल बंद नहीं हुए हैं। वहां पी.एम. श्री स्कूल अलग से चयनित हुए हैं।

श्री उमेश पटेल :- अग्रवाल जी, सरगुजा में यह नहीं हुआ है, उसके लिये आपको धन्यवाद। लेकिन कई जगहों पर हुआ है। आत्मानंद स्कूलों को दे दिया गया है।

श्री सुशांत शुक्ला :- नहीं हुआ है।

श्री उमेश पटेल :- हुआ है। मैं उदाहरण प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- पी.एम. श्री स्कूल के लिये डिमांड आयी होगी।

श्री उमेश पटेल :- आप मेरे साथ चलिये, मैं आपको दिखा देता हूं।

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिये। यह कोई विवाद का मुद्दा नहीं है।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, इनका जवाब तो देना होगा।

सभापति महोदय :- हो गया। आपने जवाब दे दिया।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, जो नटवर स्कूल था, उसको बदलकर स्वामी आत्मानंद स्कूल किया गया। अब उसको बदलकर पी.एम. श्री स्कूल कर दिया गया है।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, जैसे आपने बगैर किसी सेटअप और बगैर किसी बजट के चलते हुए स्कूलों को रंग-रोगन करके नयी दुकान खोली थी। आपने छत्तीसगढ़ के शिक्षा के तंत्र को खराब किया था। (व्यवधान) यह कहां की बात हुई।

श्री उमेश पटेल :- बगैर कहे आप मान रहे हैं। । यदि आप मान रहे हैं तो मान रहे हैं बोलिये ना। आप तरह-तरह की बातें मत करिये।

सभापति महोदय :- सुशांत जी, आप बैठिये।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- आप नये स्कूल, कॉलेज खोलिये। केवल नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला।

सभापति महोदय :- आप सब भी बैठिये। वे बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। उनके बीच में आप सब टोका-टाकी मत करिये। एक-आत कोई सदस्य बोले तो समझ में आता है।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- सभापति महोदय, आत्मानंद स्कूल में कितने स्कूलों में नया सेटअप बनाया गया ? कितनी नई भर्तियां हुईं ? बजट में कितना पैसा दिया गया ? मैं एक उदाहरण दे देता हूं जैसे बी.पी. पुजारी स्कूल है, उसमें कितना पैसा, कौन-कौन से मद का सिर्फ पेंटिंग और डेंटिंग में खर्च हुआ, इसको आप थोड़ा बताईये? कितने आत्मानंद स्कूल का यूडाइस कोड लिया गया ? यह आप बताईये। हम उसकी प्रशंसा करते हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, स्वामी आत्मानंद स्कूल का रिकॉर्ड यह रहा कि जब 10वीं का रिजल्ट आया तो जो टॉप 1 से लेकर 10 तक रैंक थे, उसमें स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भी नाम था। यह रिजल्ट अपने आप में दर्शाता है कि यह योजना सफल योजना थी।

सभापति महोदय :- चलिये, अब आगे बढ़ जाईये।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, इसलिये मेरा यह कहना है कि जो योजना अच्छी है, उसको चलने देना चाहिए। इसमें और बहुत सारी बातें आयी। माननीय धरमलाल कौशिक जी छत्तीसगढ़ी संस्कृति और नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी के बारे में कह रहे थे कि इन सब को हटा देना चाहिए था। आप उसका विकल्प तो लाईये। हमने गौठान बनाने का काम किया, वह काम सही गलत जो भी हुआ, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन आप कम से कम उसके विकल्प में तो दूसरी योजना लाईये। आप कुछ करें।

लेकिन आप नहीं करेंगे। आपको तो सिर्फ आरोप लगाना है। यह गलत हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। आप कहां पर एक भी भ्रष्टाचार निकाल पाये ? मेरे विधान सभा क्षेत्र में 36 गौठानों की जांच हुई और एक जगह पर भी कुछ नहीं पाया गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- उमेश जी, सुनिये। आपने नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी में गोबर खरीदा। रीपा से गोबर का पेंट बनाया।

श्री उमेश पटेल :- आप गौठानों की बात कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं, आपसे गौठानों की बात नहीं कह रहा हूँ। आप मेरी बात सुन लीजिए। जैसे आपने कहा कि आपने कोई अल्टरनेट योजना नहीं लायी। पूर्व में आपकी सरकार में कैसे किया, मैं केवल उसे बता देता हूँ। अभी आपने कहा कि कोई जांच नहीं हुई, कैसे नहीं हुई। पूर्व की सरकार में गोबर के पेंट का रेट तय नहीं हुआ। अभी आप मुझे गोबर के पेंट का रेट बता दीजिए कि उस समय इतना लीटर तय हुआ था? जब गोबर के पेंट का रेट तय नहीं हुआ था और उस समय बिना रेट तय किये करोड़ों-करोड़ों रूपये की मनमर्जी, जिस रेट में जिस विभाग को पेंट लेना है गोबर के पेंट खरीद लिए गए।

श्री उमेश पटेल :- ठीक है। आप उसकी जांच करवा कर देख लीजिए। उसमें क्या निकलता है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप उस सरकार में आप मंत्री थे तो आप बताईये कि गोबर के पेंट का रेट कितना था ?

श्री उमेश पटेल :- आप यह करिये कि हम लोगों ने गौठानों में एक व्यवस्था बनायी।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप किसी विषय की प्रशंसा करते हो तो उसके कुछ तथ्य इसलिए बताने चाहिए क्योंकि उस सरकार में आप मंत्री थे। आपको उस गोबर के पेंट का रेट बताना चाहिए ? कि हमने गोबर के पेंट का यह रेट तय किया था।

श्री उमेश पटेल :- माननीय चन्द्राकर जी, अब लेना, बइठ जा। मैं हा बतात हौं।

माननीय सभापति महोदय, हमने गौठानों में यह कोशिश की कि जिस तरह से गायों की भयावह स्थिति में दुर्घटना हो रही थी, हमने उसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था बनायी थी। उसमें प्लस, माईनस, गलत सही जो हो, आप उसके लिए कुछ दूसरी व्यवस्था बनायें या उसमें सुधार करें। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी योजना को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाये, खत्म कर दिया जाये।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय उमेश जी, इन लोग तो गौठानों को अभ्यारण्य बनायेंगे। आप मन कोन से शहर में कहां अभ्यारण्य बनाहू। तुमन बस्ती में बना दूहू का ?

श्री अजय चन्द्राकर :- बहन जी, आप सुनिए। आप कहीं भी मेरे साथ छुट्टी में चलिये। यह बाजू वाला आपका है। एक गांव में आदर्श गौठान का उद्घाटन करने गया। मैं इनसे कहा कि भाई, आप

आदर्श गौठान बोलिए या कुछ भी बोलिए तो उसकी परिभाषा तो तय कर दीजिए। आपके आदर्श गौठानों में क्या होगा और कैसे होगा ? अभी आप चलकर, उस आदर्श गौठान को देखिएगा कि आप लोगों का आदर्श गौठान कैसा है ? उसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- नहीं तो ठीक हे ना।

श्री अजय चन्द्राकर :- वहां पर एक खम्भा भी नहीं है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- ठीक है। आपने आदर्श गौठानों का बोला तो वहां पर कुछ निर्माण तो हुआ है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप चलकर उन आदर्श गौठानों को देखिए। उस समय माने पैसे खाने का ऐसा-ऐसा तरीका निकाले थे कि अब क्या बताया जाये ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप अभ्यारण्य कहां बनायेंगे ? आप बस्ती में बनायेंगे क्या ? अभ्यारण्य किसको बोलते हैं आप मुझे पहले उसकी परिभाषा बताईये।

सभापति महोदय :- आप बैठिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आप मेरे साथ चलकर आदर्श गौठान देखिएगा। किसी दिन विधान सभा का सत्र के दौरान अवकाश रहे तो किसी भी क्षेत्र का मैं, आपको आदर्श गौठान दिखाता हूँ। आपक बाजू वाले सदस्य उसका उद्घाटन करने गये थे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, इनके पास वह ऑब्शन (विकल्प) है ही नहीं कि किसी योजना को बदलकर, दूसरी योजना लायें या अच्छी चीज लायें। किसी भी योजना को बेहतर करें। उस समय आपने यहां-यहां गलतियां की थी तो हम इन-इन चीजों को सही कर रहे हैं। इनके पास ऐसा सिस्टम ही नहीं है। किसी योजना को कांग्रेस पार्टी ने लागू किया था तो अब उसको बंद करो। यदि ऐसा लगा रहा है कि यह तो थोड़ी प्रसिद्ध योजना है, उन योजनाओं का नाम बदल दिया। प्रदेश में उस योजना को चलाईये क्योंकि यह प्रदेश की प्रसिद्ध योजना है। कांग्रेस पार्टी ने बाकी योजनाओं को लागू किया, अब उसको बंद करिये। पूरे प्रदेश में ऐसा ही चल रहा है। जल जीवन मिशन योजना की बात कहना चाहूंगा। पिछले डेढ़ सालों से जल जीवन मिशन में कोई काम ही नहीं हुआ है। उसमें कुछ काम नहीं हुआ है। जहां पर पूर्णता का प्रमाण पत्र दे चुके हैं, उस स्थान में पानी नहीं आ रहा है। आपने इसमें लिखा है कि जल जीवन मिशन में 40 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल सुनिश्चित करेंगे। इन डेढ़ सालों में एक काम नहीं हुआ है। प्रदेश में एक भी काम नहीं हुआ है। आप मुझे कोई भी काम गिना दें।

श्री सुशान्त योजना :- माननीय उमेश भईया, आपके कार्यकाल की प्रसिद्ध योजना कौन सी है, जो हमने स्वीकार किया है। आप एक योजना का नाम तो बताईये ?

सभापति महोदय :- उमेश जी, आपको बोलते हुए 50 मिनट हो गया है।

श्री सुशान्त योजना :- मेरा, माननीय उमेश भईया से आग्रह है कि आपके कार्यकाल की प्रसिद्ध योजना के बारे में बताईये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, हमने छत्तीसगढ़ ओलम्पिक किया। तब यहीं पर यह लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। हमारी योजना का नाम बदलकर बस्तर ओलंपिक कर दिया। आप यह बताईये कि यह क्या है ? आपने कहा कि मतलब पूर्व वक्ता ने कहा कि इनकी जमीन खिसक रही है और आपको इस बात का पता ही नहीं है। माननीय सभापति महोदय, वहां उस तरफ बैठते हैं तो ऐसा ही महसूस होता है हम लोगों को भी ऐसा महसूस हुआ था। लेकिन जब फील्ड में रियालिटी में जाकर देखते हैं तो मैं ऐसा कहता हूँ कि आपकी जमीन खिसक नहीं रही है। यह पूरी तरह से खिसकने वाली है। इसीलिए हम आपको बार-बार चेतावनी दे रहे हैं और आपको समझा रहे है कि अभी भी आपके पास साढ़े 3 साल का समय है । आप लोग सुधर जाईये। अपने व्यवहार को सुधार लीजिए। प्रदेश की जनता को अपने अभिभावक के रूप में समझिये। माननीय सभापति महोदय, इतना कहते हुए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्रीमती गोमती साय (पत्थलगांव) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य श्री धरमलाल कौशिक जी द्वारा प्रस्तुत माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन का समर्थन करते हुए आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। इसके लिए मैं सभापति महोदय जी के माध्यम से आप सभी को व प्रदेश की जनता को बधाई देती हूं। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह जन्म शताब्दी वर्ष है। इस अवसर पर मैं उन्हें प्रणाम करती हूं। उनकी मंशा अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम के नेतृत्व में पिछले सवा साल में हमारी सरकार ने सुशासन स्थापित किया है तथा विकसित देशों की सूची में शामिल होने के लिए विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार दिन-रात मेहनत कर रही है। हमारी सरकार ने पूर्व सरकार में जो विकास की धीमी गति हुई थी और सुस्त पड़ी हुई अर्थव्यवस्था में जान फूंकने का कार्य कर रही है। सभापति महोदय, मैं सबके भाषण को बड़ी गंभीरता से सुन रही थी और अनेकों विषय में सबने अपनी बात को गंभीरता से रखा। जैसी संगति होती है, गुण वैसा ही आता है। पूर्व की सरकार में एक समय था जब पूरे देश में छत्तीसगढ़ की चर्चा महादेव सट्टा, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, चावल घोटाला पर सुनते थे। इस तरह के तमाम तरह के घोटाले थे। उसको सुनते-सुनते छत्तीसगढ़ की जनता थक गई थी। आज विष्णु देव साय जी का सुशासन जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है, उनके अनुरूप माननीय राज्यपाल महोदय जी ने अभिभाषण में जो-जो विषय कहें हैं, छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय का चुनाव हो, आज विष्णु देव साय जी की डबल इंजन की सरकार और मोदी जी की गारंटी की सरकार का

सुखद परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की विष्णु देव साय जी की सरकार को सफलता मिली है। इसकी हम लोगों को बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। उसका परिणाम जनता देती है। जनता का परिणाम ही सर्वोपरि है, वही उत्तर देने का अधिकारी होता है। मैं सबकी बात को गंभीरता से सुन रही थी। पूर्व की सरकार ने जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव में जनता के हक को छीनने का काम किया था, हमारी विष्णु देव साय की सरकार ने प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को लागू करके सही मायने में जनता के अधिकार को दिया है। यह आज उसी का दुष्परिणाम है कि अयोग्य व्यक्ति भी महापौर बन गये थे जिसे वर्तमान जनता ने पार्षद पद के लिए भी योग्य नहीं समझा। (मेजों की थपथपाहट) यह विष्णु देव साय जी की सरकार की उपलब्धि है।

माननीय सभापति जी, राज्य की खुशहाली किसानों की खुशहाली से मापते हैं। किसान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी सरकार का मानना है कि किसान जितना समृद्ध होगा, हमारी अर्थव्यवस्था भी उतनी सुदृढ़ होगी। हमारी सरकार की किसान हितैषी नीतियों के चलते किसानों की संख्या बढ़ी है। हमारी सरकार किसानों की उनकी उपज का अधिकतम मूल्य दे रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आज इसी का परिणाम है कि हमारे किसान भाई तेजी से आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं। आज ट्रेक्टर की इतनी व्यापक मात्रा से अगर खरीदी हुई है तो आज इसमें समझ सकते हैं कि कृषि से उनको कितना फ़ायदा मिला है, यह हमारे विष्णुदेव साय जी की उपलब्धि है । आज पूरे छत्तीसगढ़ के किसान खुश हैं ।

माननीय सभापति महोदय, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को साकार रूप देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना आरंभ की है जो वाकई में आज 10 साल-20 साल पीछे की बात को अगर हम लोग याद करें तो आज छत्तीसगढ़ की हरेक जनता जो अंतिम छोर में जीवन-यापन करने वाले व्यक्ति आज अपने आपको सक्षम महसूस करते हैं । माननीय महोदय जी, हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी की सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए आज तमाम तरह की योजनाएं लागू की हैं जिसमें से 1000 रूपये उनके खाते में डालकर महिला को खाली मतलब यह एहसास नहीं करा रहे हैं कि आपको 1000 रूपये दे रहे हैं, आप एक गरीब महिला के स्थान में अगर खड़े होकर उसकी व्यथा को समझें तो जैसे अपने घरवालों के पास 10 रूपये का कोई सामान होगा, अगर उसको हाथ फैलाकर कोई मांगे और यदि उसको नहीं मिलता है तो उस व्यथा को हमारे गांव की महिला ही समझ सकती है, बाकी लोग नहीं समझ सकते हैं लेकिन हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने के बाद हर माता-बहनों के खाते में 1000 रूपये एक महीने में आता है तो उनके चेहरे की चमक देखने लायक होती है यह हमारी सरकार की उपलब्धि है ।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह पूर्व की सरकार के द्वारा रेडी टू ईट को छीन करके किसी एक व्यापारी को देने का काम किया गया था । हमारी महिला स्वसहायता समूह वाली बहनों ने कितने लाखों-लाखों का machine खरीद करके रखा था जो आज रेडी टू ईट उनके समूह को मिल जाने के कारण उनके चेहरे में हम लोगों ने एक चमक देखी तो उनके भाव को हम लोग समझ सकते हैं कि उनकी मनोस्थिति में कितनी सक्षमता आयी है, कितनी ताकत आयी है उसे हम लोग देखने के बाद समझ सकते हैं ।

माननीय सभापति महोदय, आज पर्यटन क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही सुंदर प्रदेश है । चाहे भौगोलिक दृष्टि से हो, चाहे प्राकृतिक दृष्टि से हो, सरगुजा संभाग से लेकर बस्तर संभाग, दोनों संभाग में अगर देखा जाए तो पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं जिसको हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम वैश्विक पहचान बना रहा है, हमारी सरकार में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन में धुड़मारास गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिये चुना है तथा मेरे जिला जशपुर जहां विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग मधेश्वर महादेव जी यह हमारे लिए गौरव की बात है । जिस छत्तीसगढ़ को कोई जानता तक नहीं था लेकिन आज विश्व पटल पर हमारे छत्तीसगढ़ का अगर नाम हो रहा है तो यह विष्णुदेव साय जी के सुशासन का सबसे बड़ा प्रमाण है ।

माननीय सभापति महोदय, माननीय नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना यह हम लोगों के लिये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि जिस तरह से आने वाले समय में मोदी जी ने समझा है और विष्णु देव साय जी ने समझा है । आज सूर्य घर बनाकर के हर घर के मतलब छत में अगर सौरप्लेट लगता है तो हम लोगों को दूसरे से बिजली लेने की आवश्यकता नहीं है इसी सौर प्लेट से हम लोग स्वयं के काम के लिए उपयोग कर सकते हैं, हमारी सरकार की ऐसी दूरदर्शी सोच है ।

समय :
4.54 बजे

(सभापति महोदया (सुश्री लता उसेंडी) पीठासीन हुईं)

माननीय सभापति महोदया, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नक्सलवाद आखिरी सांस गिन रहा है । माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में केंद्रीय सुरक्षा बल, राज्य सुरक्षा बल के समन्वय से छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का जो उन्होंने कदम उठाया है, यह छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात है और आज सुख, चैन, अमन और शांति का जो उस क्षेत्र का हकदार है, जो बरसों से उनको नहीं मिल रहा था, आज उस क्षेत्र के लोगों में एक आशा की किरण और उम्मीद मन में उत्पन्न हो रहा है, वे स्थानीय लोग ही उस विषय को समझ सकते हैं। माननीय सभापति महोदया, हमारी इस सरकार ने सुदूर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनता का विश्वास जीता है। इसी का परिणाम है कि नक्सल प्रभावित 26 गांवों में पहली बार आजादी के बाद झंडारोहण का

कार्य हुआ है और सुकमा जिले के कई गांवों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आजादी के बाद कभी अपना मतदान का उपयोग नहीं हुआ था। आज वे लोग जब पहली बार अपने मतदान का उपयोग करने के लिए बूथ में गए होंगे, तब उनके मन में कैसा लगा होगा तो उसे तो वही लोग समझते होंगे, क्योंकि आजादी के बाद अगर किसी व्यक्ति को मतदान करने का अवसर नहीं मिला हो और पहली बार अवसर दिया हो तो उसका सुखद अनुभव वही लोग महसूस कर सकते हैं। जिस तरह से खेल जगत में बस्तर ओलंपिक युवाओं के लिए ऊर्जा का एक विषय है। खेल जगत में उनके लिए प्रेरणा का विषय है तो हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खेल जगत में बस्तर ओलंपिक योजना लागू कर युवाओं में उत्साहवर्धन करने का एक बहुत बड़ा विषय है और आज यहां मेरे पास ऐसे कई विषय आये हैं। सभापति महोदया, आज महिलाओं की सुरक्षा के विषय में हमारे इधर बैठे हुए साथियों ने कई बार महिला सुरक्षा को लेकर कई विषयों में टिप्पणी किये हैं। आज महिलाएं अपनी शिकायत बिना किसी भय के कर सकते हैं। आज हमारे चार बड़े जिलों में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग तथा सरगुजा में पांच नवीन महिला थाना खुल चुका है, जिसमें से 543 पुलिस थानों एवं चौकियों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित भी किया गया है। जो नि:संकोच हमारी महिला बहनों को जब कभी भी महसूस हो कि मैं खतरे में हूं तो यहां आकर शिकायत कर सकते हैं। इनका इलजाम लगाना व्यर्थ है। सभापति महोदया जी, आज मैं एक चीज और कहना चाहूंगी। 144 वर्षों बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ, जिसमें 66 करोड़ से अधिक लोगों ने कुंभ स्नान किया। इस महा आयोजन में हमारी सरकार ने भी प्रदेश के श्रद्धालुओं का विशेष ख्याल रखा और उनके रूकने व खान-पान की अच्छी सुविधा प्रदान की। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। इसी तरह मैं विपक्ष के हमारे सभी साथी लोगों को इतना ही कहना चाहती हूं कि सरकार आते जाते रहती है। अभी विष्णुदेव साय जी का सरकार है। दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर हम लोगों को काम करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता को हम लोग कैसे सेवा दे सकें, उस ओर हम लोगों को सोचने की आवश्यकता है। हम सब लोगों को मिल कर एक साथ काम करने की आवश्यकता है। हमारे पास विष्णुदेव साय जी जैसे मुख्यमंत्री हैं। वे सहज, सरल और बहुत ही मधुर और एक साधारण परिवार के मुख्यमंत्री हैं। हमारे पास ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास हम लोग सहजता के साथ अपनी बात रख सकते हैं। ऐसे मुखिया हमारे पास छत्तीसगढ़ में हैं। ऐसे मुखिया के नेतृत्व में हमारे विपक्ष के साथी और हम सब लोगों को एक साथ मिल कर काम करने की आवश्यकता है और अधिक से अधिक क्या अच्छा हो सके, इस विषय में सोच कर, हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है और मैं आप लोगों से निवेदन करती हूं कि हम लोगों को विष्णुदेव साय जी की सरकार का भरपूर उपयोग करना चाहिए और उनकी टीम भी बड़ी अच्छी है हमें कदम से कदम मिलाकर उनका साथ देना चाहिए । केवल विरोध करने के लिए ही विरोध नहीं करना चाहिए । जहां अच्छा काम होता है, वहां सराहना भी मिलनी चाहिए और जहां थोड़ा ठीक काम न हो रहा हो तो वहां अवगत भी कराना चाहिए । हम सबको मिलकर एक सुंदर

छत्तीसगढ़ बनाना चाहिए । आज जिस तरह से विपक्ष के साथियों ने अपनी बात रखी है । मैं बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार बहुत गंभीरता के साथ काम करेगी । हम सब इन सदन में सेवा भाव के साथ काम करने के लिए बैठे हैं, न कि एक दूसरे पर टीका-टिप्पणी करके, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए यहां नहीं बैठे हैं । जनता ने बड़े विश्वास के साथ हम सबको चुनकर यहां भेजा है । जिस काम के लिए हम यहां बैठे हैं, हम सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है (मेजो की थपथपाहट) । अंत में, दोनों पक्षों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी -

सिर्फ़ हंगामा खड़ा करना मेरा मक़सद नहीं है,
मेरी कोशिश है कि छत्तीसगढ़ की सूरत बदलनी चाहिए,
मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में ही सही,
हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए ।

बहुत बहुत धन्यवाद् ।

समय
5.00 बजे

सभापति महोदय :- चर्चा में दोनों पक्षों की ओर से प्रथम वक्ताओं द्वारा पर्याप्त बातें सभा के समक्ष रखी जा चुकी हैं । आगामी वक्ताओं से अनुरोध है कि कृपया अपने क्षेत्र से संबंधित बातों को 10-10 मिनट में रखने का प्रयास करें । श्री विक्रम मंडावी ।

श्री विक्रम मंडावी (बीजापुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं । सभापति महोदय, आज हमारे सत्ता पक्ष के साथियों ने अपनी बात रखी । मैं बहुत ही ध्यान से सुन रहा था । किस तरीके से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपनी बात रख रहे थे और लगभग एक साल तीन महीने के कार्यकाल में सभी वायदों को पूरा करने का दावा भी किया । लेकिन मैं इसको भी पढ़ रहा था । मोदी की गारंटी नाम की 56 पेज की पुस्तक को पढ़ रहा था । यहां 56 इंच नहीं, मैं 56 पेज बोल रहा हूं । इस पुस्तक में बहुत सारे वायदे किये गये थे । उनमें से कोई भी वायदा पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है । सभापति महोदय, हमारे सत्ता पक्ष के साथी कह रहे थे कि पिछले सत्र तक हम डबल इंजन में थे, फिर इस सत्र में हम ट्रिपल इंजन में आए । अब आगे कितना इंजन लगेगा या बढ़ेगा, यह मैं नहीं कह सकता । लेकिन हमारे सत्ता पक्ष के साथी बार-बार यह कह रहे हैं कि हमने वायदा पूरा किया, वायदा पूरा किया । जब हम इसको पढ़ रहे थे कि इस पुस्तक में से कितने वायदे पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं । महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई भी वायदा पूरा होता हुआ हमको तो नहीं दिख रहा है । अगर मैं किसानों की बात करूं, किसानों के बारे में सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा था कि हर पंचायत में किसानों को एकमुश्त धान का पैसा देंगे । हर पंचायत में धान खरीदी केन्द्र खोलेंगे । हर पंचायत में

पैसे का वितरण होगा । न वहां पर धान खरीदी केन्द्र खोला गया, न वहां एकमुश्त पैसा वितरण हुआ और न ही पंचायतों में पैसा मिला । इस तरह सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम सरकार ने किया है ।

सभापति महोदय, अगर मैं युवाओं की बात करूं । छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में युवा हैं । मोदी की गारंटी में युवाओं की बात हुई थी । शिक्षक के पदों पर 57 हजार युवाओं की भर्ती करेंगे । आज कितने शिक्षकों की भर्ती हुई है ? आप, हम और पूरा प्रदेश जानता है, भर्ती नहीं हुई है । क्या वास्तव में युवाओं को रोजगार मिल रहा है या रोजगार नहीं मिल रहा है, यह भी पूरा प्रदेश जान रहा है । बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, कितनों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, कितनों को नहीं मिल रहा है, यह आप जान रहे हैं । भर्तियां पूरी तरह से बंद हैं । पिछले एक साल तीन महीने में प्रदेश में एक भी बड़ी भर्ती नहीं हुई है । सत्ता पक्ष ने एक और वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा को मुफ्त करेंगे, वह भी आज तक कहीं पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस तरह से किसानों की आय दोगुनी करने का वादा हुआ था, आज किसान किस स्थिति में है, समय पर खाद बीज नहीं मिल रहा है, उनको जो बिजली की सुविधा मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रहा है, किसान बिजली कटौती से परेशान है, खाद नहीं मिलने की वजह से परेशान हैं। किसानों ने जो पिछला धान बेचा था, उनका पूरा पैसा भी अभी तक नहीं मिला है। इससे किसान परेशान हैं। सभापति महोदय, अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाएं भी अपने आपको **ठगा** महसूस कर रही हैं। यहां पर बार-बार महतारी वंदन की बात होती है, इस पुस्तक में लिखा था कि हम सभी महिलाओं को महतारी वंदन की राशि देंगे। आज कितनी महिलाओं को महतारी वंदन का लाभ मिल रहा है? कितनों को नहीं मिल रहा है, आप जानते हैं। हम सिर्फ आधी महिलाओं की आबादी को ही देने का काम कर रहे हैं। उसमें भी कितने लोगों को मिला ? उसकी स्पष्टता अभी तक सरकार के द्वारा या पक्ष के द्वारा नहीं किया गया है। आज भी ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं, जिन्होंने पिछली बार चुनाव के समय आवेदन किया था और जब-जब चुनाव आता है, तब-तब उनको फिर से फार्म भरवाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन वास्तव में जिन महिलाओं को महतारी वंदन का लाभ मिलना चाहिए, उनको आज तक पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। हमारी बहुत सारी महिला बहनें हैं जो लाभ लेना चाहती हैं, उनको नहीं मिला है। उनको **ठगने** का काम इस सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, अभी हमारे सत्ता पक्ष के साथियों के द्वारा रेडी टू फूड की बात की जा रही है, हम महिलाओं को रेडी टू फूड देने का काम कर रहे हैं। मैं हमारे साथियों से पूछना चाहता हूं कि आप रेडी टू फूड कहां दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं ? पूरे प्रदेश में उसकी शुरूआत कहां हुई है ? आप एक दो समूह का नाम बता दीजिए जहां पर हमने रेडी टू फूड दिया है। यह सिर्फ और सिर्फ कापी किताबों में नजर आ रहा है लेकिन वास्तव में धरातल पर कहीं पर भी रेडी टू फूड किसी महिला समूह को दिया है या दे रहे हैं, ऐसा नजर नहीं आ रहा है।

सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण में महिलाओं की सुरक्षा की बात कही गयी है, महिला सुरक्षा पर विशेष पहल किया गया है। आप जान रहे हैं पूरे प्रदेश में महिलाओं के साथ किस तरह से घटनाएं घट रही हैं। महिला अपराध लगातार बढ़ रहा है। उनको भी **ठगने** का काम किया गया है।

सभापति महोदय, हमारे कर्मचारी संगठनों को भी अनियमित संविदा कर्मचारी को नियमित करने की बात कही गई थी। मोदी की गारंटी 57 पृष्ठों में दावा किया गया था कि हम सरकार बनने के बाद उनको लाभ देंगे, वह भी कहीं पर पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं बस्तर से आता हूं, बस्तर के आदिवासी समाज वर्ग भी अपने आपको **ठगा** हुआ महसूस कर रहे हैं। आप तेंदूपत्ता की बात कर रहे थे, वहां पर भी 4500 रूपए मानक बोरा की दर से वार्षिक बोनस देने की बात हुई थी, वह बोनस आज पर्यन्त तक एक साल हो गया, वह भी नहीं मिला। बस्तर में ऐसे बहुत सारे शिक्षकविहीन, भवनविहीन स्कूल हैं, आप कैसे भवनविहीन, शिक्षकविहीन स्कूलों को बनाएंगे ? उनका भी इस अभिभाषण में कहीं पर उल्लेख नहीं है। सभापति महोदय, आप बस्तर की जर्जर सड़क की स्थितियां जानते ही हैं, आप भी बस्तर से आते हैं, उसका भी विशेष उल्लेख इस अभिभाषण में नहीं है। 15 दिन तक तेंदूपत्ता तोड़ाई के बारे में भी उल्लेख नहीं है। सरकार बनने के बाद लगातार 15 दिनों तक तेंदूपत्ता तोड़ाई करेंगे, मुश्किल से बस्तर में 2, 3 दिन से उपर तेंदूपत्ता की तोड़ाई नहीं होती है। मैंने पिछली सरकार में भी इस बात को रखा था। बस्तर में ग्रामीण आदिवासी, गरीब लोगों का सबसे बड़ा आय का जरिया तेंदूपत्ता है, उन्हें एकमुश्त पैसा मिलता है और वे सालभर इंतजार में रहते हैं कि कब तेंदूपत्ता का पैसा मिलेगा। उसके बाद उनका जीवन आगे बढ़ता है। वह भी वादा पूरा नहीं हुआ है। फड़मुंशियों को वार्षिक 25000 रूपए दिए जाएंगे, वह वादा भी पूरा नहीं हुआ है। यह बस्तर के साथ **छलावा** है। 5 लाख वन अधिकार पट्टा देने की बात हुई थी, लगभग साल भर होने को जा रहा है, वहां पर कोई भी पट्टा वितरण किसी भी आदिवासी परिवार, गरीब परिवार को नहीं मिला है। जहां तक नक्सली की बात है, हमारे सत्ता पक्ष के सभी साथी कह रहे थे कि नक्सल मुक्त बस्तर हुआ है। नक्सलवाद पर मैं कोई कांग्रेस या भाजपा की बात नहीं करना चाहता हूं और मैं इस सदन से भी अनुरोध करता हूं कि यह बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं उस क्षेत्र से आता हूं, जो सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिला है, बीजापुर। आप सब जानते हैं कि वहां पर नक्सलवाद कोई कांग्रेस या बीजेपी का मुद्दा नहीं है और न होना चाहिए। लेकिन यदि आप सिर्फ और सिर्फ पेपर में असत्य दावा करेंगे तो उससे भी काम नहीं चलेगा। बस्तर का हर एक आदिवासी और ग्रामीण चाहता है कि बस्तर में शांति हो, विकास हो और उसके बच्चे पढ़ें। लेकिन पिछले साल भर से हम सिर्फ यह सुनते और देखते आ रहे हैं। हमें इससे और आगे बढ़ने की जरूरत है और सच्चाई के साथ काम करने की जरूरत है कि वास्तव में वहां की जनता क्या चाहती है। असत्य और वाहावाही लूटने से बहुत जल्दी सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार इसमें और अच्छी

पहल करे और वास्तविकता में जाये कि वास्तव में हो क्या रहा है, दिख क्या रहा है और होना क्या चाहिए। इसपर भी विचार होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदया, स्वास्थ्य के बारे में बता रहे थे। मैंने पिछली बार भी इस सदन में इस बात को रखा था कि आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से जो इलाज होना चाहिए, लेकिन निजी अस्पतालों में उस योजना के माध्यम से पूरी तरह से इलाज बंद है। उसकी सहायता राशि को 5 लाख रूपये से बढ़ाकर 10 लाख रूपये करने की बात हुई थी, लेकिन 5 लाख रूपये का भी इलाज निजी अस्पतालों में नहीं हो पा रहा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इसपर पहल करने की कृपा करें। पिछली बार मैंने कहा था कि भुगतान नहीं होने की वजह से निजी अस्पतालों ने इलाज करना बंद कर दिया है, लेकिन भुगतान हो चुका है और उसके बाद फिर मैं निजी अस्पताल में गया था तो उनका भी यही कहना है कि हमको अभी भी भुगतान नहीं हुआ है, इस वजह से वहां पर आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।

सभापति महोदया :- मण्डावी जी, आपको 10 मिनट हो गये हैं। कृपया आप समाप्त कीजिए।

श्री विक्रम मण्डावी :- जी, मैं केवल 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। सभापति महोदया, उसके बाद भी सरकार का यह कहना कि हम सहायता राशि को 5 लाख रूपये से बढ़ाकर 10 लाख रूपये कर रहे हैं, यह सिर्फ असत्य है। आप जो 18 लाख आवास देने की बात कर रहे हैं। आप बार-बार 18 लाख आवास-18 लाख आवास देने की बात कह रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि आपने कितने गरीबों को 18 लाख आवास दिये हैं, उसकी भी आपको सार्वजनिक सूची जारी करनी चाहिए कि वास्तव में सरकार बनने के बाद पिछले साल भर के अंदर कितने गरीबों को 18 लाख आवास मिले हैं। कानून व्यवस्था के चौपट होने की बात भी यहां पर होनी चाहिए थी। यह पूरी तरह से असत्य है और यह कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। आज पूरे प्रदेश में लगातार हत्या, लूट, डकैती और बहुत सारी घटनाएं बढ़ रही हैं। इसकी कहीं पर भी रोकथाम नहीं हो रही है। ऐसा कोई दिन नहीं है, जब हम लोगों को समाचार पत्रों में या न्यूज चैनलों में ऐसी घटनाओं की जानकारी न मिले। समाचार पत्रों व न्यूज चैनलों में लगातार यह समाचार आ रहा है कि किस तरीके से ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। उसके बावजूद भी सरकार का यह कहना कि यह पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ है।

श्री नीलकंठ टेकाम :- मण्डावी जी, यह जो प्रधानमंत्री आवास है, वह तो पब्लिक डोमेन में उस लिस्ट में है। आप ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर लीजिए न।

सभापति महोदया :- मण्डावी जी, कृपया आप समाप्त कीजिए।

श्री विक्रम मण्डावी :- सभापति महोदया, केवल दो मिनट। आपकी सरकार बनने के 1 साल, 2 महीने में ये स्थितियां हैं तो इससे आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि प्रदेश में अवैध शराब, नकली शराब व जुआं की क्या स्थिति है। दूसरी बात, हमारे मंत्री जी बार-बार चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं।

चुनाव जीतने से कुछ नहीं होता है। सरकार में रहकर चुनाव कैसे जीता जाता है, यह तो सब जानते हैं। आप उसका आकलन चुनाव जीतने से नहीं कर सकते हैं। हमारे वरिष्ठ सदस्य माननीय धर्मजीत भैया भी बार-बार बोल रहे थे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का विरोध कर रहे हैं। वह आदिवासी परिवार से हैं। हम भी आदिवासी परिवार से हैं और हमको भी खुशी है कि हमारे समाज से वह मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन जो बाते हैं, उनको विपक्ष में होने के नाते हम लोग कह रहे हैं कि वास्तव में यदि यह सरकार सुशासन की सरकार है तो आखिर किस तरीके से यह सरकार चल रही है और सरकार को कौन चला रहा है ? यह डबल इंजन की सरकार है या ट्रिपल इंजन की सरकार है ? इस बात को हमने रखा है। यदि विपक्ष विरोध करता है तो इसका मतलब यह मुख्यमंत्री जी का विरोध नहीं है, बल्कि यह नीतियों का विरोध है। वास्तव में हमने जो बात रखी है कि सरकार कौन चला रहा है तो आज भी यह बात सही है। सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह :- मण्डावी जी, क्या है कि आप तो कागज लेकर सीधे मुख्यमंत्री जी के पास चले जाया करिये। आपका सब काम हो जायेगा। यदि आप रामकुमार जी और निषाद जी के चक्कर में आएंगे तो ये लोग उल्टा-सीधा बोलवाते हैं। आप मत बोलवाइये।

श्री विक्रम मण्डावी :- नहीं, मैं किसी के चक्कर में नहीं आता हूं। आप निश्चिंत रहिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- धर्मजीत भैया, ऐहा मोर चक्कर में रहही तो बढ़िया रहही।

सभापति महोदया :- श्री गुरू खुशवंत साहेब जी।

श्री गुरू खुशवंत साहेब (आरंग) :- माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। समाज में मनखे-मनखे एक समान, कह गए गुरू घासीदास महान। समाज में आपसी सौहार्द्र व समरसता का संदेश देकर समाज-जाति के कल्याण हेतु संघर्ष करने वाले सतनाम धर्म के प्रवर्तक व सत्य को स्थापित करने वाले परम पूज्य गुरू घासीदास बाबा जी के वंशावली से मैं एक छोटा सा सदस्य हूं। सत्य ही मेरा आधार है, सत्य ही मेरे ईश्वर हैं, इसलिए मैं केवल सत्य ही कहूंगा। माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार का जो स्वरूप नजर आ रहा है, वह उन्नत छत्तीसगढ़, प्रगतिशील छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ का संकेत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की कल्पना और माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के कुशल मार्गदर्शन में छत्तीसगढ समग्र विकास के सपने साकार कर रहा है। लगभग सवा साल की हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार ने अभूतपूर्व सफलता अर्जित की है। आमजनों का विश्वास हमने जीता है। हमारी कोशिश यही है कि समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक लोक कल्याणकारी योजना को उन तक पहुंचा सकें।

"जीतूंगा मैं यह मेरा वादा है, कोशिश मेरी सबसे ज्यादा है,
हिम्मत भी टूटे तो भी नहीं रूकूंगा, मजबूत मेरा ईरादा है।"

माननीय सभापति महोदय, लोकतन्त्र में जनमत का बहुत बड़ महत्व है। लोकशक्ति ही राष्ट्रशक्ति होती है और हमारे लिए यह गर्व और उपलब्धि का विषय है कि राज्य सरकार बनने के बाद लोकसभा के निर्वाचन हो या स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम हो, भारतीय जनता पार्टी की नीति और योजनाओं का समर्थन किया है। आमजनों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ता हुआ निरंतर विश्वास इस बात का प्रमाण है, जो हम कहते हैं, वह करते हैं। विधान सभा चुनाव के पहले हमने जिन वादों को आम जनता के समक्ष रखा था, हमने विगत सवा साल में उन सभी वादों को पूरा करने का भरपूर प्रयास किया है, ईमानदार कोशिश की है। राज्य किसानों के उपज का मूल्य हो, धान खरीदी हो, महतारी वंदन योजना हो, गरीबों के लिए आवास की योजना हो, आदिवासी कल्याण के लिए जनजातीय विकास की योजना हो, हमारे अनुसूचित जाति भाईयों के कल्याण के लिए योजना हो, समाज के सभी वर्गों के समावेशी विकास के लिए सरकार के सभी प्रयास परिणाम सिद्ध हो रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है। जो लोग लक्ष्य तय करके और योजना बनाकर काम करते हैं, उनके सफल होने की संभावनाएं काफी अधिक होती हैं। माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी जनता के विश्वास का नाम है। भारतीय जनता पार्टी जन-जन के विकास का नाम है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रेम, सद्भाव और समन्वय का नाम है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में सरकार के उन समस्त नीतियों का उल्लेख किया है, जिसे हमारी राज्य सरकार क्रियान्वित कर रही है अथवा क्रियान्वित करने जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी की देन है। माननीय अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का सपना साकार किया है। भारतीय जनता पार्टी का सुशासन, भ्रष्ट्राचार मुक्त समाज निर्माण का संकल्प है। हमारी राज्य सरकार ने सुशासन के माध्यम से पूर्ण पारदर्शी ढंग से कार्य किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने पूरी दृढ़ता से कार्य किया है। पूर्ववर्ती सरकार ने जो शराब घोटाला किया था, पी.एस.सी. घोटाला किया था, कोयला घोटाला किया था और ना जाने कितने घोटाले किए थे, उन सभी पर जांच के किए और जांच में बहुत सारे जेल में है और बहुत सारे अभी जो बचे हुए हैं, वे आने वाले समय में उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी है।

माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी मातृशक्ति के सम्मान और सुरक्षा के प्रति सदैव गंभीर रही है। लोकसभा के पिछले कार्यकाल में महिला आरक्षण बिल पास हुआ था। वहीं हमारी राज्य सरकार ने महतारी वंदन योजना के माध्यम से राज्य की माताओं-बहनों के आर्थिक स्वलंबन और महिला सशक्तिकरण के संकल्प को पूर्ण किया है। महतारी वंदन योजना से हमारी बहनें-माताएं केवल आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हुईं, बल्कि इसके माध्यम से आर्थिक रूप से स्वावलम्बन की ओर बढ़ रही हैं। यह योजना उन्नत और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए वरदान ही है। नारी को सशक्त करने से ही भारत पुन: विश्व गुरू बनने का अपना संकल्प पूरा करेगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर चल रही है। हमारी केन्द्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, हमारी सरकार की नीतियां केन्द्र में आम आदमी ही है समाज के गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों की सेवा हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना प्रथम दायित्व मानती है। पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अन्त्योदय विकास का पुनीत संकल्प ही हमारी सरकार का ध्येय रहा है। माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, शहीर वीर नारायण आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के माध्यम से 77 लाख 20 हजार परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने का उल्लेख किया है।

माननीय सभापति महोदया, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार दिया है। सभी शासकीय चिकित्सालयों में स्वास्थ्य सेवा को और अधिक बेहतर बनाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। मैं उस विधान सभा क्षेत्र का सेवक हूं, जहां कौशल प्रदेश छत्तीसगढ़ की राजकुमारी तथा अयोध्या के राजा दशरथ की पत्नी और देवमाता अदिति की अवतार थीं। माता कौशल्या का जन्म रायपुर जिले के चंदखुरी नामक ग्राम में हुआ था। कौशल्या माता का एकमात्र मंदिर यहीं चंदखुरी में स्थित है, जहां माता कौशल्या बालस्वरूप श्रीराम जी को गोद में लिए हुए हैं।

"कौशल्या नंदन है जो अपने प्रभु श्रीराम करता हूं,
उनका वंदन इस दिन पूरे आठों धाम,
इस स्वार्थ भरी दुनिया में उनके सिवाय मेरा कौन,
वही मेरे रखवाले, वही सुधारते बिगड़े काम।
जय श्रीराम। राम का वंशज हूं, गीता मेरी गाथा है,
छाती ठोक कर कहता हूं, भारत ही मेरी माता है।"

सभापति महोदया, प्रयागराज में 45 दिनों तक विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक एवं आध्यात्मिक समागम महाकुंभ वर्ष 2025 बुधवार को अंतिम स्नान महाशिवरात्रि के साथ सम्पन्न हुआ। 13 जनवरी, 2025 को प्रारंभ हुए महाकुंभ मेले में देश-विदेश से 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा नदी और संगम में डुबकी लगाई।

"मंजिलों की तलाश में सफर पर निकल आया हूं,
मुश्किलों से भरे हालात में घर से निकल आया हूं,
कई जिम्मेदारियां हैं, निभाना है, जिद्द है कुछ कर गुजर जाना है।"

माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, उद्योग, आवागमन, सिंचाई, पेयजल एवं ऊर्जा संबंधित जिन भी बिन्दुओं उल्लेख हुआ है, उन सभी बिन्दुओं पर हमारी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, पारदर्शिता के साथ कर रही है।

इसलिए मैं माननीय राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मैं अंतिम में यही कहूंगा -

"ताजमहल की बात तो पुरानी हो गई,

दुनिया अयोध्या के श्रीराम मंदिर की दीवानी हो गई।"

जय जय श्री राम। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदया :- श्री रामकुमार यादव।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय सभापति महोदया जी, धन्यवाद्। मैं माननीय राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के विरोध मा बोले बर खड़े हौं। मैं सिर्फ एखर खातिर विरोध नई करत हौं, हमन विपक्ष मा बइठे हन ता सिर्फ विरोध करना हमर उद्देश्य नई हे। मैं आज ओ दिन ला याद करत हौं। आज से एक साल तीन महीना पहिली, इहां पहला पंक्ति मा ये जेतका बड़े-बड़े मंत्री बनके बइठे हे, पाय-पाय बजत हे अऊ बिजली जलत रोड में गाड़ी चलत हे, आगे-पीछे पुलिस गाड़ी लगे हे, ये मन गांव-गांव में जाय अऊ जाकर भाषण देवय अऊ काय भाषण कहय ओला मैं आज कहना चाहता हौं। ओ बात ला ये मन नई करय तेखर कारण मैं हर विरोध करे बर खड़े हौं। माननीय सभापति महोदया जी, पहिली तो दिल्ली मा ये मन के एक ठन इंजन रिहीस हावय। ओखर बाद में पता नहीं, जइसे कोई भी व्यक्ति ला एक इंजन मा भरोसा नई रहय एक इंजन हा अच्छा नई रहय त एक ठन अऊ इंजन जोड़थे। ये मन के डबल इंजन जुड़ गईस, लेकिन डबल इंजन मा भी मन नई माढ़िस त तिबल इंजन हो गे। अब इंजन कहत-कहत छोटे-बड़े ये मन के सरकार के चार ठन इंजन हावय। चार ठन इंजन तो जुड़ गइस, लेकिन विकास रूपी डब्बा अभी भी गोल हावय। विकास के डब्बा कइसे गोल हावय? ये मन कहे रिहीस हावय कि हमारी सरकार आएगी तो किसानों को लाईन में लगने नहीं देंगे, आपके घर में पैसा पहुंचा कर देंगे। किसान मन ताली बजावय। ये मन ला किसान मन भर-भर वोट दे दिस। ये मन अऊ काय कहे रिहीस कि 3100 रूपये धान के पइसा देबो अऊ अगर दिल्ली मा केन्द्र सरकार हा पैसा ला बढ़ा दिही तहू ला तुमन ला जोड़ के देबो। छत्तीसगढ़ के 3100 रूपये अऊ 170 रूपये दिल्ली सरकार के। जे दिन भी छत्तीसगढ़ के जनता हर ये मन ला पूछही कि दिल्ली से जे 170 रूपये आय हे, ओ हर कहां हे? चन्द्राकर जी के चेथी के रूंवा हर खड़े हो जाही। 170 रूपये पैसा कहां हे, ओला कोन रखे हावय? ये मन का जवाब दिही। एखर खातिर आज रामकुमार यादव किसान के पक्ष मा खड़ा होथे कि छत्तीसगढ़ के 170 प्रति क्विंटल के हिसाब तुमन ला करे बर लागही। आज ये मन कहे रहिस हे, युवा। ए मेर युवा मंत्री बहुत झन हावय। युवा बोलता है, छत्तीसगढ़ बोलता है। ये हर ये मन के भाषण रिहीस हावय। ओ युवा जेन पढ़-लिख कर एक ठन भरोसा करथे कि आज छत्तीसगढ़ में ये मन एतेक बड़े वादा करे हे, 33,000 पद मा भर्ती करही। आज ये मन ला भर्ती करके बेचारा मन ला निकालत हावय। वाह रे छत्तीसगढ़ की ? सभापति जी, अइसे बहुत आदमी गरीब घर के रइथे, गरीब के कोख ले जनम लेके,

वहु हा बड़े आदमी बने के सपना देखथे, वोमन कथे कि अगर सरकार बेरोजगारी भत्ता देतिस त कहीं मेर फीस ला पटाके बेरोजगारी भत्ता के फारम ला भर देतेंव । आज एमन एक रूपया बेरोजगारी भत्ता देवत नइ हे ? सभापति महोदय, एमन युवा साथी के काय बात करथे, एमन ला कोई अधिकार नइ ये ? मैं आज कहना चाहथंव कि एमन मितानिन मन करा गे रिहिन, आज स्वास्थ्य मंत्री जी भाषण ला सुनके स्वयं सूजी देवाय ला चल दे हे का ? मितानिन मन कना गिन, एमन कहींन मितानिन, स्वास्थ्य के एमन कर्णधार हे, हमारी सरकार आने दो, मितानिन कैसा काम करेंगी, हम बतायेंगे । सभापति महोदय, आंगनबाड़ी स्वीपर, अंशकालीन स्वीपर, जेमन तीन घण्टा, चार घण्टा काम करथे, अऊ वोला कइथे तुमन चले जाओ, वो बेचारा कहां जाही ? वोखर समय बरबाद हो जाथे । एमन कहे रहिने कि अंशकालीन स्वीपर मन के हमन वेतन बढ़ाबो, अऊ वेतन भोगी कर्मचारी रइथे, वोखर वेतन बढ़ाबो । सभापति महोदय, मैं आज पूछना चाहथंव कि मोर सरकार हो, छत्तीसगढ़ के भाग्य विधाता हो, चार इंजन के सरकार हो, तुंहर वादा कहां गिस ? सभापति जी, मोला बोलन दव ।

सभापति महोदय :- अपन क्षेत्र के बात ला बोल के जल्दी समाप्त करव, बाकी तो टीका-टिप्पणी में आ जाथे ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, एमन के चार इंजन काय काम करथे, एखर मन के विकासरूपी डब्बा गोल हे, सिर्फ इंजन बाचे हे, अऊ इंजन में धुंवा ही धुंवा भरे हे ? आज मैं आदिवासी समाज के बात करना चाहथंव, हमर धरमलाल कौशिक भईया हा कहात रहिसे कि इंहा आदिवासी मुख्यमंत्री बने हे त तुमन के छाती हा जलथे । ददा, हमन आदिवासी, मैं त यादव आंव । सौरा अऊ यादव के जोड़ी, माढ़े हे, काय कथे कि रऊत के छांदे त सौरा के पांगे । सभापति महोदय, हमन एकेच हरन । सभापति महोदय, आदिवासी समाज के बात करथे, आज मैं अतका कन आदिवासी समाज बता दिहंव जेमन जाति प्रमाण पत्र के नाम पे रोवथे । मैं मुख्यमंत्री कना लेके आय रेहेंव, फोटो खिंचईन, वोखर नाम हे पोबिया-पबिया समाज, हमर इंहा मान लिस आदिवासी समाज एक कहिके, वोला दिल्ली भेज दिन, आज भी वोमन के जाति प्रमाण पत्र नई बनथे । सभापति महोदय, एमेर बहुत झन आदिवासी समाज के मंत्री बैइठे हे, आप मन अपने समाज के हित के काम नई कर सकथव, वोला तुमन रोड-पानी-बिजली मत देवव, जाति प्रमाण पत्र दे देवव । सौंरा,पाव, पोबिया, खड़िया, मांझी, राव, धनवार, कोड़, कोड़ा 22 ठन जाति के जाति प्रमाण पत्र आज नइ बने हे, आज काय बात करथव ? आप अपन दिल ला झांक के देखव, ये मोर दिल के बात ए, जब मैं विधायक नइ बने रेहेंव...।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप अपन क्षेत्र के बात ला बोल के समाप्त करव ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, रामकुमार हा सौंरा,पाव, पोबिया, खड़िया, मांझी, राव, धनवार, कोड़, कोड़ा के लिये आंदोलन करने वाला व्यक्ति हरय। तुंहर सही सीट में बैठने वाला व्यक्ति नई हरै ?

श्री अजय चन्द्राकर :- रामकुमार जी, अभी जैसे याद कर रहे हो ना, उस समय मैं विधायक नहीं बना था, अभी बोलो कि अभी मेरी शादी नहीं हुई है । तब वैसा बोल रहा हूँ । जब विधायक नई बने थे तो मेरी शादी नहीं हुई है, तब ऐसा बोल रहा हूँ । शादी होही त अइसे करहूँ कईके । (हंसी) बोलना, शाही होही त मैं अइसे करहूं कइके ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, ज्ञान कई प्रकार के होथे ।

सदन की सूचना

सभापति महोदय :- माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन पर चर्चा हेतु अभी 6 सदस्यों को अपनी बातें रखना है, इसके बाद माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब भी आना है । दिनांक 28-02-2025 को भोजन अवकाश के बाद अशासकीय कार्य लिया जाना भी निर्धारित है, अत: चर्चा समय पर पूर्ण हो सके, इसलिये सभा के समय में 1 घण्टा और वृद्धि की जाये । मैं समझती हूँ कि सभा सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (क्रमश:)

श्री रामकुमार यादव :- धन्यवाद सभापति जी । आप मन सभापति करथव त बहुत अच्छा लागिसे । समय बढ़ाववं । सही ला एमन सुनय ।

सभापति महोदय :- आप अपन क्षेत्र के बात ला खतम करके जल्दी पूरा करव।

श्री रामकुमार यादव :- हमर गुरू गोसाई जी बोलत रहिसे, पढ़त रहिसे कि हमन गुरूघासीदास जी के वंशज अन, मैं आप ला प्रणाम करथंव । मोला आज खुशी ए बात के होईसे कि आप राम भगवान के गुणगान करे हव अच्छा बात ए, लेकिन दुख ए बात के होईसे कि आज परम पूज्य गुरूघासीदास जी के जैतखंब ला आप के दल के मन रक्षा नई कर पाईस, वोखर विरोध नई कर पायेव, ए बात के मोला दुख होइसे । आज मैं कहना चाहथंव कि छत्तीसगढ़ में 250 साल पहले परम पूज्य गुरूघासीदास बाबा जी कहे रहिसे कि मनखे-मनखे एक समान । मंदिरवा में काय करे जाबो, अपन घर के देवता ला मनाबो । अऊ रविदास जी काय के हे रहिसे, रविदास जी कहे रहिसे कि मन चंगा त कठौती में गंगा । सभापति महोदय, ए बात के समीक्षा हमन ला करना चाही । अऊ एक ठन कहे रहिसे कि...।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आपको बोलते हुए 8 मिनट हो गए हैं । अपने क्षेत्र की बात बोलकर अपना भाषण समाप्त करिए ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, हमर महापुरूष मन एक ठी अउ बात केहे रिहीसे । का केहे रिहीसे ? तीरिथ गए तीन झने ठग, ठाकुर और चोर । पाप तो घटै नहीं, तीन मन लादे और । अउ आज मैं देखथौं कि ए मन के जो कर्म हे, ए मन के पाप तो घटत नहीं हे, तीन मन अउ लदत जात हवय । एकर खातिर मैं आपला कहना चाहथौं कि ये सरकार ह छत्तीसगढ़ के जनता से जो-जो वादा करे हे, ओला पूरा करौ, नहीं तो छत्तीसगढ़ के जनता सबला देखथे, बोलत कुछ नहीं हे। तुमन कहात हौ कि इंजन के ऊपर इंजन जोड़त जावथे, ले त एक ठी इंजन ले ले, दू ठी इंजन ले ले, तीन ठन इंजन ले ले और ग्राम पंचायत होवत ले चार इंजन हो जहि, लेकिन आप ला काम करे बर लागही ।

सभापति महोदय, अंत में मोर क्षेत्र के बात हे । जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार रहिसे त मोर क्षेत्र 4 ठी बड़े-बड़े पावर प्लांट खोलिन, लेकिन सड़क नहीं बनईन । पहली से जेन सड़क रिहीसे, ओमा गाड़ी चला-चला के ए मन धुर्रा मता दे हें, ओ क्षेत्र मा रेंगत नहीं बनथे, ओ क्षेत्र के आदमी मन बीमार पड़ जाथे, मोर आपसे निवेदन हे कि ए मन ला निर्देशित करौ कि क्षेत्र कहीं भी रहाय, चाहे वह कांग्रेस पार्टी के विधायक के रहाय या भाजपा पार्टी के विधायक के क्षेत्र रहाय, ए मन ला एक ठी चश्मा से देखना चाहिए । छत्तीसगढ़ के सबके साथ, सबके विकास कहिथे, लेकिन ए मन अलग-अलग चश्मा लगाए हे । अगर मोर क्षेत्र में ए मन कम्पनी से रायल्टी लेवथे तो क्षेत्र के रोड़ ला भी बनाए बर लागही । नहीं तो रामकुमार यादव आपके माध्यम से कहाथे कि कल वहां पर चक्का जाम, आन्दोलन करही तो मोर नाम से एफआईआर करहिं, एमन मोला अंदर करहिं, यह मैं जानथौं। तेकरे खातिर मैं आप ला पहिली अगाह कर दे हवं । ए मन छत्तीसगढ़ के जनता ला वादा करके सरकार में आए हे, ओमा एको ठी वादा पूरा नहीं करिस, तेकर खातिर मैं छत्तीसगढ़ सरकार के अउ अभिभाषण के घोर विरोध करते हुए अपन वाणी ला विराम देवथौं ।

श्री प्रबोध मिंज (लुण्ड्रा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आपने अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । हमारे विपक्ष के साथियों को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि राज्यपाल जी के अभिभाषण पर उन्होंने बहुत शालीनता से बातों को सुना है, कोई टोका-टाकी नहीं की । हमारी सरकार की जो उपलब्धि है, उसका उल्लेख राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में किया है और उस अभिभाषण में सभी सदस्यों ने अपनी बातें विस्तार से की हैं । चूंकि आपका निर्देश है कि संक्षेप में बोलना है, मैं बहुत लंबी बातें नहीं करूंगा, सबने अपनी बातें की हैं । धरम लाल जी ने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी, धर्मजीत जी ने भी अपना विषय रखा, लेकिन राज्यपाल जी का अभिभाषण इन किताबों में कई बिन्दुओं पर दर्ज है । उन्होंने पहले ही कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश को हम सब लोगों को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है और भारतीय जनता पार्टी के एक साल के कार्य में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ी भी है और उस लक्ष्य को पाने के लिए लगातार इस क्षेत्र में योजनाएं बनाकर काम करने का प्रयास एक साल में हुआ है । इसी कड़ी में 25 वर्षों

में छत्तीसगढ़ में मानव संसाधन और अधोसंरचना विकास के कार्य हुए हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ साल की बाधा और कमजोर प्रगति के बाद यह विकास प्रक्रिया पुन: तेज होगी । इसका तात्पर्य यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद 25 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 15 वर्षों तक लगातार काम करने का अवसर मिला । पिछले पॉच वर्ष में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी । उस 5 साल के कार्यकाल के एक झलक का उल्लेख उन्होंने किया है । उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में एक वर्ष से काम शुरू किया है। यह पहली सरकार है, जिसने अपने एक साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जनता को पेश किया है । विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में यह पहली सरकार है, जिन्होंने अपनी घोषणाओं पर अमल किया, जो मोदी जी का गारंटियां थीं, उसे चुनाव में लेकर गए थे । उन सारी चीजों को एक साल में पूरा किया, चाहे वह धान की कीमत हो, चाहे तेंदूपत्ता का मामला हो, बोनस का विषय हो, महतारी वंदन का विषय हो, क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेव्हपल करने का विषय हो और पहले ही बजट में हमारे नौजवान वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी जी के नेतृत्व में जो बजट पेश हुआ था, उस बजट में पूरे साल हमारे काम करने की झलक थी और एक वर्ष में जो वायदे उन्होंने पूरे किये, हम सब लोगों ने कहा था कि धान की कीमत 3100 रुपए देंगे और एक साथ देंगे। मैं बताना चाहूंगा कि अभी रामकुमार जी बड़ी-बड़ी बात कर रहे थे कि चार इंजन की सरकार बन गई है। भईया रामकुमार जी, डबल इंजन की सरकार तो विधान सभा और लोक सभा में बनी थी और उसी में बता दिया था कि इंजन बहुत पॉवरफुल इंजन है। इतनी बड़ी संख्या जो आपकी इधर थी, चंद लोगों में सिमटकर उस पार चली गई। केन्द्र में भी हमारे छत्तीसगढ़ की जो लोक सभा सीटें थीं, इतने बड़े बहुमत के साथ हम सब लोगों ने जीता था। तो बहुत पॉवरफुल इंजन डबल इंजन लगा है। आप तीसरे इंजन की बात कर रहे हैं ना, अभी नगर निगमों के चुनाव हुए, इस इंजन की तो बात ही छोड़िए कि कितना पॉवरफुल है, 10 के 10 निपट गए। 10 के 10 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। एक साल के बाद ये चुनाव हुए थे और इस एक साल में जनता ने भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार और विष्णु देव साय की जो हमारी नीति, नीयत और उपलब्धियॉ हैं, जो घोषणाओं पर अमल हुआ है, उसका परिणाम है कि जनता ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है और हम सबके सामने 10 के 10 नगर निगम में हम और चंद नगरपालिकाओं में आप आए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- केवल और केवल सदन में और अखबार में। धरातल में डबल इंजन का परिणाम बताइए। धरातल में बताइए कि एक साल में सरकार कितना कर्ज ले ली? डबल इंजन क्या मदद कर रही है? ऐसी कौन सी योजना है, जिसमें डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ को अलग से राशि दी है?

श्री प्रबोध मिंज :- आप सुनने की क्षमता रखिए। अभी तो एक साल में आपने झलक देखा है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मैं पूरा सुन रहा हूं। आप लॉटरी निकलवाकर चलिए धरातल में। डबल इंजन का डेढ़ साल में प्रभाव बताइए।

श्री प्रबोध मिंज :- मैं धरातल की बात पर आ रहा हूं। आप बैठिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप सदन को गुमराह कर रहे हैं, डबल इंजन, चार इंजन।

श्री प्रबोध मिंज :- आपने कहा, रामकुमार जी ने कहा था कि चार इंजन की सरकार। मैं तीसरे इंजन तक पहुंचा हूं और उतने में ही अकबकी छूट गई। चौथा इंजन जो बता रहा हूं, ग्राम पंचायतों के लिए पंचायती राज के जो चुनाव हुए हैं, उस इंजन को भी देखिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- हम सुनने के लिए तैयार हैं लेकिन आप डबल इंजन-डबल इंजन। किसी भी योजना में धरातल पर बताइए ना।

श्री प्रबोध मिंज :-अभी एक साल में चारों इंजन जब दौड़ेंगे ना, तब छत्तीसगढ़ का विकास देखिएगा। मैं आपको एक झलक बता रहा हूं। आपके महतारी वंदन योजना में हमने महिलाओं को वायदा किया था, उसे दिया। हमने 3100 रुपए दिया और आप चार किश्तों में पैसा देते थे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- चार किश्त में क्यों दिए, क्योंकि केन्द्र सरकार की नीयत नहीं थी कि उसे दें। हमें बाध्य किया गया। माननीय विधायक जी, आप कलेक्टर की पत्नि को, मुख्य मंत्री की पत्नि को देने की बात किए थे।

सभापति महोदय :- आप लोग सीधे आपस में बात न करें। सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री प्रबोध मिंज :- हमने केन्द्र सरकार की योजनाओं का पैसा, धान की कीमत किसानों के खाते में समय पर दी और उनकी धान की खरीदी के बाद जो राज्यांश हमें देना था, राज्यांश का हिस्सा धान खरीदी के बाद पिछले साल हमारी विष्णु देव की सरकार ने सारे किसानों को एकमुश्त दिया, जबकि आप चार बार में पैसे देते थे और चंद-चंद पैसे चार किश्तों में जाते थे, जबकि धान तो एक बार में किसान का ले जाते थे। आज दुकान में कोई उधारी देता है क्या? पैसा जमा हो जाता है और बाकी सामान थोड़ा-थोड़ा ले जाओ। हमारी सरकार में विष्णु देव जी ने धान का पैसा लगातार दो बार में किसानों तक पहुंचाया। आप महतारी वंदन की बात कर रहे थे कि 500 रुपए कम करके दे रहे हैं। 500 रुपए कम का विषय नहीं है लेकिन हमारी वे माता-बहनें जो कि छत्तीसगढ़ के गांव, देहात, गरीब क्षेत्रों की रहने वाली हैं, उनके लिए 1000 रुपए भी बहुत होता है। घर के छोटे-छोटे सामान को पूरा करने के लिए, जरुरतों को पूरा करने के लिए उन माताओं-बहनों को महतारी वंदन योजना से पैसा मिल रहा है। ये हमारी योजनाएं हैं।

माननीया सभापति महोदया, गरीब महिलाएं जंगलों में जब तेंदूपत्ता तोड़ने जाती थीं, तो हमारी सरकार में उस समय जूते-चप्पल की योजना थी, जो कि उनके पॉव में पहनाया जाता था, जिससे कांटों से उनका बचाव होता था और गर्मी में उन्हें राहत मिलती थी।

सभापति महोदय :- मिंज जी, अपने क्षेत्र की बात कहकर समाप्त करें।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय सभापति महोदया, 5500 रुपए में हमारी सरकार वहॉ तक पहुंचाकर उनको दे रही है। सभापति महोदय, मेरे कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहा है, उस लाईन पर लगातार चल रही है, आगे बढ़ रही है।

सभापति महोदया, आज हम सब नक्सल क्षेत्र की बात करते हैं। जब वर्ष 2003 में हमारी सरकार नहीं थी, तब सरगुजा एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। वर्ष 2003 के पहले हम अंबिकापुर शहर के रहने वाले लोग दो किलोमीटर-तीन किलोमीटर दूर जाने में डरते थे, इतना आतंक था। नक्सलियों का वह बड़ा आतंक बस्तर में भी था। डॉ. रमन सिंह जी के समय में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरगुजा के नक्सलवाद को समाप्त किया। इससे विकास तेजी से आगे बढ़ा है। आज वही काम एक साल में पूरे बस्तर में हो रहा है। आपने पूरे आंकड़े सुने। सैकड़ों नक्सलियों को मारने का काम, उनको खत्म करने का काम हुआ। कई सरेंडर हो गए, कई जेल में हैं और इस तरह से आज पूरा अमन-चैन पूरे छत्तीसगढ़ में और बस्तर क्षेत्र में जो हो रहा है, तो विष्णु देव सरकार के सुशासन में सांय-सांय हो रहा है। हम घोटालों की बात करते थे। इनकी सरकार की बात करते थे। इनकी सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल में कोयला घोटाला, शराब घोटाला, सट्टा घोटाला एवं तमाम प्रकार के घोटाले किये।

सभापति महोदया :- आप कृपया अपने क्षेत्र की बात करें।

श्री प्रबोध मिंज :- सभापति महोदया, यह तमाम घोटाले इनकी कांग्रेस सरकार में होते थे। जब ई.डी. का छापा पड़ा, कार्रवाई हुई है तो आज वे जो सारे लोग जेल के अंदर हैं। प्रदेश के नौजवानों के साथ पी.एस.सी. जैसी परीक्षाओं में छलावा होता था। अच्छे-अच्छे पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती थी। उन्हें पी.एस.सी. में फेल कर दिया जाता था। आज उसका परिणाम है कि उसकी जांच में सारे लोग जेल में है। आज विष्णु देव साय जी की सरकार में हमारी पी.एस.सी. की जो परीक्षाएं हुई हैं, पूरे प्रदेश के अभिभावक उसकी दाद दे रहे हैं। इस पूरी परीक्षा के परिणामों को और उसके साथ जो इनकी सुव्यवस्था है, जो व्यवस्थित तरीके से परीक्षाएं हुईं, उससे सारे नौजवान संतुष्ट हैं और आने वाले समय में भी इसी तरह से बहुत अच्छे ढंग से परीक्षाएं होंगी, नियमों का पालन होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। आज विष्णु देव साय जी की सरकार में ग्रीन फील्ड में औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। मैं लगातार देख रहा था कि अब इसमें 12 हजार करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट की बात आयी है। सभापति महोदया, मैं एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे लुण्ड्रा विधान सभा क्षेत्र में इसी योजना के अंतर्गत ग्रीन एनर्जी का पॉवर प्लांट लगने की स्वीकृति हुई है और वहां 12000 मेगावॉट का पॉवर प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 6000 करोड़ रूपये का इनवेस्टमेंट होने जा रहा है। रामकुमार जी, यह 1 साल की उपलब्धि है। इस तरह से आपने लगातार 1 साल की चीजें देखी हैं। आने वाले समय में विष्णु देव साय जी की सरकार में इस पूरे सदन में हम सब लोगों को उपलब्धि

हासिल होने वाली है। अब नया छत्तीसगढ़ बनेगा। वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। उसी तरह से 2047 तक हमारा छत्तीसगढ़ भी विकसित राज्य की श्रेणी में आयेगा। आज उन जगहों पर जो 5 अत्यंत पिछड़ी जनजातियां हैं, उन पूरे क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जन-मन योजना के तहत लगातार काम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जन-मन योजना के माध्यम से वहां तक सड़कों का जाल पहुंच रहा है। वहां पर उन लोगों की तमाम चीजों का विकास हो रहा है।

सभापति महोदया :- कृपया जल्दी समाप्त करिये।

श्री प्रबोध मिंज :- सभापति महोदया, मैं 2 मिनट का समय और लूंगा। इसी तारतम्य में आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत जो हमारे जनजातीय क्षेत्रों की छोटी बसाहटें हैं, वहां भी आने वाले समय में केंद्र सरकार की नरेन्द्र मोदी जी की योजनाओं से विकास होने वाला है। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में चाहे नक्सलवाद को समाप्त करना हो, चाहे हमारे इस क्षेत्र की अधोसंरचना का विकास करना हो, चाहे क्षेत्र का विकास करना हो, विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यह झलक माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में आयी हैं। आज मैं उनके अभिभाषण का साधुवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद्। जय हिन्द। (मेजों की थपथपाहट)

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय सभापति महोदया, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी हमारे बहुत से विद्वान साथियों ने अभिभाषण के पैरा नंबर 5 में माननीय राज्यपाल जी ने जिन शब्दों का उल्लेख किया है, उसकी बातें की है कि अटल बिहारी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। यहां तक तो ठीक है। लेकिन उस समय छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में जिनका भी योगदान रहा, जिनकी सोच रही, ऐसे स्वर्गीय खूबचंद बघेल जी, स्वर्गीय बिसाहु दास महंत जी, स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर जी और स्वर्गीय पवन दीवान जी के नाम का भी उल्लेख होना चाहिए। यह भी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के स्वप्नदृष्टा थे।

समय:
5.44 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

जिन्होंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन छत्तीसगढ़ को बनाने में, छत्तीसगढ़ को संवारने में और छत्तीसगढ़ को सजाने में लगाया है। इनके भी नाम का उल्लेख इसमें होना चाहिए था। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कहा गया है कि कुछ साल की बाधा एवं कमजोर प्रगति के बाद यह विकास की प्रक्रिया पुन: तेज हुई तो क्या विगत 5 वर्षों में पूर्व सरकार ने कोई काम नहीं किया ? ऐसा करके इस अभिभाषण में माननीय राज्यपाल महोदय जी से गलत कथन करवाया गया है। इस अभिभाषण के पैरा 7 में का उल्लेख है कि नगरीय निकायों में अब नई निर्वाचित सरकार चुनी गई है। पूरे प्रदेश की जनता

यह जानती है कि नगरीय निकायों में किस तरह से निर्वाचन की प्रक्रिया हुई ? अधिकारियों के माध्यम से एक जीते हुए प्रत्याशी को दबावपूर्वक हरा दिया जाता है और मैं स्वयं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र के 4 वार्डों में यह संभव हो सकता है कि एक वार्ड में 91, दो वार्ड में 91, फिर एक वार्ड में 191, फिर उसके बाद एक वार्ड में 191 इस तरह से जीत का अन्तर था। नगरीय निकायों चुनाव में लगातार किसी वार्ड 191 का आंकड़ा मिल सकता है और वहां जीत का भी अंतर आता है तो 191 आता है। यह कैसे संभव हो सकता है ? यह जो धांधली नगरीय निकायों के चुनाव में हुई है, यह भी किसी से छुपा नहीं है। इस सदन में हमारे विद्वान साथीगण किसानों के लिए बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। वह यह भूल गये कि वह भी किसान परिवार से हैं। यदि आज आपने धान की कीमत 3100 रूपये देने का वायदा किया है तो अगर उसके पीछे कोई सोच है तो पूर्व की हमारी सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार ने 2500 रूपये समर्थन मूल्य देने का वायदा किया था और 2800 रूपये तक पहुंचाया था। तब आप धान की कीमत 3100 रूपये देने पर मजबूर हुए हैं। आप किसानों को 300 रूपये अतिरिक्त दे रहे हैं आप यह बताईये कि आपने इस राशि को कितना बढ़ाया ? आप 2800 रूपये के बाद 300 रूपये बढ़ाकर, अब 3100 रूपये धान की कीमत दे रहे हैं। यहां पर एक मुश्त राशि देने, पंचायतों के माध्यम से देने, नगदी देने और खरीदी व्यवस्था चालू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां धरातल पर कुछ नहीं है। अभी नगरीय निकाय चुनाव आया तो अचानक आपने चुनाव के समय दूसरी किश्त की राशि दी। यहां केवल बात करने से कुछ नहीं होता। हमें धरातल पर काम दिखना चाहिए। इस सरकार को अपने ही अधिकारियों पर भरोसा नहीं है। राजस्व विभाग के सारे कर्मचारी-अधिकारियों ने गिरदावरी की। जब खरीदी की बात आई तो उस खरीदी के समय ऐसे-ऐसे विभाग के कर्मचारी- अधिकारियों को लगा दिया गया जिसको किसी से कोई मतलब नहीं होता। उनके मोबाईल में एप्प डाऊनलोड कर दिया गया था वहां क्षेत्र में जाकर फोटो खिंचकर भेजिए कि वहां क्या हो रहा है ? उन निरीह लोगों से गिरदावरी की परिभाषा पूछिए तो उनको परिभाषा नहीं पता थी। आपने ऐसी परिस्थितियां निर्मित की कि वहां धान की खरीदी केन्द्रों, समितियों पर धान की खरीदी चल रही है, उसके बाद भी वहां आपको अपने कर्मचारी-अधिकारियों पर भरोसा नहीं है। आपने फिर दूसरी बार गिरदावरी करवायी। वहां पर लोग घर-घर जाकर, जांच कर रहे हैं कि आपके यहां पर कितना एकड़ खेत है आपके यहां धान की उपज कितनी है तो आपने यह परिस्थितियां निर्मित करवायी थीं। इस पर भी आपको जवाब देना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 'दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना' आरंभ की है। आपने केवल योजनाओं का नाम बदलने काम किया है। पूर्व में हमारी सरकार ने जो भूमिहीन थे, साल में उनको भी 7000 रूपये देने का वायदा किया था, हम उनको वह राशि दे रहे थे । आपने केवल योजनाओं का नाम बदलकर, लाभ देने का काम किया है। जब धान खरीदी के समय बड़ी-बड़ी बातें हुईं। वहां पर समितियों में कोई सुचारू रूप से संचालन नहीं हुआ। समाचार पत्रों और टेलिविजन के माध्यम

सभी में यह समाचार चला कि प्रदेश के किसान धान खरीदी केन्द्र में जाकर आन्दोलन कर रहे थे, उन्होंने वहां पर ताला लगाया था। मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगातार यह बातें आयीं। मैंने पिछले शीतकालीन सत्र में यह बातें रखी थीं कि धान खरीदी केन्द्रों में बारदानों की कमी है। वहां बारदानों के अभाव में हमारे किसान परेशान हो रहे हैं। वह जबरदस्ती जाकर, व्यापारियों से 35, 40 और 45 रूपये में बारदाना ले रहे हैं। वहां पर ऐसी परिस्थितियां निर्मित थीं। उनकी मजबूरी थी उनको अपना धान बेचना था, लेकिन आज आप देखेंगे कि आप केवल बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं वहां पर सुचारू रूप से समुचित व्यवस्था की गई है, लेकिन आज भी आप जाकर उन समितियों या धान खरीदी केन्द्रों में देखेंगे तो लगभग 50 प्रतिशत धान के उठाव नहीं हुए हैं। यदि आप मेरे साथ देखने चलना चाहें तो मेरे विधान सभा क्षेत्र के जिस खरीदी केन्द्र में बोलिए, मैं वहां पर ले जाने के लिए तैयार हूँ। आप यह बताईये कि उसकी सूखत का भार कौन सहेगा ? इस बार समितियां इतने ज्यादा घाटे में जाने वाली है कि उसकी आपूर्ति करना संभव नहीं होगा। यहां पर केवल बातें करने से कुछ नहीं होता है। यदि आपने इसमें किसानों की आय दुगुनी करने की बात की है। आपने इसमें किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की बातें कहीं हैं, आपने किसानों को समृद्ध करने की बाते कही हैं तो धरातल पर काम दिखना चाहिए। महतारी वंदन योजना की राशि की बात आई, बहुत से माननीय सदस्यों ने उसमें बात की, मैं उस पर बात नहीं करना चाहूंगा। लेकिन उनका क्या दोष है जिनको पूर्व में वृद्धावस्था पेंशन के नाम से 500 रुपये मिल रहा था, उनके खाते में 1000 रुपये जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए? साल भर से जिन नई बेटी, बहुओं की शादी हुई है, क्या उनका नाम नहीं जुड़ना चाहिए? लेकिन आपका पोर्टल बंद है। यह पोर्टल कब चालू होगा? ताकि जो नये पात्र हितग्राही हैं, उनकी भी यह राशि मिलनी चाहिए। रेडी टू ईट के संबंध में बातें हुईं, चरणबद्ध तरीके से हम यह काम समूह की महिलाओं को दे रहे हैं, यह बता दें कि कहां पर चालू हुआ और कहां पर दे रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, केवल कागज पर लिख देने से कुछ नहीं होता। यदि आप इसे धरातल पर कार्यरूप में परिणित करें तब इन सारी योजनाओं का काम हो सकता है। युवाओं को नौकरी देने की बात आई। पिछले सदन में यहीं पर माननीय मंत्री जी के माध्यम से घोषणा हुई थी कि 34 हजार शिक्षकों की भर्ती करेंगे। लेकिन आज सवा साल हो गये हैं, जो भर्ती हुए थे, किसी अड़चन को सामने रखकर उनको निकाल दिया गया। आखिर भर्ती करने वाले कौन थे? सरकार में वही कर्मचारी, अधिकारी थे। क्या उस समय उनको ख्याल नहीं आया कि इसमें कानूनी अड़चनें आ सकती थीं? उनको भर्ती होने के बाद दो साल काम करने के बाद निकाला गया तो फिर उन युवाओं के भविष्य का क्या होगा? जो 3 हजार बी.एड. शिक्षक काम कर रहे थे, वह आज सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जिन युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के रूप में 2500 रुपये महीने मिलते थे, नौकरी का फार्म भरने के लिए, अपने दैनिक जीवन की दिनचर्या का काम करने के लिए उनको पैसे की जरूरत होती थी, आज उनकी जेब खाली है। आज वह युवा किसी

अपराध में, अनैतिक काम में लिप्त हो रहे हैं। उन युवाओं की सुध लेने वाला और सोचने वाला कोई नहीं है। पहले वेकेंसी के लिए जो आवेदन निकलते थे, हमारी सरकार ने उसे नि:शुल्क किया था। पहले आवेदन करने के लिए पैसे नहीं लगते थे, एक की जगह 7-8 जगह आवेदन करते थे। लेकिन अब फार्म भरने के लिए पैसे देना पड़ता है, उनके पास फार्म भरने के लिए पैसे नहीं हैं। इसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा और चिंतन करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, कुंवर सिंह जी, समाप्त करिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो चालू किया हूं, दो मिनट ही हुआ है। स्व-सहायता समूह को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह बातें आ रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि पूर्व में गौठान के माध्यम से पूरे प्रदेश में ऐसे सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों समूह काम करते थे। आज उन समूहों के ऊपर वित्तीय संकट की समस्या आ गई है, क्योंकि उनके सारे काम बंद हो गये हैं। जो रोजगारमूलक काम गौठान के माध्यम से होते थे, चाहे वह कुक्कुट पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन करते थे, साग-भाजी का उत्पादन करते थे, अन्य चीजों को करते थे। लेकिन आज काम के अभाव में उनकी सारी चीजें बंद हो चुकी हैं, सारे व्यवसाय बंद हो चुके हैं। रीपा के माध्यम से, जिसका उल्लेख हर बार होता है रीपा के माध्यम से अपनी बहनें पापड़, बड़ी बनाने का, कपड़ा सिलाई करने का, पेंट बनाने का, अन्य चीजों को करने का काम कर रही थीं, वह सारे काम बंद पड़े हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के संबंध में बात आई कि सरकार 18 स्थानीय भाषाओं में बच्चों को शिक्षा दे रही है। हम तो अभी स्कूलों में जाकर देखते हैं तो अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत भाषा में पढ़ाई हो रही है। इसके छोड़ अगर नवोदय विद्यालय में चले गये तो एक-दो भाषाओं में और पढ़ाई हो रही है, लेकिन 18 भाषाओं में कहां पर पढ़ाया जा रहा है, इसके बारे में मुझे समझ में नहीं आता है। ऐसा असत्य कथन माननीय राज्यपाल महोदय से पढ़ाया गया है। इस पर भी विचार होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, स्वामी आत्मानंद स्कूल में बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बातें हुईं। अब उसमें एक टेग पीएमश्री लगा दिया जा रहा है। आखिर क्या हो रहा है? स्वामी आत्मानंद के सामने में आपने पीएमश्री लगा दिया है। ठीक है, आप उन्नयन करें, व्यवस्था दें, सुविधायें दें, सब चाहते हैं। लेकिन अभी विगत 5 से 6 महीने तक न उनके पास चाक, डस्टर लेने के लिए पैसे हैं। अभी 6 महीने से वहां पर कलेक्टर दर पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको तनख्वाह देने तक के लिए पैसे नहीं हैं। मेरे बालोद जिला की बात बता रहा हूं, मैं बाकी जिले की बात नहीं बोल सकता। लेकिन मेरे पास सारे लोग आये थे, इसलिए मैं आपसे यह बात कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिव्यांगजन की बात आई । सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर इनको हम लोग सुविधाएं दे रहे हैं, बढ़िया लिखा है, मैं उसको पढ़ रहा था लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय जी जब आप मुख्यमंत्री थे, बालोद जिला का एकमात्र दिव्यांग स्कूल कचांदूर में संचालित है । मैंने पिछले बजट सत्र में भी आग्रह किया था, अनुपूरक के समय भी आग्रह किया था कि

जोड़ दिया जाए, यह वैकल्पिक व्यवस्था के तहत माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से संचालित हो रहा है, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से थोड़ा-बहुत अंशदान लेकर संचालित है लेकिन यदि आप इसका budget में प्रावधान रखते हैं तो नियमित रूप से यह चल पाएगा और जितने बच्चे वहां दिव्यांग हैं जिसके बारे में हम लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, जिनको ऊंची उड़ान देने की हम लोग कल्पना करते हैं और आज उन बच्चों के पास कोई सुविधा नहीं है, कोई संसाधन नहीं है क्योंकि शासन ने आज तक उनको budget में नियमित रूप से संचालन करने का कोई प्रावधान नहीं रखा है । आपके समय वह संचालित था, वह बीच में बंद हो गया था । हमारी सरकार के समय हमने उसे चालू करवाया था और आज निरंतर चल रहा है लेकिन उसको यदि budget में प्रावधान लाकर चालू करवा दिया जाए तो निश्चित ही उनका लाभ उन बच्चों को मिल सकता है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, खेल के संबंध में बात हुई थी । मैं एक-बार फिर से आपसे आग्रह करना चाहूंगा और माननीय खेल मंत्री जी भी बैठे हैं कि ग्रामीण स्तर की जो प्रतिभाएं हैं, जो सुविधाएं और संसाधन के अभाव में भी अपनी प्रतिभा, अपनी कला का जौहर दिखाते हैं । राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक खेलते हैं लेकिन जब सुविधाएं नहीं हो पातीं, संसाधन नहीं हो पाते हैं और पर्याप्त पोषक तत्व या डाईट नहीं मिल पाती तो वह आगे तक नहीं जा पाते हैं । मैंने अपने स्तर पर कोशिश की है कि मेरे विधानसभा के जितने बच्चे हैं यहां तक कि डाईट के पैसे का खर्च भी मैं वहन करता हूं ताकि वह बच्चे राष्ट्रीय स्तर तक खेल सकें और मुझे गर्व होता है कि जिन बच्चों को मैंने संरक्षण दिया है उसमें से छह बच्चे भी राष्ट्रीय स्तर तक खेले और दो बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर खेल में जाने को तैयार हैं तो ऐसे बच्चे, ऐसी प्रतिभा जो ग्रामीण स्तर पर हैं, उन बच्चों के लिए हम एक योजना अलग से बनाएं, केवल केंद्र तक सीमित न रहें मतलब एक center बनाकर उसको विधिवत रूप से प्रशिक्षण दें ताकि बच्चों की प्रतिभा निखर कर आए और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम हो, ऐसा मैं चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, योजना की बातें आती हैं । स्कूल जतन योजना पर जो काम पूर्व की सरकार में हुआ था, आज भी होना चाहिए वह स्कूल व्यक्तिगत किसी का नहीं है, वह स्कूल एक मंदिर है जहां से आप भी और हम भी सब पढ़कर निकले हैं । उन स्कूलों के प्रति सबकी एक सोच होनी चाहिए, पार्टी से हटकर, राजनीति से हटकर कि उन स्कूलों का संधारण कैसे करें, उन स्कूलों में कैसी सुविधा दें ? जो पर्याप्त शिक्षकों की कमी है उन शिक्षकों की कमी को पर्याप्त रूप से पूरा करें लेकिन आपने युक्ति-युक्तिकरण के नाम से जो पद को खत्म करने का एक बड़ा खेल किया है लेकिन फिर आप नयी vacancy कैसे निकाल पाएंगे ? जितने बच्चों ने आज बी.एड. किया है, डी.एड. किया है, अन्य योग्यता लेकर बैठे हैं उनका फिर क्या होगा तो इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अस्पताल की बुनियादी सुविधाओं के बारे में भी एक बात कहना

चाहूंगा कि उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर Higher health center तक चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, Community health center हो या फिर खंड के चिकित्सा कार्य हो, पूरा कार्यालय का सेटअप हो, पूरा जिला का हो या फिर प्रदेश के हों, जो स्थिति आज निर्मित है, अचानक जब कोई दुर्घटना घटती है, accident होता है तो हम लोग सीधा पास के नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाते हैं । वहां पर वेंटिलेशन के अभाव में या त्वरित चिकित्सा के अभाव में ऐसा नहीं हो पाता है । जब एक खतरनाक सड़क दुर्घटना होती है, पैर के नीचे से अगर गाड़ी चली जाती है या सीने से गाड़ी चली जाती है उसकी सांस चलती रहती है उस समय हमारे पास यह नहीं रहता है कि हम उसको वेंटिलेशन दे पायें, उसको एक higher center तक उसकी जान बचाकर ले जाएं तो यह व्यवस्था नहीं होती है तो कम से कम पी.एच.सी. हेल्थ सेंटर तक यह व्यवस्था अगर हो जाए तो निश्चित ही सी.एच.सी. और पी.एच.सी. स्तर तक तो उन लोगों को दुर्घटना से बचाया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करिये । आपको 15 मिनट हो गये हैं ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें और कहूंगा । मेरी सरकार वर्तमान Climate change में बड़ी चुनौतियों को समझती है यह बातें...।

अध्यक्ष महोदय :- आप Climate change छोड़ दो न । आप Climate change को महंत जी के ऊपर छोड़ दो न, बड़ा विषय है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा बोल देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- कुछ महंत जी के लिए छोड़ोगे तभी तो ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है, मैं छोड़ देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप अंतर्राष्ट्रीय विषय इनके ऊपर छोड़ दीजिये ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय हमारे नेता जी इसमें करेंगे । मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हम लोग अभी कुंभ के बारे में, अयोध्या के बारे में, राम मंदिर के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, राम आपके नहीं हैं, मेरे नहीं हैं, हम सबके हैं, किसी व्यक्तिगत के नहीं हैं और मैं जिस वर्ग, जिस समुदाय से आता हूं, मेरे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं । निषाद समाज के आराध्य ही राम हैं । (मेजों की थपथपाहट) तो हमारे बारे में कहने से कोई बात नहीं है ।

समय :
6.00 बजे

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम कितना अपने बारे में सोचते हैं, वह कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हम राम के बारे में कितना सोचते हैं, ये महत्वपूर्ण होना चाहिए। राम के प्रति हमारी आस्था कितनी है? छत्तीसगढ़ की धरा, छत्तीसगढ़ की भूमि, कौशल्या माता की जन्मभूमि प्रभु श्री राम चंद्र जी का ननिहाल गर्व से कहते हैं, जिसके सपनों को जिसकी जगह को हमने चिन्हांकित कर राम वन गमन

परिपथ के माध्यम से उसको विस्तार करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में भांचा का दर्जा मिलता है, आज प्रभु श्री रामचंद्र जी को आदर्श मानकर हम भांचा में राम देखते हैं। उन राम के प्रति एक आस्था, एक अटूट लगाव छत्तीसगढ़ वासियों की है और छत्तीसगढ़ की आस्था के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। केवल विरोध के रूप में कहना कि यहां के लोग वहां नहीं गए, वहां के लोग यहां नहीं गए। सबकी अपनी-अपनी परिस्थितियां हो सकती हैं, मजबूरी हो सकती है। क्या अभी जाएंगे तभी पाप धुल सकते हैं। सालों से लोग वहां जाते हैं। चाहे वह बनारस में हो, चाहे इलाहाबाद के संगम में हो, उनके पाप उस समय नहीं धुलते थे ? क्या 144 साल बाद ये महाकुंभ आया? तभी उनके पाप धुलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लोग यदि आस्था के साथ आज भी जा रहे हैं, कल भी जा रहे हैं, 1 साल बाद जाएं, 2 साल बाद जाएं तो हमारी आस्था है, वह हमारा विश्वास है। राम के बारे में कहना, मैं तो यही बस कहना चाहूंगा कि

तन में राम, मन में राम,
तन में राम, मन में राम
रोम, रोम के नाताराम,
राम बसे, सबके हृदय,
सबके भाग्य विधाता राम,
राम रहे रचना निस्बासर,
पौंडी पोथी पंडित, भांचा राम
सब बर तो भगवान मगर,
छत्तीसगढ़ बर भांचा राम,
छत्तीसगढ़ बर भांचा राम।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं अपने क्षेत्र की कुछ मांगों पर भी कटौती के रूप में जो प्रस्ताव दिया, उसमें भी बात करना चाहूंगा। मैंने लगभग 42 कटौती दिया है, लेकिन यदि उसमें प्रदेश के रूप में भी और क्षेत्र के रूप में भी देखें तो प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन शासकीय तकनीकी पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रारंभ हो जाए, इसका कोई उल्लेख नहीं है। पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने का भी कोई उल्लेख नहीं है। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का कोई उल्लेख नहीं है। नवीन महाविद्यालय को प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का कोई उल्लेख नहीं है। बढ़ते साइबर अपराध को भी नियंत्रित करने का कोई उल्लेख नहीं है। प्रदेश में जिस हिसाब से अवैध शराब की बिक्री हो रही है, उसको भी किस तरीके से हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं, उसका भी कोई कोई उल्लेख नहीं है। भवनविहीन शालाओं को भी बनाने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है। राज्य के क्षेत्रों में अस्पतालों

का भी उल्लेख नहीं है। पुल-पुलिया निर्माण का भी कोई उल्लेख नहीं है। प्रदेश में मादक पदार्थ जो अन्य राज्यों से आते हैं, उनके भी रोकथाम के प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं है। सड़क दुर्घटना जिनके बारे में मैंने बात की। सड़क दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं, उस सड़क दुर्घटना को हम प्रभावी रूप से कैसे रोक सकते हैं, इस पर कैसे नियंत्रण किया जाए, उसका भी कोई उल्लेख नहीं है। प्रदेश में वनों की अवैध कटाई रोकने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है। प्रदेश में गौण खनिज के अवैध उत्खनन पर नियंत्रण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही प्रदेश के B.Ed योग्यताधारी शिक्षकों को जिनको आपने निकाला, उनको समायोजित करने का भी कोई उल्लेख नहीं है। प्रदेश के महाविद्यालयों में रिक्त पड़े सहायक प्राध्यापकों की भर्ती की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है..।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती चातुरी नंद। चलिए, हो गया।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- प्रदेश में गौ संरक्षण की जो बात आपने कही है..।

अध्यक्ष महोदय :- वह प्रिंटेड है, सबको मिल जाता है। चलिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- लेकिन आज उन गौ संरक्षण के संबंध में बात करने की कोई योजना का उल्लेख नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, श्रीमती चातुरी नंद।

श्रीमती चातुरी नंद (सरायपाली) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं नवा विधायक हव। पहली बार जीत के आए हव अउ पहली बार भाषण देवत हव, आपके संरक्षण चाहथव।

अध्यक्ष महोदय :- पहली बार नहीं, सवा साल होगे।

श्रीमती चातुरी नंद :- हां, पहली बार भाषण देवथव।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, कई भाषण दे डारे हस, चलि शुरू कर।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हा माननीय राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण के विरोध में विपक्ष में बोले बर खड़े होये हव, अभिभाषण के पैराग्राफ 38 मा, ये लिखाय हे कि 18 लाख आवास के स्वीकृति और हितग्राही मन ला घर के चाबी सौंपे जाये के उल्लेख हावय। माननीय पंचायत मंत्री जी से मैं पूछना चाहथव कि कि 1 साल में कतका हितग्राही मन ला चाबी दिए गए हावे? ये जरूर बताहिया। मैं बताना चाहथव कि कांग्रेस सरकार के समय निर्माणाधीन आवास के जो अंतिम किश्त रिहिस ओला देकर आप मन फोटो खींचा ले हौ । आप मन के द्वारा जारी प्रथम किश्त के कतना ठन आवास पूर्ण हो गे हावय अउ कतका हितग्राही मन ला आप मन चाबी दे डारे हावव, ये भी जानना चाहत हौं । कम से कम मोर विधान सभा क्षेत्र का कतना हितग्राही मन ला आवास मिल गे हावय, यह मैं जानना चाहत हौं । अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण के पैराग्राफ 26 में उल्लेख हवय कि आपके सरकार छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधन के उचित दोहन बर नावा नीति लागू करे हावय । तो ये

नावा नीति का हावय, एकाध प्वाइंट त बता दे रतौ ? मैं कहना चाहत हौं कि नावा नीति का हावय एकाध प्वाइंट त बता दे रतौ । आपके सरकार रेत जैसे गौण खनिज के खदान के नीलामी तक नइ कर पाए हे । आपके सरकार के द्वारा अवैध रेत के खनन के खुले छूट दे गे हे । जेखर से बालू के आने वाला रायल्टी के राजस्व मुद्रा सरकार के खाता मा जाना चाहिए लेकिन वह राजस्व मुद्रा सरकार के खाता मा नइ जात हे, बहुत बड़ा विडम्बना के बात हे । ये सोचनीय विषय हे कि जो राजस्व मुद्रा सरकार के खाता मा जाना चाहिए वो कोनो और के हाथ में जात हे, बहुत बड़ा विडम्बना के बात हे । मोर क्षेत्र के बताना चाहत हौं महासमुंद जिला मा सांकरा मा जोंक नदी हावय, जोंक नदी मा रेत माफिया मन रेत के मेन्युवली लोडिंग के आदेश रथे, ओखर धज्जी उड़ाकर एमन पोकलेन गाड़के रेत उत्खनन करत हावय, जो कि अवैध हावय ।

अध्यक्ष महोदय, पैराग्राफ 31 मा उल्लेख आवय कि आपके सरकार हा शासकीय विभाग मा 9 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया चालू कर दे हावय । मैं कहना चाहत हौं कि राजनांदगांव के पुलिस भर्ती प्रक्रिया काकरो से अछूता नइ हे, भ्रष्टाचार और अनियमितता के चलते मोर क्षेत्र के एक आरक्षक फांसी लगा ले रहिस हे । मोर विधान सभा क्षेत्र के एक छोटे से गांव सूखापाली के आरक्षक, भर्ती प्रक्रिया के शिकार होइस और वो फांसी लगाके आत्महत्या कर लिस । एखर अलावा 2024 मा जो पटवारी भर्ती अउ आर.आई. के परीक्षा होए रहिस । आप सबला याद तो होही। एखर जांच भी आप सब करत हावव । आपके सरकार मा एखर जांच होवत हे, जिसमें बिना परीक्षा दिए व्यक्ति आर. आई. घलो बन जात हे । ए बहुत बड़े सोचनीय विषय हे । एखर अलावा जब हमारी इही विधान सभा सत्र मा पिछले समय हमर शिक्षा मंत्री रहिन हे, अउ शिक्षा मंत्री के द्वारा ए घोषणा करे गे रिहिस हे कि 33000 शिक्षकों के भर्ती करे जाही । न तो 33000 शिक्षकों के भर्ती होइस, बल्कि जो 3000 बी.एड.धारी शिक्षक साथी मन ला रोजगार से निकाल दिए गिस । बेरोजगार मन ला रोजगार कहां उपलब्ध होवत हे, ये बताए के कष्ट करिहौ ?

पैराग्राफ 37 मा उज्जवला योजना के उल्लेख हावय । मैं पूरा प्रदेश के बात नइ करत हौं, मैं केवल एक जिला के उज्जवला हितग्राही के गैस रि-फिलिंग आंकड़ा मंगवा लो । योजना के उपयोगिता पता चल जाही। हमर पूर्व प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के सरकार जब रिहिस तो वो समय गैस सिलेंडर ला लेकर सड़क मा बैठने वाला मन आज कहां हावय, कहां लुका गे हे ओमन ? अभी गैस के दाम 900 से 1000 चलत हावय । कहां लुका गे हे जो गैस सिलेंडर ला लेके सड़क मा बैठे रहिस । अध्यक्ष महोदय, मैं एक दू लाईन कहना चाहूं :-

पान पतई झरथे त उठाथे कोनो-कोनो
वादा तो सब करथे पर निभाथे कोनो-कोनो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पैराग्राफ 38 में जल जीवन मिशन के तहत् 40 लाख परिवार ला जल आपूर्ति के उल्लेख करे गे हे। मैं बताना चाहत हौं कि आपके जल जीवन मिशन डबल इंजन के सरकार में फेल हे। मैं मोर क्षेत्र के बार करना चाहत हौं, मोर क्षेत्र में 270 ठन टंकी प्रत्येक टंकी 1-1 करोड़ से ज्यादा के लागत से बने हावए लेकिन आज तक न ओ टंकी में पानी आईस, न बोर उत्खनन होईए। ऐखर से क्षेत्र के जनता पानी बर परेशान हे। मोर क्षेत्र ड्राई एरिया के अंतर्गत आथे, ड्राई क्षेत्र हे, पानी के हाहाकार अभी से मच चुके हे। लेकिन ये 270 टंकी में न पाई आईस न बोर उत्खनन पूरा होए हे। मैं कहना चाहत हौं, कई टंकी तो अइसे बने हावए जो नाममात्र बर बने हे। पुराना टंकी ला कलर रंगरोगन पोत दिए गे हे और पुराना टंकी ला एमा जोड़ दे गे हे। अधिकारी मन सुनत हावए, आप मन ऐखर तरफ जरूर संज्ञान लेवव और कार्रवाई जरूर करिहा।

श्री रामकुमार यादव :- मोर दीदी कल्ला-कल्ला के गोठियात हे देखत हव।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पैराग्राफ नंबर 32 मा आप कहिथो की बच्चा मन ला 18 भाषा में शिक्षा देवत हव। त का 19वां भाषा के रूप में हमर छत्तीसगढ़ी भाखा नई हो सकत हे। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाखा मा शिक्षा दीक्षा काबर नइ होवत हे ये भी सोचे के विषय हावए। पिछला एक साल मा कतका उद्योग स्थापित करे हा, ओखर नाम पता तो बता दे रता। हमर बड़े भाई धर्मजीत सिंह कहत रिहिन हे कि अनुसूचित जाति, जनजाति के किसान मन ला फ्री मा बिजली उपलब्ध कराए के आदेश हावए। ये आदेश वाकई में हावए। हमर तात्कालिक मुख्यमंत्री परम सम्माननीय रमन सिंह जी के द्वारा दिये गे रिहिस हे लेकिन बिजली विभाग हा ओ प्रमाण पत्र के धज्जियां उड़ा के उही किसान मन ला 60-60, 70 हजार के बिजली बिल के राशि धमाय हे संगवारी हो। ये बहुत बड़े विडंबना के बात ए। हमर बड़े भाई कहत रिहिन हे, कांग्रेस में विश्वसनीयता के संकट आ गे हे, भाई, विश्वसनीयता के संकट कांग्रेस में नई आए हे, बल्कि बी.जे.पी. के सरकार में विश्वसनीयता के संकट आए हे। तभे तो आप मन नगरीय निकाय चुनाव मा कांग्रेस प्रत्याशी मन ला बलपूर्वक डरा धमका के ओमन के फार्म ला वापस लेबर मजबूर करे हो। ऐखर बर मे कहना चाहत हौं।

दिल से सच्चा रेहेन, अंतश ले साफ रेहेन।
तेखरे सेती, खूरापाती दिमाग वाले मन से हार गेन।।

अध्यक्ष महोदय, आज भी लोग पलायन करत हे, किसान आज भी दुखी हे। किसान संतोषजनक जिंदगी जियत हे, ये आपके कहना हे लेकिन किसान आज भी त्रस्त हे, किसान ला अपन धान के पईसा ले बर लाईन में लगे बर लगत हे। रात के 4 बजे आ के लाईन में लगत हे तभो ले संझा के 7 बजे तक ओला पईसा नई मिलत हे तो कइसे किसान संतुष्ट हावए, ये मैं जानना चाहत हौं। लोगन कथे बेटी ला मारिहा त बहू कहां से लानिहा, मैं कईथव कि किसान ला मारिहा तो रोटी कहां से लानिहा। संगवाही हो, आज हमन जो भी हन, किसान मन के बदौलत हन। किसान मन के वजह से हमन ला रोटी मिलत हे

और अगर किसान प्रताड़ित हे तो सोच सकत हव आगे का हो सकत हे। प्रदेश में बढ़ते हुए सड़क दुर्घटना ला रोके बर कोनो उल्लेख नई होए हे। साथ ही बैंकिंग सुविधा के कोनो उल्लेख नहीं हो पा हे। राज्य में फर्जी चिटफंड कंपनी अउ शेयर मार्केट के नाम पर आम जनता के गाढ़ी कमाई ला लूटने वाला मन के ऊपर ठोस कार्रवाई करे बर कोनो रणनीति घलो नई बनाए गेहे। साथ ही राज्य में बढ़ते साइबर क्राइम ला रोके बर भी कोनो प्रकार के उल्लेख नहीं होए हे अउ राज्य में नवीन रोजगार सृजित करे बर कोनो प्रकार के उल्लेख नहीं करे गेहे। खेल के विषय में उल्लेख करे गेहे कि खेल ला हमन बढ़ात हन। लेकिन अगर आप खेल के क्षेत्र मा उन्नति चाहत हव अउ खेल ला बढ़ाना चाहत हो तो नवा खेल स्टेडियम निर्माण के भी कोनो उल्लेख नहीं हे। माननीय सदस्यगण मन, ये बहुत सारा कारण हवे। बस मैं अतका कह के अपन भाषण ला विराम देवत हो। मैं आप सब ला पुन: प्रणाम करत हो, जोहार करत हो। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 2025 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(सायं 6 बजकर 16 मिनट पर विधान सभा शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 2025 (फाल्गुन 9, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छ.ग.)
दिनांक : 27 फरवरी, 2025